

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

23 मार्च, 1979

खंड 1 अंक 15

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भुक्तवार 23 मार्च 1979

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(15)1
अध्यक्ष द्वारा निरूपण	
प्र नों के उत्तरों की ज्यादा प्रतियां सप्लाई करने सम्बन्धी	(15)24
तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(15)25
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकि प्र नों के लिखित उत्तर	(15)28
सचिव द्वारा घोशणा	(15)43
ध्यानाकर्षण सूचना—	
जिला करनाल में भाराब के नये ठेकों की नीलामी सम्बन्धी	(15)43
अध्यक्ष द्वारा घोशणा	
खालों को पक्का करने के बारे में ध्यानाकर्षण सुचना को वापिस लेने सम्बन्धी	(15)44

वक्तव्य:—	
लोक निर्माण मंत्री द्वारा ने नल हाईवेज पर हो रही गम्भीर दुर्घटनाओं सम्बन्धी	(15)44
औचित्य प्र न—	
ग्रहण की गई ध्यानाकर्षण सूचना को वापिस लेने सम्बन्धी	(15)47
वर्ष 1978—79 के लिये सरकारी आ वासनों के बारे मे समिति की दसवीं रिपोर्ट पे ा करना।	(15)48
सरकारी प्रस्ताव—	
परिवार कल्याण उपायों द्वारा जनसंख्या को सीमित रखने सम्बन्धी	(15)49
वर्ष 1979—80 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(15)62
बैठक का समय बढ़ाना	(15)75
वर्ष 1979—80 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(15)75
बैठक का समय बढ़ाना	(15)89

वर्ष 1979-80 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(15)89
बैठक का समय बढ़ाना	(15)92
वर्ष 1979-80 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(15)93

हरियाणा विधान सभा

भुक्तवार 23 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़, में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मँबर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Revision of Pay Scales of Work Charged Employees

***1174. Shri Mange Ram Gupta:** Will the Minister for Public works be pleased to state-

(a) the names of categories of work charged employees of the P.W.D. (Public Health) whose pay scales were revised in 1969 or subsequently together with the old and revised pay-scales;

(b) whether it is a fact that there are some categories of work charged employees and regular employees who do the same job but their posts carry different pay scales;

(c) if so, the pay scales for regular and work charged employees in each category be laid on the Table of the House; and

(d) whether the Government proposes to remove this discrimination in the pay scales?

Public Works Minister (Shri Lachhman Singh):

(a) Pay scales of none of the categories of work charged employees of the P.W.D. (Public Health) were revised either in 1969 or subsequently.

(b) Yes, Sir.

(c) A list (statement) showing in each category, the pay scales of regular and work charged employees who do the same job is laid on the Table of the House.

(d) The matter is under consideration.

Statement

S.N.	Category of Post	Pay scale of regular employees	Pay scale of work-charged employees doing the same job
1	2	3	4
1	Heavy duty foreman	250-15-400/20-500	210-10-300
2	Foreman (Mech.)/(Elect.)	200-10-280/15-430/20-450	150-5-225
3	Asstt. Foreman (Mech.)/(Elect.)	200-10-280/15-430/20-450	150-5-225

4	Chargeman (Misc.)	140-6-170/8-210/10-300	100-3-130
5	Chargeman(Mech.)	140-6-170/8-210/10-300	100-3-130
6	Chargeman(Elect.)	140-6-170/8-210/10-300	100-3-130
7	Chargeman(Civil)	140-6-170/8-210/10-300	100-3-130
8	Plumber Grade I	160-10-180/15-400	125-5-175
9	Plumber Grade II	120-5-160/6-190/8-230/10-250	88-3-118
10	Mason	120-5-160/6-190/8-230/10-250	88-3-118
11	Painter	120-5-160/6-190/8-230/10-250	88-3-118
12	Vehicle Driver	110-4-130/5-180	90-3-120
13	Work Munshi	80-2-90/3-120	44½-1½-59½
14	Work Mistri	110-4-130/5-160/5-225	50-3-80/4-88
15	Bricklayer	160-10-280/15-400	125-5-175
16	Mason-cum-carpenter	160-10-280/15-400	125-5-175
17	Fitter Grade-I	160-10-280/15-400	125-5-175

18	Fitter Grade-II	120-5-160/6-190/8- 230/10-250	88-3-118
19	Strata Observer	110-4-130/5-160/5-225	50-3-80
20	Store Keeper	110-4-130/5-160/5-225	50-3-80
21	Laboratory Assistant	110-4-130/5-160/5-225	50-3-80
22	Store Munshi	110-4-130/5-160/5-225	50-3-80
23	Diesel Mech.	110-4-130/5-160/5-225	60-5-125
24	Well Borer	140-6-170/8-210/10- 300	90-5-150
25	Turner	120-5-160/6-190/8- 230/10-250	60-3-90
26	Electrician	120-5-160/6-190/8- 230/10-250	60-3-90
27	Jack Hammer Driller	120-5-160/6-190/8- 230/10-250	60-5-120
28	Work Inspector	120-5-160/6-190/8- 230/10-250	60-4-80/5- 120
29	Store Coolie	75-2-85/2-95	32-1-37
30	Oil Man	75-2-85/2-95	32-1-37
31	Store Attendent	75-2-85/2-95	32-1-37
32	Wlder	110-4-130/5-160/5-225	60-5-75

33	Petrol Man	75-2-85/2-95	32-1-37
34	Mate	75-2-85/2-95	35-1-45
35	Beldar	75-2-85/3-95	30-½-35
36	Skilled Coolie	75-2-85/3-95	30-½-35
37	Mali	75-2-85/3-95	30-½-35
38	Fitter Coolie	75-2-85/3-95	30-½-35
39	Gate Keeper	75-2-85/3-95	30-½-35
40	Sewerman	75-2-85/3-95+Rs.15/-as Spl. pay	30-½-35
41	Helper	75-2-85/3-95	30-½-35
42	Chowkidar	75-2-85/3-95	30-½-35
43	Truck Cleaner	75-2-85/3-95	30-½-35
44	Sweeper	75-2-85/3-95+Rs.15/-as Spl. pay	30-½-35
45	Fitter Attendant	75-2-85/3-95	30-½-35
46	Pump Driver	110-4-130/5-160/5-180	90-3-120
47	Asstt. Pump Driver	80-2-90/3-120	50-2-60/3-90
48	Air Conditioning Operator	110-4-130/5-160/5-180	90-3-120
49	Meter Reader	80-2-90/3-120	50-2-60/3-90

50	Chemist	350-25-500/30-590/30-860/35-900	250-25-500/25-750
51	Water Works Supdt.	350-25-500/30-590/30-860/35-900	250-25-500/25-750
52	Keyman	70-2-80/3-95+Rs.15/-as Spl. pay	30-½-35
53	Air Conditioning Foreman	200-10-280/15-430/20-450	150-5-225
54	Mali-cum-chowkidar	75-2-85/3-95	37½-1-42½
55	White washer	75-2-85/3-95	30-½-35
56	Oilman-cum-chowkidar	75-2-85/3-95	32-1-37
57	Drilling Foreman	200-10-280/15-430/20-450	150-5-225

श्री मांगेराम गुप्ता: स्पीकर साहब मेरे सवाल के पार्ट(बी) के जवाब में मंत्री महोदय ने 'जी हां' कहा है और पार्ट (सी) के जवाब में ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी है। सूची के मुताबिक स्पीकर साहब रैगूलर ऐम्पलाइज और कर्मचार्जड ऐम्पलाइज के स्केल में फर्क है जबकि उनका काम एक है। क्या मंत्री जी बताने की मृपा करेंगे कि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको बराबर का स्केल देकर कितने दिनों में दूर कर दिया जाएगा?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, बजट स्पीच के अन्दर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने माना है कि इस किस्म के जो 25 हजार वर्कचार्ज्ड मुलाजिम है उनके पे-स्केल परमानेन्ट और टैम्परेरी मुलाजिमों के बराबर कर दिये जायेंगे। गुप्ता साहब कृपया बजट स्पीच पढ ले। (विधान)आप कहें तो मैं रैलेवैन्ट पो न्न पढ देता हूं। (विधान) गवर्नमेंट ने इन-प्रिंसिपल यह मान लिया है (विधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों को पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि इस बात को ऐगजामिन कर रहे है और वर्क चार्ज्ड ऐम्पलाइज को रैगूलर ऐम्पलाइज के बाराबर लाने के कोर्ण कर रहे है।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, यह काफी हअम सवाल हैं जब मत्रियों की बराबर पे है , एच0सी0एम0 ओर आई0ए0एस0 अफसरों की बराबर पे है तो इन एक जैसा काम करने वाले मुलाजिमों की भी बराबर पे होनी चाहिये। रोजना यहां डैपुटे न्न आते रहेते है। कभी ड्राइवरों का डैपुटे न्न आता है और कहता है कि सैक्रेटैरिएट वालों की तनख्वाह ज्यादा है ओर हमारी कम है। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से पूछनार चाहता हूं कि इन एक ही कैटेगरी के ऐम्पलाइज को बराबर लोन मेक कितना टाईम लगेगा?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, 1969 के बाद कर्मचारियों के पे-स्केल रिवाइज नहीं हुये है। इसमें जगननाथ जी

हमारा कसूर नहीं है यह कसूर तो ये जो भद्र पुरुष यहाँ बैठे हैं इनका है (कांग्रेस बैचिज की तरफ इ गारा) जनता पार्टी की सरकार तो जब से आई है इसने यह महसूस किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिये। इसने कई कमेटीज भी बनाई है जिनकी रिपोर्टें इन पर गवर्नमेंट ने इन-प्रिंसिपल यह मान लिया है कि इनकी तनखाह बराबर होनी चाहिये।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, उसके बारे में मैं थोड़ी सी क्लैरिफिके इन देना चाहता हूँ। सरदार लखमन सिंह जी ने अभी कहा कि कमेटीज बनाई गई और रिपोर्टें इन की गई। ये दोनों महकमें पहले मेरे पास थे। इसमें कमेटीज नहीं बनी थी। (विधान)

श्री अध्यक्ष: थोड़ी क्लैरिफिके इन दी जा सकती है। मतलब यह है कि हाउस के समने करैक्ट इन्फमें इन दी जानी चाहिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, तीनों चीफ इंजीनियरज और ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैकेगटरीज ने बैठकर इन सारी मागों को देखा था। कमेटी वह होती है जो गवर्नमेंट नोटिफिके न से बने। इसके बारे में इस किस्म की कोई नोटिफिके इन नहीं की गई थी। उन्होंने अपने सुझाव दिये थे। (विधान) उन सुझावों के अनुसार पे-स्केल्ज की अनाउंसमेंट फाईनैन्स मिनिस्टर साहब सअपनी बजट स्पीच में कर चुके हैं। (विधान) ये तीन डिपार्टमेंट्स

पब्लिक हैल्थ, पी0डब्ल्यू.डी(पी0एंड0आर0) और इरीगे ान के थे। वर्कचार्जड मुलाजिमों की पे बराबर होने के बारे में तो फाईनैस डिपार्चमेंट ने मान लिया है लेकिन बाकी जो डिमांडज थी उनकी डिटेल्ज अभी तक डिपार्चमेंटस में रिसीव नहीं हुई है।

श्री भाम ार सिंह: स्पीकर साहब, 1947 से 1978 तक की फिगर्ज अगर हम देखें तो ऐगजैक्टिव इंजीनियर इरीगे ान को छोडकर हर अफसर की पे चीफ सैक्रेटरी से लेकर नीचे तक 50 परसैन्ट के करीब बढी है लेकिन एजैक्टिव इंजीनियर्ज इरीगे ान की पे केवल दो परसैन्ट बढी है। या मंत्री जी बतायेगें कि इसका क्या कारण है?

Mr. Speaker: I will not allow that question. It will be unfair to put supplementary on a clarification which he has given. Please put a supplementary arising out of the main question, otherwise it will be unfair. He may not be prepared for it.

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी फरमाया कि उनके साथ बेइन्साफी होती रही है। क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि यह बेइन्साफी कब तक दूर हो जायेगी क्योंकि 1969 के बाद कोई स्केल रिवाइज नहीं हुये है।

श्री लछमन सिंह: इसी के बारे मे तो बजट स्पीच में कहा है।

श्री अध्यक्ष: जैन साहब ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि यह मामला तकरीबन तय हो चुका है। He is seized of the problem.

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने यह तो मान लिया है कि कर्वचार्जड और रैगूलर मुलाजिमों को बराबर पे—स्केल दिये जायेंगे लेकिन मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा इनको वर्क चार्जड रख कर किया जायेगा य ये सब रैगूलर कर दिये जायेंगे?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, वर्कचार्जड का मतलब मेरे मोहतरिम दोस्त गलत समझ लेते हैं। स्पीकर साहब, वर्क चार्जड ऐम्पलाई एक पर्टिकुलर वर्क के लिये रखा जाता है। मान लो हम एक रैस्ट हाउस बनाना चाहते हैं वहां कुछ तो परमानेंट ऐम्पलाइज होंगे जैसे ऐग्जैक्टिव इंजीनियर, एस0डी0ओ0 और ओवर सीयर आदि लेकिन इस काम के लिये जो मिस्ट्री की जरूरत होती है उसको टेम्परेरी तौर पर रख लेते हैं वह वर्कचार्जड हैं उसका खर्चा उसी वर्क कोजाता है बाकी स्टाफ का खर्चा जो है वह रैगुलर बजट से मीट होता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इसके बारे में भी मैं एक क्लैरिफिके ान देना चाहता हूँ। जिन लोगों की वर्क चार्जड मुलाजिम के रूप में पाचं साल की रैगुलर सर्विस हो चुकी है उनको रैगुलेराइज करने का मसला भी गवर्नमेंट के जेरे गौर है।
(विधान)

चौधरी परी चन्द: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी बताया कि वर्कचार्जड कर्मचारियों के स्केल रिवाइज कर रहे हैं का वे बतायेगें कि ये अभी से रिवाइज कर रहे या पिछली तारीख से कर रहे है?

श्री बीरेन्द्र सिंह: ये पहली अप्रैल से रिवाइज हो रहे है क्योंकि इसतें 26-27 लाख रूपये की फाइनै गल इम्पलीके गन इनवौलव्ड है।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, मेरे सवाल के जवाब में मन्त्री महोदय ने कहा है कि ये तो टेम्परेरी वर्क चार्जड कर्मचारी है।

श्री अध्यक्ष: ऐसा इन्होंने नहीं काह हैं इनहने तो कहा है कि एक पर्टिकुलर वर्क के लिये इनको रखा जाता है। जैसे कोई रैस्ट हाउस बनाना हो कैनाल बनानी हो या ब्रिज बनाना हो।

श्री मांगे राम गुप्ता: फिर भी तो वे टेम्परेरी हुये।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, एक काम जब खत्म हो जये तो उन्हें दूसरे काम पर भी लगा दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: वीरेन्द्र सिंह जी ने अभी यह भी कहा है कि पांच साल की कजनकी वर्कचार्जड के रूप में सर्विस होगी उनको रैगुलर कर रहे है।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, इसमें थोडा अन्तर है।

श्री अध्यक्ष: मुझे तो कोई अन्तर नहीं दिखाई देता।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, इन्होंने कहा है कि पांच साल की जिनकी रैगुलर सर्विस होगी उनको रैगुलर किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: इसकमें कोई अन्तर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि एक पर्टिकुलर वर्क के लिये ऐम्पलाई रखे जाते है लेकिन ज बवह खत्म हो जाता है तो दूसरे वर्क पर भी उनका लगा दिया जाता है। इरीगे अन एंड पावर मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि काम करते करते जिन कर्मचारियों को पांच साल हो गये है उनको रैगुलर करने की कोशिश की जा रही है।

**Additional Dearness Allowance to Work-Charged Employees
in P.W.D. (B&R)**

***1177. Shri Shamsheer Singh:** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the work charged employees of P.W.D. (B&R) are paid Additional Dearness Allowance on the basic pay (unrevised pay scale) while those whose services were regularized in 1974 are paid on the total emoluments of basic pay (of unrevised pay scales) and Dearness Pay;

(b) if so, a copy each of the Government's order allowing two different rates of Additional Dearness Allowance be laid on the Table of the House.

(c) whether any order was issued by the Engineer-in-Chief(B&R) in the year 1978 to pay the Additional Dearness Allowance to the work-charged staff as is being paid to the regular employees;

(d) if so, a copy of the same be laid on the Table of the House;

(e) whether the order referred to in part(c) above has been withdrawn; and

(f) the steps taken to remove the discrimination?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(क) जी नहीं।

(ख) प्र न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्र न नहीं उठता।

(ङ) —यथोपरि—

(च) —यथोपरि—

श्री भाम ार सिंह : स्पीकर साहब मंत्री महोदय ने ए पार्ट का जवाब 'नहीं' में दिया है मैं मंत्री महोदय से जानना

चाहता हूँ क्या यह बात सही है कि वर्कचार्जड इम्पलाइज को डीयरनैस अलाउन्स बेसिक पे पर दिया जाता है ओर रैगुलर इम्पलाइज को टोटल पे पर दिया जाता है , इसका क्या कारण है?

श्री लछमन सिंह: इसका मेरे पास जवाब नहीं है। आपका यह सवाल मेन क्वे चन से सम्बन्धित नहीं है इसका आप सेपरेट नोटिस दें।

श्री भाम ोर सिंह: स्पीकर साहब इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ।

Mr. Speaker: I must admit that it appears to be something of a technical nature and I have not understood the question myself.

श्री भाम ोर सिंह: बडा सिम्पल सा सवाल है। जो वर्कचार्जड इम्पलाइज है उनको बेसिक पे पद डीयरनैस अलाउन्स दिया जाता है ओर जो रैगुलर है उनको टोटल पर मिलता है इसका क्या कारण है?

श्री लछमन सिंह: आप सैपरेअ नोटिस दें।

श्री भाम ोर सिंह: बडा सा सिम्पल सा सवाल है।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, पे के चार कम्पोनेंटस है बेसिक पे, डी0ए0 डीयरनैस पे और इन्टेरम रिलीफ।

श्री भाम ोर सिंह: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

Mr. Speaker: The question, I thin, is a fair one. If the hon. Minister has not got facts with them at present, he may kindly supply the informait0on to the hon. member.

श्री लहरी सिंह मेहरा: अगर पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर जवाब नहीं दे सकते है तो इरीगे ान एन्ड पावर मिनिस्टर साहब जवाब दे दे।

श्री अध्यक्ष: यह क्वै चनर आवर है, सजै ान आवर नहीं है।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब सरदार लछमन सिंह जब भी किसी सवाल का जवाब देते है तो 'नहीं ' में देते है या यह कहते है कि 1982 तक पुरा हो जायेगा। क्या आप इनके सवाल के जवाब देने के तरीके में तरमीम करायेगें ताकि ये हाउस को टालने की कोि ा ा न करें। (हंसी)

Raids by Sales Tax Department

***1040. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) the total number of raids, made by the Sales Tax Department in the State upto 31-1-79 after the formation of Janta Government;

(b) the total amount spent on the aforesaid raids upto 31-1-79; and

(c) the total amount of tax recovered as a result of raids upto 31-1-79?

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि जनता पार्टी की हकूमत आने के पचास 839 छापे मारे गये। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि ये छापे कितने रेलवपे स्टेशनों पर कितने बस सटैन्ड पर और कितने बैरियरज पर मारे गये हैं?

चौधरी भोर सिंह: यह तो मैं नहीं बता सकता। जिलेवार बता सकता हूँ इसके लिये नोटिस देंगे तो ये भी बता दूंगा।

चौधरी सन्त कंवर: स्पीकर साहब, पिछले दिनों एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरों को बुरी तरह से पीटा गया था उन अफसरों ने पीटने वालों के खिलाफ केसिज दर्ज कराये थे लेकिन हमारे नोटिस में यह बात आई है कि किसी मंत्री महोदय के दबाव के कारण उन अफसरों ने अपने केसिज विदड्रा कर लिये हैं। अगर यह सच है तो ऐसा क्यों किया गया?

चौधरी भोर सिंह: अध्यक्ष महोदय यह बात बिल्कुल सही है कि पिछले वर्ष छापे मारे गये थे और अफसरों की पीटायी भी हुई थी। यह बात भी बिल्कुल सही है कि केसिज रजिस्टर हुये थे। जहां तक विदड्रा होने का सवाल है यह इन्फर्मेंशन मेरे पास नहीं है। अगर आनरेबल मॅबर नोटिस देंगे तो मैं जवाब दे दूंगा।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि बिना हुक्म दिये कोई केस विदड्रा नहीं हो सकता। होम मिनिस्टर चौधरी वीरेन्द्र सिंह की तरफ से या सबका होम मिनिस्टर डाक्टर मंगल सैन जी की तरफ से हुक्म दिये बिना विदड्रा नहीं हो सकते।

श्री अध्यक्ष: मिनिस्टर महोदय ने कहा है कि केसिज दर्ज हूये हे विदड्राल का इनको इस वक्त पता नहीं है।

श्री भाम ार सिंह: यह स्प्रे ान आफ टूथ है। उनको पता है लेकिन जान-बूझ कर नहीं बता रहे हे।

चौधरी संत कंवर: अब इनके पास जवाब नहीं है तो सोमवार को जवाब दे दें।

Mr. Speaker: This is not directly linked with the main question.

श्री भाम ार सिंह: स्पीकर साहब यह तो उनके महकमे से सम्बन्धित है, उनको जवाब देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कहा है कि मुकदमें दर्ज हुये है उसके बाद क्या कर्यावाही हुई है इस बारे मे जानना चाहते है तो अलग से नेटिस दें

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: जगाधरी के अन्दर जो इनके महकमें के कर्मचारियों की पिटाई हुई थी और केस रजिस्टर

करवाये गये थे क्या उनको विदद्वा करने के लिजये मंत्री जी ने कोई हुक्म फरमाया था या ऐसी कोई बात उनके नालेज में है?

Mr. Speaker: He has said that he does not know anything about withdrawal.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब मैकं तो यह पूछ रहा हूं कि मंत्री जी ने विदद्वा के आर्डर किये है या नहीं ?

चौधरी भोर सिंह: मैंने कोई आर्डर नहीं किया।

डा० बृज मोहन गुप्ता: मैं मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि इन 839 छापों में से कितने रात को मारे गये और कितने दिन को मारे गये?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मूल चन्द मंगला: क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि 839 छापों में कितने डिसाइड हो गये ओर कितने अभी पैन्डिंग है और जो पैन्डिंग है उनका कितने दिनों तक फैसला हो जायेगा?

चौधरी भोर सिंह: अध्यक्ष महोदय यह जो 839 छापे मारे गये थे इनमें 12 लाख 8 हजार 668 यपये पैनेल्टी का, 9 लाख 26 हजार 698 यपये टैक्स्ज का असैस हुआ था जिसमें से 18 लाख 72 हजार 118 रूपये रिकवर हो चुके हे और बाकी चार लाख रूपये के केसिज चल रहे है।

चौधरी ई वर सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन 839 छापों में से बैरियर पर कितने छापे मारे गये हैं?

चौधरी भोर सिंह: बैरियर पर छापे मारने का यह सवाल नहीं है।

चौधरी खुर गीद अहमद: क्या मंत्री महोदय जिलेवाइज रिकवरी की फिगर तथा जगाधरी की रिकवरी की फिगर बताने की कृपा करेंगे?

चौधरी भोर सिंह: स्पीकर साहब अम्बाल में 154 छापे मारे गये। 35893.00 रूपये टैक्स असैस हुआ। 2 लाख 72 हजार और 560.00 रूपया पैंनेल्टी लगाई गई। 3 लाख 8 हजार 453.00 रूपये टोटल बना और पूरे का पूरा रिकवर कर लिया। भिवानी में 73 छापे मारे गये। 27 हजार 482.00 रूपया टैक्स असैस हुआ। 95 हजार 627.00 रूपया पैंनेल्टी लगाई गई। 87 हजार 459.00 की रिकवरी कर ली गई।

चौधरी सन्त कंवर: स्पीकर साहब छापे दो किस्म से पडते हैं। गांव में जो लोग नाजायज भाराब निकालते हैं उनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया जाता है और उस आदमी को सजा होती है। दूसरे जो बिजनैस प्रिमिसिज हैं उन पर छापे मारे जाते हैं उन छापों के बारे में डिपार्टमेंटल आफिसर्ज खुद डिसाइड करते हैं। उनके उपर जुर्माना होता है। वे पुलिस केस रजिस्टर

नहीं होते। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बजाये जुर्माने के सजा देने का प्रोविजन करने का सरकार का कोई विचार है?

चौधरी भोर सिंह: ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: क्या यह फ़ैक्ट है कि देहात में भाराब निकलाने का केस तो रजिस्टर होता है और भाहर का केस रजिस्टर नहीं होता है।

चौधरी भोर सिंह: जी हां। यह ठीक है।

Mr. Speaker: It appears to be a surprising state of affairs.

Construction of Warehouses in the State

***1104. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the government to construct more Warehouses for storing food-grains in the State, if so, the names of places where these are proposed to be constructed?

कृषि मंत्री (ब्रिगेडियर रण सिंह): स्पीकर साहब, हम अगले साल काफी गोदाम बनाने जा रहे हैं और यह इंफरमे तन सदन की मेज पर रखी गई है।

Statement

**The Statement indicating places where
Warehouses for storing foodgrains are to be constructed.**

S.n	Name of the Centre	programme for construction of Godowns during 1979-80				Total
		HWC	HAFED	HAMB	FSD	
1	2	3	4	5	6	7
District Ambala		Figures in M.Ts.				
1	Ambala City	5000	-	-	-	5000
2	Yamuna Nagar	8000	10000	-		18000
3	Shahjadpur	-	-	5000		5000
4	Barara	-	5000	5000		10000
5	Kalka	-	-	5000		5000
6	Naraingarh	-	-	5000		5000
7	Bilaspur	-	-	5000		5000
8	Mustafabad	-	4000	-		4000
Total		13000	19000	25000		57000
District Karnal						
1	Taraori	-	-	-	1000	1000

2	Gharaunda	5000	-	-	-	5000
3	Madlauda	5000	-	5000	-	10000
4	Panipat	1000	-	-	-	1000
5	Samalkha	--	2000	-	-	2000
6	Assandh	-	-	5000	-	5000
Total		11000	2000	1000	1000	24000

District Kurukshetra

1	Shahabad	4000	10000	-	-	14000
2	Kurukshetra	8000	4000	-	-	12000
3	Kaithal	5000	20000	-	3000	28000
4	Guhla	5000	16000	-	-	21000
5	Pehowa	5000	8000	-	-	8000
6	Pundri	5000	3000	-	-	8000
7	Ladwa	5000	5000	-	5000	15000
8	Radaur	5000	12000	-	-	17000
9	Siwan	3000	-	-	-	3000
10	Ismailabad	5000	-	-	-	5000
11	Pipli	-	-	-	5500	5500
12	Thol	-	4000	-	-	4000

Total		45000	82000	-	13500	140500
District Jind						
1	Jind	-	-	--	2000	2000
2	Safidon	-	-	-	1000	1000
3	Narwana	-	4000	-	-	4000
4	Kalayat	-	6000	-	-	6000
5	Pillukhera	-	10000	-	-	10000
Total		-	20000	-	3000	23000
District Rohtak						
1	Rohtak	-	-	15000	-	15000
2	Bahadurgarh	-	-	-	10500	10500
3	Kalanaur	-	-	5000	-	5000
Total		-	-	20000	10500	30500
District Hissar						
1	Hissar	-	-	-	667	667
2	Uklana	-	-	5000	-	5000
3	Ratia	-	4000	-	-	4000

4	Fatehabad	3000	-	-	-	3000
5	Barwala	-	-	5000	-	5000
6	Tohana	4000	-	-	2000	6000
7	Bass	-	-	5000	-	5000
8	Narnaund	-	2000	-	-	2000
Total		7000	6000	15000	2667	30667
District Sonapat						
1	Gohana	-	-	-	2000	2000
2	Ganaur	-	3000	-	-	3000
Total		-	3000	-	2000	5000
District Bhiwani						
1	Bhiwani	-	-	-	4000	4000
Total		-	-	-	4000	4000
District Mohindergarh						
1	Mohindergar h	-	-	-	950	950
2	Rewari	-	-	-	700	700
Total		-	-	-	1650	1650
District Gurgaon						

1	Hodal	1500	-	-	-	1500
2	Palwal	-	10000	-	2200	12200
3	Gurgaon	-	5000	-	-	5000
4	Pataudi	4000	6000	-	-	10000
5	Hasanpur	---	-	5000	-	5000
6	Firozpur Zirkha	-	2000	-	-	2000
7	Sohna	-	2000	-	-	2000
8	Punhana	-	2000	-	-	2000
9	Mudkola	-	2000	-	-	2000
Total		5500	29000	5000	2200	41700 0
District Sirsa						
1	Sirsa	5000	5000	-	-	10000
2	Rania	-	-	5000	-	5000
3	Ellenabad	2000	-	-	-	2000
4	Dabwali	2000	-	-	-	2000
5	Kalanwali	2000	2000	-	-	4000
6	Chautala	-	-	2500	-	2500

Total	11000	7000	7500	-	25500
G.Total	92500	16800	8250	4051	38351
	0	0	0	7	7

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: स्पीकर साहब, जो लिस्ट सदन कीमज पर रखी गई है यह 62 गोदामों की लिस्ट है जिनको 1979-80 में बनाने का प्रावधान है मैंने यह देखा है कि ये सारे गोदाम कस्बों या भाहरों में है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का मंडियों से दूर गांवों में गोदाम बनाने का विचार है जिससे कि किसान लोग अपने घर के नजदीक ही अपना अनाज उन गोदामों में रख सकें?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, हम मंडियों के पास गोदाम बनारहे है ओर भाहरों में भी गोदाम बना रहे है क्योंकि वहां पर सडक और रेल से लाने ले जाने का साधन है और हमको अगर अनाज बाहर ले जाना हो तो काफी मदद मिलती है। वर्मा साहब का सुझाव अच्छा है हम विचार कर लेंगे?

डा० बृज मोहन गुप्ता: स्पीकर साहब, मैंने अम्बाला जिले की लिस्ट देखी है उसमें जगाधरी का नाम नहीं है। जगाधरी बहुत बडी मंडी है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जगाधरी में वेयर हाउस बनाने का विचार किया जायेगा?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, यमुनानगर जगाधरी के बिल्कुल पास है। यमुना नगर में एक आठ हजार टन का और दुसरा दस हजार टन का यानि कि अठारह हजार टन की कैपेसिटी के दो गोदाम बनाने जा रहे है।

श्री गुलजार सिंह: स्पीकर सहाब, मंत्री जी ने बताया है कि अगले साल में हम काफी गोदाम बना रहे हैं क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गोदाम बनाने का काइटेरिया क्या है?

श्री ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, इस काम के लिये हमारे डिपार्टमेंट की एक कमटी बनी हुई है और दुसरे डिपार्टमेंट जैसे फुड कार्पोरेट इन आफ इंडिया है उकनी भी एक कमटी बनी हुई है जो गोदाम बनाने का फैसला करती है। दुसरे हम यह देखते है कि अनाज की पैदावार कहां ज्यादा होती है मिसाल के तौर पर कुरुक्षेत्र जिला जो पैदावार के लिहाज से सब से अच्छा है वहां पर 2 लाख 41 हजार टन की कैपेसिटी के गोदाम बनाये है। इसके अलावा आप देखे कि महेन्द्रगढ में अठारह हजार टन की कैपेसिटी के गोदाम बनाये है। हम तो जहां ज्यादा पैदावार होती है उसके हिसाब से और प्रोक्योरमेंट के हिसाब से गोदाम बनाते है।

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकरसाहब, मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि हम देहातों में भी गोदाम बनायेगे लेकिन जो लिस्ट सदन की मेज पर रखी गई है उसमें देहातो का नाम नहीं

हैं क्या मंत्री महोदय बातने की कृपा करेंगे कि वे कौन से देहात हैं जहाँ पर गोदाम बनाने का सरकार विचार है?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब सवाल बहुत अच्छा है जो गोदाम बनाने का हमने प्लान बनाया है वह तो बता दिया है और उसकी लिस्ट सदन की मेज पर रख दी गई है लेकिन हम कुछ देहातों में गोदाम बनाने जा रहे हैं जैसे कनीना आपके जिले महेन्द्रगढ़ में है रानिया जिला सिरसा में है ऐलनाबाद जिला सिरसा में है। छछरौली, अम्बाला जिला में है। मुलाना ओर मुस्तफाबाद अम्बाला में हैं सफीदों में बना रहे हैं हसनपुर और फरुखनगर गुडगांव में हैं इन जगहों पर भी स्पीकर साहब हम गोदाम बनाने जा रहे हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि गोदामों की कंस्ट्रक्शन का काम पी0डब्ल्यू0डी को सौंपा गया है या प्राईवेट ठेकेदार को दिया गया है और अगर प्राईवेट ठेकेदार को दिया गया है तो क्यों दिया गया है?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, यह सवाल तो बड़ा पेचीदा है और इसकी मुझे खबर नहीं है कि पी0डब्ल्यू0डी बनाती है या ठेकेदार बनाता है।

Chaudhri Birender Singh: Some of the godowns are under construction.

Mr. Speaker: It is not the question asked. Probably he has not got the information.

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, मैं इसके बारे में आज ही एक घंटे में जवाब दे दूंगा।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जो लिस्ट सदन की मेज पर रखी है उसमें कोसली बेरी, झज्जर और बादली का नाम नहीं है कोसली और झज्जर तो मंडियां हैं और इस एरिया में काफी अनाज होता है और बेरी तो मंत्री महोदय की कांस्टीच्यूएंसी भी है क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यहां पर भी गोदाम बनाने का सरकार कोई विचार है।?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, मैं अपने साथी को बताना चाहता हूँ कि हमारा फर्ज बनता है कि पहले हम दूसरे जिलों में बनायें और फिर बाद में आने वाले जिलों में।

Mr. Speaker: I think, that is a very good tradition, if set up.

चौधरी लाल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नारायणगढ़ और कालका में गोदाम बनाने का सरकार का कोई विचार है?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, मुझे कल यह है कि चौधरी लाल सिंह वह इन्फरमेंशन तो पढ़ते नहीं हैं जो सदन की मेज पर रखी गई है और सवाल पूछने लग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: चौधरी लाल सिंह जी नारायणगढ़ और कालका दोनों जगह पांच-पांच हजार टन की कैपेसिटी के गोदाम

बनाये जा रहे है। मै आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना करुंगा कि पहले ठीक तरह से जवाब पढ लें ओर फिर सप्लीमेंटरी पूछ लिया करें।

चौधरी खुर पीद अहमद: स्पीकर साहबखु जो लिस्ट सप्लाई की गई हे उसको मैने देखा है। हमारे यहां नूह काफी बडी मंडी है और अभी तक वहां पर कोई गोदाम नहीं हैं कया मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि क्या फ्यूचर में नूह में कोई गोदाम बनाने का सरकार का विचार है?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, आप जानते है कि खुर पीद अहमद मेरे पुराने मित्र हैं वहां पर इसी साल जरूर गोदाम बनायेगें।

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड गोडाउन वहां बनाता है जहां मंडी होती हैं एक तो गोडाउन्ज मंडियों में बनाये जाते है। देहात में गोडाउन्ज वहां बनाये जाते हे जहां बीज खाद या कीटना एक दवाइयां जमा की जाती है। ये गोदाम कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट बनाता है। रहा सवाल पी0डब्ल्यू0डी0 या ठेकेदार के बनाने का इसका कायदा यह है कि जिस महकमें के पास जो बजट है वही महकमा टेन्डर इंवाइट करता है फिर काम अलाट करता है।

(10.00 बजे)

चौधरी देस राज: स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर फूड एण्ड सिविल सप्लाय विभाग, मार्किटिंग बोर्ड, हैफड और हरियाणा वेयर हाउसिंग गोदाम वगैरह बनाते है क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि गोदाम बनाने का काम केवल हाउसिंग को ही सौपने का सरकार का विचार है?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, सुझाव तो अच्छा मालूम..... पर विचार करेगे लेकिन हम इस का स्टेट लैवल पर कोआर्डिनेशन करते है.... साथ स्पीकर साहब, मै एक बात और क्लेरीफाई करना चाहता हूं और

जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनहोने इस प्वायंट को रेजसाहब, इस वक्त हमारे पास आलुओं के गोदाम बहुत कम है। सिर्फ.....और वह भी तरावडी के अन्दर है जिसके कारण इस दफा हमारे किसान.....तकलीफों का सामना करना पडा, इसके लिये हम विचार करेगे कि ओर

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने.....हरियाणा के अन्दर 62 के करीब गोदाम बनाने जा रही है। में आपके.....जानना चाहता हूं कि हिसार में कितने गोदाम बनाये जा रहे है औरजगह पर बनाने का सरकार का विचार है?

श्री अध्यक्ष: चौधरी पीरचन्द जी, मिनिस्टर साहब ने पूरी लिस्ट दे रखी है। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चल जायेगा।

ब्रिगेडियर रण सिंह : स्पीकर साहब, इस सवाल से सम्बन्धित सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अगर फिर भी आनरेबल मैबर हिंसार का पूछना चाहेंगे तो मैं पढ़ देता हूँ हिंसार प्रोपर, उकलाना, रतिया, फतेहबाद, बरवाला, टोहान, बास, नारनोंद। यहां पर 70 हजार टन की कैपेसिटी के स्टोर बनेंगे। इसके बाद मैं चौधरी विठ्ठलजी को एक ओर खबर देना चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र में 56-56 हजार टन कैपेसिटी के एफ0 सी0 आई0 तीन और गोदाम बनायेगी।

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब मेरी स्प्लीमेंटरी है (गोर) मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूँ (गोर एवं विधान)

श्री अध्यक्ष: चौधरी लाल सिंह जी, कृपया करके आप बैठिये। मैं माननीय सदस्यों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रिप्लाय मंत्री जी देते हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की कृपा किया करें और उसमें जो आलरेडी इन्फॉर्मेशन दी गई हो, उसके उपर स्प्लीमेंटरी न पूछें ताकि हाउस का समय जाया न हो।

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि सिरसा जोकि

अनाज की एक बड़ी भारी मंडी है वहां पर कितने और किस किस जगह पर गोदाम बनाये जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: भांकर लाल जी, इस बारे में जवाब आ चुका है। आप कृपया मंत्री जी के जवाब को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

चौधरी राजेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अभी मेरे लायक साथी श्री खुरीद जी ने एक प्रश्न पूछा और उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने धोशणा की है कि नूह में भी गोदाम बनायेंगे।

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, दोस्ती को भी मद्देनजर रखा गया है लेकिन वहां पर गोदाम बनाने की जरूरत भी है।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: स्पीकर साहब, कुरुक्षेत्र और करनाल हरियाणा के दोनो जिले पैदावार के लिहाज से सब से आगे हैं और सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र जिला में 1 लाख 80 हजार टन की कैपेसिटी के गोदाम बनाये जा रहे हैं। और इनको चारो संस्थायें बना रही हैं करनाल जिले में केवल 24 हजार टन की कैपेसिटी वाले गोदाम बनाये जा रहे हैं पर नीलोखेड़ी को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या वहां पर भी ऐसे कोई गोदाम बनाने की सरकार के स्कीम विचारधीन है जिससे कि लोगों को भी और राहत मिल सके?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, करनाल में पहले ही 1 लाख 93 हजार टन के गोदाम बन चुके हैं और मैंने अपने

जवाब में बताया है कि इस साल हम 24 हजार टन कपैसिटी वाले गोदाम और बनाने जा रहे हैं इसलिये मैं कह सकता हूँ कि सब से ज्यादा गोदाम कुरुक्षेत्र और करनाल में बने हैं इसके अलावा मैंने पहले भी बताया है कि एफ0सी0आई0 वाले 56-56 हजार टन की कपैसिटी वाले गोदाम इनके इलाके में बनाने जा रहे हैं।

Qualifications for Yoga Coach

***1169. Shri Mool Chand Mangla:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the qualifications prescribed for the post of Yoga Coach togetherwith the pay-scale of this post;

(b) the qualifications prescribed for the post of Yoga instructors; and

(c) whether a degree holder with one year diploma in Yoga is eligible for the pay-scale of Rs. 300-600 or more than it?

शिक्षा मंत्री (श्री हीरानन्द आर्य):

(क) विभाग में योगा-कोच की कोई आसामी नहीं है, अतः वेतन मान होने का प्रश्न ही नहीं।

(ख) योगा-शिक्षकों के लिये निर्धारित अहितायें निम्नलिखित हैं:-

अनिवार्य:

1. किसी मान्यता प्राप्त योगा संस्थान से एक वर्ष का योगा-प्रतििक्षण का डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र।

2. मैट्रिक स्तर तक हिन्दी अनिवार्य।

ऐच्छिक:

1. भारीरिक प्रतििक्षण का प्रमाण पत्र, भारीरिक ििक्षा का डिप्लोमा, भारीरिक ििक्षा का स्नातक, भारीरिक ििक्षा का स्नातकोत्तर।

2. टीचर आफ थ्यूरी।

3. थैरापैटिक अनुभव जिससे कि योग के माध्यम से बिमारियो का इलाज करना या प्राकृतिक इलाज।

(ग) नहीं।

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, अभी माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के 'क' भाग में योग-कोच की कोई आसामी नहीं है। अतः वेतनमान होने का प्रश्न ही नहीं उठता जबकि लास्ट ईयर इन्होंने आवासन दिलाया था कि हरियाणा में योग-ििक्षा के लिये प्रावधान रखा जायेगा और अब कहते हैं कि योग-कोच की कोई आसामी नहीं है। स्पीकर साहब, योग-ििक्षा बच्चों के लिये उनके स्वास्थ्य के लिये बहुत लाभकारी है इसके कारण बच्चों को कोई बीमारी वगैरह नहीं होती है। क्या सरकार

इस शिक्षा की और खास ध्यान देने का विचार रखती है ताकि बच्चों को इससे लाभ हो सके?

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, पहछली दफा कोच के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी बल्कि यह कहा गया होगा कि हम हर जिले के अन्दर एक एक योग-केन्द्र खोलने जा रहे हैं। मैं अपने आनरेबल मँबर को यह बता देना चाहता हूँ कि चार केन्द्रों में तो हमने इंस्ट्रक्टर लगा दिये हैं और सात के लिये बोर्ड के पास डिमांड भेज दी गई है।

डा० बृज मोहन गुप्ता: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के अन्दर योग केन्द्र कितने हैं?

श्री अध्यक्ष: इन्होंने बताया है कि हर जिले में एक लगाने का विचार है।

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, इन्होंने केन्द्रों के बारे में पूछा है वह मैंने इनको पहले ही बता दिया है कि जमना नगर, गुडगांव जीन्द और करनाल में केन्द्र है और वहां पर इंस्ट्रक्टर लगे हुये हैं और कोच की कोई पोस्ट नहीं है।

श्री जगननाथ: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि इन योग सैन्टरों के अन्दर स्वामी अग्निवेश और स्वामी आदित्वे को भेजने की कोई प्रोपोजल है?(हंसी)

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि हिन्दी भाषा में जो जवाबयहां मेज पर रखे जाते हैं या जो मंत्री महोदय पढ़ते हैं उसको भाषा बहुत मुश्किल होती है और सारी ग़ामर उसमें भर दी जाती हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या कोई ऐसी प्रोजेक्ट है कि आगे से सरल हिन्दी में या हिन्दुस्तानी भाषा में जवाब दिये जायें?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य दलाल जी ने जो बात कही है उससे मैं भी सहमत हूँ मैं मानता हूँ कि हमें हिन्दी में कार्यवाही करनी चाहिये और कर भी रहे हैं लेकिन हिन्दी को सरल भाषा इस्तेमाल किये जाने चाहिये। आज कल आइडिया यह बनता जा रहा है कि जितने कोई मुश्किल भाषा इस्तेमाल करेगा उतनी उस आदमी की नालेज ज्यादा मानी जाती है। इसलिये आगे से सरल भाषा इस्तेमाल करने की कोशिश की जानी चाहिये। हिन्दुस्तानी भाषा के सरल भाषा इस्तेमाल करने की कोशिश की जानी चाहिये।

चौधरी संत कवर: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जिन मेरे साथियों ने (चौधरी सुरेन्द्र सिंह की तरफ इंतार करते हुये) धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम में योग की शिक्षा ली है क्या उनको इन केन्द्रों में नौकरी देने की सरकार की कोई प्रोजेक्ट है?

श्री हीरा नन्द आर्य: अगर कोई ऐसा आदमी प्रान्त में है तो माननीय सदस्य उसका नाम बतायें हम विचार कर लेंगे। (हंसी)

श्री अध्यक्ष: नाम तो इन्होंने बताया है। (हंसी)

श्री हीरा नन्द आर्य: जिनका इन्होंने नाम बताया है वे दरखास्त दे दे हम विचार कर लेंगे।

चौधरी हरिचन्द हुड्डा: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि योग मास्टर और पी0टी0 मास्टर में क्या फर्क है?

श्री हीरा नन्द आर्य: उतना ही अन्तर है जितना गाय और भैंस में होता है।

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, सारे हाउस की यह सैंस है कि योग शिक्षा से काफी लाभ है और मंत्री महोदय ने भी इस बात को माना है। अगर इससे इतना लाभ है तो इन केन्द्रों में केवल चार ही टीचर्स क्यों लगाये गये हैं? क्या इनकी संख्या बढ़ाने पर विचार किया जायेगा?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, मैं इसके बारे में हाउस की इतलाह के लिये कह दूँ कि सरकार ने योग शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये फैसला किया है कि और कई सैन्टर्स खोले जाएं। इसके लिये एक तो मंगला साहब के इलाके के नजदीक सैन्टर खोला जायेगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी भीम सिंह हे उनके जिम्मे यह काम लगाया गया है जैसे

यमुना नगर में मुकन्द लाल कालेज है वहां पर योगा की शिक्षा का बहुत अच्छा इन्तजाम है , बडी अच्छी शिक्षा दी जा रही है। मैं समझता हूं कि उस किस्म के सैन्टर्ज बहुत जयादा खोले जायेगें ऐसा सरकार ने फैसला किया है ।

Construction of Bus Stand

***1190. Chaudhri Ishwar Singh:** Will the chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the government to construct a bus stand at Gulha Chika; if so, the time by which it is likely to be constructed;

(b) the number of bus routes being operated from gulha to Kaithal together with the income accrued from them during the last four months;

(c) whether the Government proposes to run the local buses from Samana Mandi to Kaithal and from Sewan to Kaithal. and

(d) the reasons for stopping the bus service which was being plied from Gulha to Delhi during the Last years?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला): कथन सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

स्टेटमेंट

(क) चीका के स्थान पर बस स्टैन्ड बनाने का प्रस्ताव हैं। इसके लिये भीघ्र ही भूमि का चुनाव किया जा रहा हैं इसके निर्माण की निर्ि चत तिथि का दिया जाना कठिन है।

(ख) 31 वापसी चक्कर। इन नक्करों की आय का पिछले 4 मास का विवरण निम्नलिखित है:—

मास का नाम	प्रति कि.मी. आय (पैसों में) कैथल—गुहला	कैथल खडका बरास्ता गुहला
नवम्बर, 78	179	177
दिसम्बर, 78	199	190
जनवरी, 79	189	174
फरवरी, 79	212	175

(ग) दो वापसी चक्कर पहले से ही कैथल—सीवन मार्ग पर चलाये जा रहे है। समाना मंडी कैथल मार्ग एक अन्तर्राज्यीय मार्ग है। इस मार्ग पर बस सेवा सम्बन्धित राज्य (पंजाब) की स्वीकृति से ही चलाई जा सकती है। यह मामला पंजाब सरकार के साथ उठाया जायेगा।

(घ) गुहला—देहली मार्ग पर बस सेवा इसलिये बन्द की गई थी कि बस को सीधी सवारी उपलब्ध नहीं थी और इस मार्ग की आय भी बहुत कम हो रही थी।

चौधरी ई वर सिंह: मंत्री जी ने जवाब के 'ग' भाग में बताया है कि यह इन्टरस्टेट मार्ग है। समाना मंडी से कैथल 17 किलोमीटर पडता है। परन्तु इसमें सात किलोमीटर पंजाब का टुकडा है ओर बाकी दस किलोमीटर हरियाणा का टुकडा हैं मंत्री जी ने फरमाया है कि पंजाब की स्वीकृति से बसें चलाई जायेगी। चूंकि इस मार्ग पर पांजाब की बसें भी चलती है। तो क्या पंजाब वालों ने हरियाणा से स्वीकृति ले रखी है?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: उन्होंने पहले ही ले रखी है।

अध्यक्ष द्वारा निरूपण

प्र नों के उत्तरों की ज्यादा प्रतियां सप्लाई करने सम्बन्धी

चौधरी सरदार खां: स्पीकर साहब, सवालें का जवाब जो पटल पर रखा जाता है वह सबे पास नहीं पहुंचता। आज जितने भी सवालों का जवाब दिया गया है उनमें से किसी सवाल का जवाब भी मेरी मेज पर नहीं रखा गया है मैं चाहता हं कि सवाल का जवाब हर सदस्य के डैस्क पर रखा जाना चाहिये। इसके बाद मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नूह में जो बस अड्डा बनना था उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: जो मास्टर सरदार खां ने प्वायंट रेज किया है कि सबके पास जवाब की कापी नहीं पहुंच रही है। उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट 45 कापियां विधान सभा को प्रोवाइड करती है। उनमें से कुछ कापियां तो प्रैस वालों को दे दी जाती है और कुछ कापियां उन मैनबर साहिबान को दी जाती है जो सवाल पूछते हैं इसलिये कापियां सारे सदन को नहीं मिल सकती। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 10-10 कापियां और लाने का प्रबन्ध किया जाये ताकि दो-चार मैनबर साहिबान के बीच में एक एक कापी अवेलेबल हो जाये। इसमें एक प्वायंट और भी है कि वैसे जितनी फालतू कापियां भेजी जायेगी तो मैं बर साहिबान जब मंत्री महोदय जवाब देते हे उसकी तरफ जयादा ध्यान नहीं देंगे आपस में भाोरगुल हो जाएगा। इसलिये ये कापियां कम इसलिये बांटी जाती है कि मैनबर साहिबान मंत्री महोदय के जवाब को गौर से सुनें। इसके बावजूद भी आगे से मैं जवाब में कापियां ज्यादा बंटवाउंगा लेकिन जब मंत्री जी जवाब दे रहे हो तो मैनबर साहिबान उनको ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें।

चौधरी सरदार खां: जब मंत्री महोदय यह जवाब दे देते है कि उत्तर मेज पर रख दिया गया है तो दूसरों को उसका कोई फायदा नहीं होता क्योकि उनके पास उसकी कापी नहीं होती इसलिये या तो मंत्री महोदय पूरा जवाब पढ कर सुना दिया करें या जवाब की कापी सब के पास होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: ऐसा तब किया जाता है जब जवाब बहुत लम्बा हो और वह सारा पढ़ना नामुमकिन होता है।

श्री सुमेर चन्द भट्ट: स्पीकर साहब, आपको याद होगा मैंने आपको लिख कर भी भेजा था कि जवाब की कापियां न होने की वजह से मੈंबरोँ को दिक्कत होती है। कम से कम इतना तो होना चाहिये कि एक डैस्क पर एक कापी जरूर आनी चाहिये। अगर चार-पांच डैस्कोँ के लिये एक कापी दी जाएगी फिर भी बडी मुँ कल होगी।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। आप बार-बार ऐसे प्र न क्यों रेज कर रहे हो?

तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री जगननाथ: स्पीकर साहब, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो बसें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चलाई जा रही है वहां क्या हमारी स्टेट का दुसरी स्टेट से समझौता है? जैसे कैथल हरियाणा में है तो वहां से समाना के लिये पंजाब की बसें चलती है, क्या हरियाणा सरकार पंजाब सरकार से कोई ऐसी बातचीत कर रही है कि हरियाणा की ही बसें कैथल से समाना चलाई जाये?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: यह जो जवाब पटल पर रखा गया है। इसमें कहा गया है कि पंजाब सरकार के साथ मीटिंग

होगी तो उनसे बातचीत करके ही क्योंकि यह अन्तर्राज्यीय मार्ग है, बसें चलाई जा सकती है।

श्री अध्यक्ष: यह तो रैसीप्रोकल मामला है, आपस में समझौता करके ही बसें चलाई जा सकती है।

चौधरी सरदार खां: क्या फिरोजपुर झिरका बस स्टैण्ड को बस डिपो में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है?

श्री अध्यक्ष: यह तो अलग सवाल हो जाता है अगर मंत्री महोदय जवाब दे सकते हैं तो दे दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजतला: फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री भामोर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि नरवाना में डिपार्टमेंट द्वारा बस स्टैण्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: यह मामला अन्डर कंसिड्रेशन है।

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): इसका जवाब मैं देता हूँ। जहाँ तक नरवाना का सम्बन्ध है यह छोटा स्टेशन है। छोटे स्टेशनों के बारे में अभी सरकार सोच रही है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर अभी पहले लिये गये हैं और वहाँ लैंड ऐक्वायर कर ली गई है। हिसार अभी रहता है वहाँ भी बस अड्डा नहीं बना है।

पैसों की कमी के कारण अभी डिस्ट्रिक्ट लैवल पर ही सोच विचार कर रहे हैं।

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, 'घ' भाग में मुख्य संसदीय सचिव ने फरमाया है कि आय की कमी के कारण गुहला-देहली मार्ग पर बस बन्द कर दी गई। क्या मुख्य मंत्री संसदीय सचिव महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिससमय यह बस चलाई गई थी क्या उस समय आय का अन्दाजा नहीं लगाया गया था, या आय में कमी बाद में हुई थी?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: पहले गुहला से दिल्ली बस चलाई गई थी। वह कैथल से दिल्ली कर दी गई हैं उसका कारण यह है कि कैथल से गुहला 31 बसें चलती हैं जिनकी वजह से इस बस में सवारियां कम मिलती थी और दूसरे यह गुहला से रात के 9 बजे चलती थी और तीसरा यह कि गुहला से दिल्ली डायरेक्ट सवारियां नहीं मिलती थी। इन वजुहात से यह बस बन्द करनी पड़ी।

Syphon on the Khatela Minor

***1187. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the problem of water logging subsists in the area around the syphon on the Khatela Minor; and

(b) if so, the details of the steps proposed to be taken to combat the water logging in the said area together with the time by which these are likely to be taken?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(अ) नहीं।

(ब) उक्त 'अ' अनुसार प्र न ही नहीं उठता।

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, मैं.....

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी मुझे आपका नाम तो बोलने दीजिये आप को बोलने का समय दिया जा रहा है थोडा धैर्य रखिये। हां अब पूछिये।

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, इसी सवाल का जवाब मैने पिछले दिनों पूछा था तो उसमें बताया गयाथा कि इस नाम की कोई माइनर ही नहीं है और अब स्वीकार कर रहे है कि इस नाम की माइनर है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे 15 जनवरी को वहां गये तो उनको दिखाया गया कि खटेला माइनर का जो साईफन है वह गलत बना हुआ है टुटा हुआ है इस समस्या का हल हो सकता है यदि इसे ड्रेन साईफन बना दिया जाये। इन्होने कहा था कि बदल देंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जहां तक मुझे याद है मैने एक सवाल के जवाब में स्वामी जी को कहा था कि इस किस्म

को कोई माइनर नहीं है परन्तु जो इनहोने सवाल पूछा था उसको इन्होने खेतड़ी माइनर लिखा था। खेतड़ी माइनर नाम की कोई भी माइनर नहीं है अब जिसके बारे में सवाल है वह गुड़गावं जिले में हैं इसके अलावा दुसरी बात यह है कि जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि मैं 15 जनवरी को वहां गया था और घोशणा की था कि यह साईफन गलत है इसको बदल दिया जायेगा, ऐसी कोई घोशणा मैंने नहीं की थी। यह माइनर तो उत्तर प्रदेश की है जो हमारे इलाके से गुजरती है। स्वामी जी कहते हैं कि वहां वाटर लौगिंग की प्रोब्लम है। उनको कहीं पानी नजर आ गया होगा तो उन्होने कह दिया कि वाटर लौगिंग की प्रोब्लम हैं मैं काफी घूमता रहता हूं उनके इलाके में भी काफी गया हूं परन्तु वे कभी भी समय पर नहीं मिले। यह प्रोब्लम इसलिये होती है क्योंकि ड्रेन साईफन के नीचे से गुजरती है जिसके कारण कभी कभी साईफन में गन्दगी फसने के कारण पानी ओवर फ्लो हो जाता है। हमारी हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से ऐप्रोच कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार मान भी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से यह बात चल रही है कि आगरा कैनल की डिस्ट्रीब्यूटरीज और ड्रेन्ज का हरियाणा में जो सिस्टम है वह सारा हमें ट्रांसफर कर दिया जाये। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्री कर लिया है उम्मीद है कि एक साल के अन्दर यह हो जायेगा।

स्वामी आदित्यवे 1: इस सम्बन्ध में मैंने उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अभियन्ता से पत्र व्यवहार किया था जिसका उत्तर मेरे

पास आया है कि ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि जिस समय सिंचाई के लिये पानी को अधिक आवकता होती है उस समय खटेला माइनर का साईफन बाधा होता है क्योंकि उपर के किसान बन्धा लगाते हैं या उपरी बन्धों का कबाड आकर साईफन में अटक जाता है और पर्याप्त पानी साईफन द्वारा नहीं निकल पाता है जिससे नीचे के किसानों को हानि होती है। यदि खटेला माइनर साईफन न होकर ड्रेन साईफन कर दी जाये तो समस्या हल हो जाने की आशा है।

श्री अध्यक्ष: खटेला माइनर से सारे हाउस का कोई कंसर्न नहीं है।

स्वामी आदित्यवेत: अध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी लिखा है.....

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी कभी कभी हमारी भी बात सुन लिया करिये इस खटेला माइनर का सारे हाउस से सम्बन्ध नहीं है इसलिये औरों को भी टाईम लेने दीजिये।

स्वामी आदित्यवेत: इस पत्र में यह भी लिखा है कि इस को हरियाणा सरकार के ड्रेन्ज विभाग के फरीदाबाद खंड ने बनवाया है। अतः मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इस माइनर साईफन को ड्रेन साईफन बना दिया जाये। यह उत्तर प्रदेश सरकार का काम नहीं है मैं उम्मीद करूंगा कि इसे ड्रेन साईफन बना दिया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, ये स्वामी जी पता नहीं कहां से ऐसी सूचनायें इकट्ठी करते हैं। इनसे वाद विवाद करना मेरे बस का नहीं है। इन्होंने जो फ़ैक्टस दिये हैं ये बिल्कुल गलत हैं पता नहीं ये किन एका0ई0एन0 और चीफ इंजीनियरों से बात करते रहते हैं।

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, ये अपनी सीट से बार बार उठते रहते हैं कहीं इनकी सीट में खटमल तो नहीं?

स्वामी आदित्यवे I: मैं अपने हल्के की प्रॉब्लम को तो बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी मैं आपसे एग्री करता हूं कि आप अपने हल्के की खटेली माइनर के बारे में बता रहे हैं या पूछ रहे हैं पर इस हाउस में और भी 89 मैनबर हैं उनका समय आप क्यों जाया कर रहे हैं? आप उनका समय खराब न करें और कृपया बैठ जाएं।

मैनबर साहिबान अब क्वै चन आवर खत्म होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों
के लिखित उत्तर

**Committee constituted to consider the demands of work
charged employees of P.W.D. (Public Health)**

***1175. Shri Mange Ram Gupta:** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a Committee of Administrative Secretaries/Engineer-in-Chief was constituted in the Year, 1978, to consider the demands of work-charged employees in Public Health Department;

(b) if so, a copy of the recommendations, if any, made by the said Committee be laid on the Table of the House; and

(c) the details of recommendations, if any, which have been accepted by the Government so far?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(क) वर्ष 1978 में प्रशासकीय सचिवों और मुख्य अभियन्ताओं की कोई समिति गठित नहीं की गई थी। बल्कि यह मामला प्रशासकीय सचिवों और मुख्य अभियन्ताओं के मध्य दो बैठकों में विचारा गया था।

(ख) और (ग) इस ग्रुप द्वारा की गई सिफारिशों का निरीक्षण प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जा रहा है क्योंकि यह मामला अभी विचाराधीन है बैठकों में हुये विचार-विमर्शों का ब्यौरा जन हित में विधान सभा के पटल पर नहीं रखा जा रहा है।

Pay Scales of the employees of P.W.D. (B.&R.)

***1178. Shri Shamsheer Singh:** Will the minister for Public works be pleased to state-

(a) the pay scales of various categories of work-charged employees in the public works Department (B & R)

(b) the year in which the said pay scales were revised last; and

(c) whether the Government proposes to revise their pay scales; if so, the time by which it is likely to be done?

Public Works Minister (Shri Lachhman Singh):

(a) The information at Annexure 'A' is laid on the Table of the House.

(b) In 1962.

(c) A decision to revise the pay scales with effect from 1-4-78 has been taken.

ANNEXURE 'A'

Pay scales of the various categories of work-charged employees in public Works Department

S.N.	Name of Post	Existing Grades
1.	(a) Foreman Special/Foreman Driller	300-15-400/20-500
	(b) Foreman Heavy Plan Overhaul/Assistant Foreman Special	210-10-300
2	Foreman miscellaneous-	150-5-225

	Machine Sho, Carpentry Reinforcement, Mechanical/Electrical Drilling, Permanent way, Carriage and wagons	
3	Assistant Foreman Heavy Plant Overhaul Electrical (Heavy Plant)	150-5-225
4	Assistant Foreman, Misc. for Jobs, given under Foreman Misc.	120-3-150
5	Electrical Light Plant Chargeman Jobs given against Foreman (Heavy Plant Overhaul)	130-2-150
6	Chargeman Misc. for Jobs against Foreman Misc. Boiler/Chargeman civil	100-3-130
7	Cuperintendent (a) Power Plant/Superintendent Air Conditioning/Refrigeration	400-20-600
	(b) Assistant superintendent, Air Conditioning/Regrigeration	220-10- 250/15-400
	(c) Chargeman Air	120-6-

	Conditioning		150/10-200
	(d) Supervisor	Air-Conditioning/Refrigeration and Refrigeration/Air Conditioning Mechanic	100-5-150
	(e) Operator	Air Conditioning/Refrigeration Grade-I	90-3-012
		Grade-II	60-3-90
8	Superintendent	Water Works/Superintendent Distribution	
	(a)	for plants of capacity higher than 2 m.g.d.	250-15-400/20-500
	(b)	For plants of capacity 0.5 m.g.d. to 2 m.g.d. and for plants having gravity filters upto 2 m.g.d.	200-10-300
	(c)	for plants of maller sizes than given above items (a) and (b)	100-5-150
9	Shift Engineers	Grade I/Project Engineer	250-15-400
10	Shift Engineers	Grade	150-15-

	II/Project Sectional Officer	225/15-300
11	Supervisor (including Electrical)	80-3-110
12	Safety Supervisor	80-3-110
13	Template Maker of Steel Structure	100-5-150
14	Fitter, Steel Structure	100-5-150
15	Fitter, Heavy Machine	85-3-115
16	Fitter Heavy Vehicles tyres	85-3-115
17	Erector, Steel Structure	100-5-150
18	Tool Operator (Machanic)	80-3-120
19	Blacksimth	80-3-120
20	Copper and Tin Smith	60-3-90
21	Pipe Fitter	
	Grade-I	125-5-175
	Grade -II	88-3-118
22	Diesel and Auto Motor Mechanic	60-5-125
23	Plate Layer	60-3-90
24	Opertor and drivers of Oxygen	60-3-90

	and Anetylene Plants	
25	(i) Telephone Operator/Clerk	50-3-80
	(ii) Telephone Attendant	50-3-80
26	Planer Operator	60-5-180
27	Saw Operator	60-5-125
28	Driller, Jack, Hammer	60-5-125
29	Attendant Grout Pump	30-3-60
30	Tradesman Mate to all above trades	35-1-45
31	Instrument Mechanic	50-2-60/3-90
Operators and Drivers		
32	(i) Shovela draglines and Granes (Diesel)	60-5-125
33	-do- Special	125-10-225
34	Electrical Overhead Travelling crane Operator	90-5-125
35	Shovel (Electrical)	125-10-225
	(ii) 2 cum to 4 Cum	
36	Operator Control Room (Heavy Plant)	125-5-175

37	Turbine Operator (Heavy Plant) House	125-5-175
38	Operator Hoker (Heavy Plant)	125-5-175
39	Auxiliary Operator	60-3-90
40	Asstt. Urbine Operator (Light Pant)	90-5-125
41	Astt. Operator Boiler (House Light Plant)	90-5-125
42	Ross Staddle Carier	90-5-125
Drivers of Carriers		
43	Light Vehicle Cars, Petrol Truck 2½ Tonne. etc. And heavy vehicles diamond tees, Mack tumpers	90-3-120
44	Bus Driver	90-3-120
45	Road Roller Driver (Seam or Diesel)	100-3-130
46	Euclids. Drivers	90-3-150
47	Dinky Loco Driver	90-3-150
48	Main Line Loco Driver	60-3-90/5-125
49	Assistant Dinkey Loco Driver	60-3-90

Tractor Operators		
50	All types of Tractors Drivers	60-3-90
51	Earth Moving Machinery other than Tractors, like road graders scrapers and Bulldozers etc.	100-5-150
52	Rockle Shovel Perator	90-5-150
53	tournal rocker Operator	60-3-90
54	Host OperatorLift Operator	60-3-90
Operators Stationery Plant		
55	Mechanical and Electricla Air Compressor , Pump Crete, Welding Sets, Concrete Mixers Small Generating sets/ Turner	60-3-90
56	Workshop Machinery Operator	60-3-90
57	Operator, diamond drill	60-3-90
58	Operaor Crizzly	60-5-125
59	Operator (Misc.) Cooling Plant	60-5-125
60	Operator Air Compressor 30 Cum per in or above diamond drill operator	60-5-125
61	Operator cement	60-5-125

	pump/operator crete/Assistant Driver	pump
62	Operator mechanical/Driver (Diesel and electrical)	pump 90-3-120
Concrete Placement Crew		
63	Vibrator Operator	100-5-150
64	Bucket Operator	75-5-125
65	Sand Blast Operator	60-3-90
66	Laitenance Cutter	60-3-90
67	Air/Water Jet Operator	50-3-80
68	Concrete Finisher	90-3-120
69	Bell Boy	60-3-90
70	Clean up man	40-2-60
71	Helper for above oiperations (Skilled Labour)	30-1-40
72	Operator (Gas Producers Plant)(44½-1-54½
73	Cleaner/Dilman	32-1-37
74	Boiler Attendent	51-1-60
75	Bammerman	51-1-60

76	T.M. Mate	35-1-45
77	Creaser	32-1-37
78	Attendants Concrete Mixer	32-1-37
79	Attemdant Pump	30-1-150
80	Worshop Gangman	32-1-37
81	Gangmates	32-1-45
82	Coalman	32-1-37
83	Condenser Attendant	32-1-37
84	Mucker Jamadars	35-1-45
85	Muckers	30-1-40
86	Slingers	40-2-80
87	Barryman (Crowcarman)	35-1-50
88	Fireman	50-1-60
Fire Fighting		
89	Fire Station Officer	150-5-225
90	Sub-fire officer	120-3-150
91	Leading Fireman	100-5-120/8-192
92	Driver/Fire Pump Operator	80-4-120

93	Driver cum Mechanic	106-6-160/8-200
94	Fire Fightingman	60-4-100
Transportation		
95	Station Master	75-5-100
96	Train examiner	75-5-100
97	Railway guard	75-5-100
98	Head Shunter	57½-1-67½
99	Shunter	50-1-60
100	Gangman	35-1-45
101	Trolley Man	35-1-45
102	KeyMan	35-1-45
103	gangmate	40-1-50
104	Trolley Jamadar	40-1-50
105	Draken man	40-1-50
106	Travelling Ticket Checker	60-1-75
107	Fireman or Stocker	50-1-60
108	Pointman	40-1-50
109	Permanent Way Inspector	200-10-300

110	Asstt. Way Inspector	100-8-180-10-200
111	Bus conductor	50-1-60
Electrical		
112	Cable Jonter/Armature winder	90-5-140/6-170
113	Fitter	85-3-115
114	Wireman Grade -I	60-3-90
	Grade-II	-
115	Line man Grade-I	60-3-90
	Grade-II	-
116	Switch Board Attendant	60-3-90
117	Guttiman	New Category
118	Blastman grade-I	90-5-120
	Grade-II	60-3-90
119	Attendant Electrical Pump	40-2-60
120	Wireless Mechanic	55-3-130
121	Metre Reader Electrical/Water	50-2-70
122	Electrician Grade-I	60-5-125

	Grade-II/Electric Mistry	60-3-90
123	Trademan's Mate to all above Traders	35-1-45
124	Carpenter Grade-I	125-5-175
	Grade-II	88-3-118
125	Stone Masson	
	Grade-I	125-5-175
	Grade-II	88-3-118
126	Painter	
	Grade-I	125-5-175
	Grade-II	88-3-118
127	Brick Layer	
	Grade-I(Masson)	125-5-175
	Grade-II	88-3-118
128	Pummer Class-I	125-5-175
	Class-II	88-3-118
129	Coal Tar Enamel Painter	90-3-120
130	surveyor	75-5-140
131	Rock Drivller/Well Borer	80-5-150

132	Trademen's Mate to all above Trades	35-1-45
133	Tube-well Driller	150-8-190/10-240
134	Work Inspector	60-4-80/5-120
135	Work Mistry/Work Supervisor	50-3-80/4-88
136	Earth Work Mistry/Supervisor	44½-1-59½
137	Work Munshi or Mortor Mate	44½-1-59½
138	Ganger Mate/Road Mate	35-1-45
139	Tar sprayer	51-½-55
140	Darogha (A horticultural) or Head Mali	45-1½-60
141	Reservoir Keeper	39½-1½-54½
142	Keyman tumoncocak water Supply work	50-2-60
143	Petrolman	30-½-35
144	Pipe Lineman	30-½-35
145	Sewer Helper	51-1-60
146	Discharge & Sounding	32-1-42

	Attendant	
147	Store Keeper	50-3-80-4-100
148	Stroe Clerk, Stroe Munshi, time Clerk, Lodger/Bin Card Clerk	50-2-70
149	Store Attendant/Store Coolie	32-1-37
150	Material Mistry	42½-1½-57½
151	Silt Analyst	90-5-140
152	Silt Observer pressure Pipe Observer, Strata Observer	50-3-80
153	Asstt. Laboratory Attendant	30-1-42
154	Bhisti	30-½-35
155	Chowkidar	30-½-35
156	Boatsman or Ferryman	45-½-50
157	Malis	37-½-42½
158	Mazdoor's Hospital	30-½-35
159	Dak cyclist	30-½-35
160	Dak runner (Foot)	30-½-35
161	Frasher	30-½-35
162	Khalasis	30-½-35

163	Peons, Telegraphic & Revenue	30-½-35
164	Sowars (Cawal)	30-½-35+Rs. 8/-
165	Sweeper/Swwerman	30-½-35
166	Sweeper Namadars	30-½-35
167	Beldar or regulation Beldar	30-½-35
168	Khansama	30-½-35
169	Boatsman hyead or Jamadar	50-1-55
170	Boatsman Naib Jamadar	45-½-50
171	Bullockman & Cartman (without Bullocks) or Camel Man (without Camel)	30-½-35
172	Bullockman with one bullock or camal Man with one camel or mule man with one mule	30-½-35+Rs. 30/-
173	Bullockman with two bullocks or camel man with two camel and Muleman with on mule	30-½-35+Rs. 60/-
174	Gate Keeper	30-½-35
175	Khalasis Survey	37½-½-42½
176	Khalasis Survey Head	45-½-50

177	Mali Chowkidar	37½-½-42½
178	Road Inspector	60-4-80/5-120
179	Terezo Finisher	
	Grade – I	150-5-200
	Grade- II	120-3-150
180	Plasterer	125-5-175
181	Core Conserver	50-3-80/4-100
182	Gauge Reader	35-1-45
183	White Washing & Colour Washingman	88-3-118
184	Floor Polisher	88-3-118
185	Welder	60-5-175
186	Horticulture Supervisor	80-5-120
187	Laboratory Assistant	40-2-60
188	Reaseach Assistant	New Category
189	Chemist	New Category
190	Water Motor Inspector	Do
191	Patwari	Do

192	Other Misc. Class IV categories such as skilled coolie, Fitter Coolie, Skilled, Helper, Filter Attendant etc.	Do
-----	---	----

Manufacture of Illicit Liquor

***1069. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the total number of persons taken into account for manufacturing illicit liquor in the State during the financial year 1978-79; and

(b) the action taken against persons involved in such cases?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh):

(a) 4163

(b) 1435 persons were convicted, 10 persons were acquitted, cases against 4 persons in 4 cases were canceled, cases against 5 persons in 5 cases were sent-up as untraced, cases against 1126 persons in 1096 cases are under investigation and cases against 1575 persons in 1540 cases are pending trial.

Masters of Provincialized Cadre

***1170. Shri Mool Chand Mangla:** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any

proposal under consideration of the Government to promote the masters of the Provincialized Cadre to the posts of Headmasters in the State?

शिक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य): जी हां।

Tehsil Headquarters without Civil Hospitals

***1191. Chaudhri Ishwar Singh:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any tehsil in the State where there is no Civil Hospital, if so, the reasons therefore together with the steps; if any, proposed to be taken to set up a Civil Hospital there;

(b) whether the Government propose to ungrade the Primary Health Centre to Civil Hospital at Gulha;

(c) whether it is a fact that there is neither any Centre nor a small hospital in the villages situated on the other side of Ghaghar in Gulha tehsil of Haryana; if so, the arrangement, if any proposed to be made by the Government to provide the medical facilities to the people of said area and

(d) the total number of Ayurvedic Dispensaries in gulha Tehsil?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डा० कमला वर्मा):

(क) जी हां।

राज्य की दो तहसीलें बावल तथा गुहला है, जंहा पर सामान्य हस्पताल नहीं है। इन तहसीलों के हैडक्वार्टर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। इन तहसीलों के हैडक्वार्टर पर हस्पताल की व्यवस्था किये जाने का मामला विचारधीन है।

(ख) मामला विचारधीन है।

(ग) जी नहीं।

हरियाणा की गुहला तहसील में घग्घर के पार दो उप-केन्द्र तथा एक यूनानी डिस्पेंसरी उस क्षेत्र में लोगों को चिकित्सा सुविधांये उपलब्ध करने हेतू कार्य कर रहे है।

(घ) एक यूनानी औशधालय मिला कर पांच।

Relief to the sterilized persons in the State

***921. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the total number of persons to whom relief has been given during the period from 4th July, 1977 to 30th June, 1978 on account of their being affected by sterilization during the Emergency period together with the nature of the relief given to them; and

(b) the district-wise number of persons who have been successfully recanalised during the period as referred to in part (a) above?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डा० कमला वर्मा):

(क) दिनांक 4.7.77 दिनांक 30.6.78 तक बंधीकरण से पीड़ित कुल 12 व्यक्तियों को नकद रूप से सहायता दी गई।

(ख) दिनांक 4.7.77 दिनांक 30.6.78 तक कुल 179 व्यक्तियों के पुनः नस जोड़ आग्रे तन किये गये, जिन का जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

कंमाक	जिला का नाम	पुनः नसजोड़ आग्रे तन की संख्या
1	अम्बाला	10
2	भिवानी	11
3	गुड़गांव	57
4	हिसार	4
5	जीन्द	8
6	करनाल	12
7	कुरुक्षेत्र	10
8	नारनौल	22
9	रोहतक	21
10	सिरसा	1

11	सोनीपत	23
कुल जोड़		179

Income from Excise Duty and Sales Tax

***1171. Lala Balwant Rai Tayal:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state the total income received by the Haryana Government from Excise and Sales Tax during the years 1976-77, 1977-78 and 1978-79 to-date together with the total expenditure incurred on its collection during the said period?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह):
विवरण विधान सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरणी

वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 (28-2-79 तक) में हरियाणा राज्य में आबकारी तथा बिक्री करों के अधीन प्राप्त आय तथा उनको एकत्रित किये जाने का खर्चा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	आबकारी अधिनियम		बिक्री कर अधिनियम	
	कुल आय	कुल व्यय	कुल आय	कुल व्यय

1976-77	236218940	1565794	625544413	13506367
1977-78	262602709	1543929	694562489	13325255
1978-79 (1-4-78 से 28-2-79 तक	166276051	1422394	736534733	13834986

**Appointment of new members on the Subordinate Services
Selection Board**

***1145. Rao Ram Narain:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that any more persons have been appointed recently as Members of the Haryana subordinate Services Selection Board;

(b) whether it is also a fact that antecedents of persons so appointed are verified prior to their appointment as such; and

(c) if reply to part(b) above be in the affirmative whether the antecedents of the persons referred to in part (a) above were verified, if so, the details thereof?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) नये सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा उनकी योग्यता और पूर्व-वृत्त विचारने के पचात की गई थी ।

Hospitals at Chotala, Narnaund and Kalnaur

***1110. Shri Jai Narain:** Will the Minister for Health be pleased to state the time by which the Hospitals at Chotala, Narnaund and Kalanaur are likely to start functioning?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डा० कमला वर्मा): चौटाला में हस्पताल इस समय पुरानी डिसपैन्सरी के भवन में कार्य कर रहा है नया भवन निमार्णाधीन है और 1980-81 में इस भवन में हस्पताल स्थापित हो जाने की सम्भावना है ।

नारनौंद एवं कलानौर हस्पताल 1981-82 तक चालू होने की सम्भावना है ।

Construction of Bridge over Yamuna River

***1157. Shri Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) whether the amount of expenditure incurred on the construction of a bridge over the Yamuna River which links Panipat with the Territory of the Uttar Pradesh, was shared by the Haryana Government;

(b) if so, the amount which fell to the share of the Haryana Government for the purpose;

(c) whether it is a fact that the said bridge has been rendered unfit the traffic for the last 6/7 months due to floods in the Yamuna River; and

(d) whether the Haryana Government has addressed any communication to the Uttar Pradesh Government to repair the aforesaid bridge, if not; the reasons therefore?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(ए) जी हां।

(बी) 178879/- रूपये

(सी) जी हां।

(डी) जी हां।

Category-wise work charged employees

***1166. Rao Dalip Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the category-wise number of work-charged employees in each Circle of the Irrigation Department whose services were regularized in 1974 and prior to that year;

(b) whether it is a fact that employees of Irrigation Department who were regularized before 1974 and during

1974 or afterwards are being given different pay-scales for the same post;

(c) if so, the names of such categories of employees together with the details of different set of pay-scales; and

(d) the steps being taken to remove the anomaly in the pay-scales for the same post?

Interim Reply

' अ० स० प० क० ४/१०-७९-४ लो० नि०

वीरेन्द्र सिंह

मंत्री सिंचाई एवं बिजली विभाग,

हरियाणा चण्डीगढ़

दिनांक, चण्डीगढ़ मार्च, 1979

विशय: तारांकित विधान सभा प्र न नं० 1166 जे कि राव दलीप सिंह विधान सभा सदस्य द्वारा पूछा गया है।

प्रिय श्री कर्नल साहब,

उक्त विधान सभा प्र न राव दलीप सिंह, विधान सभा सदस्य ने पूछा है और यह प्र न उत्तर के लिये 23-3-79 को लगा हुआ है इस प्र न के संदर्भ में निवेदन है कि इसका उत्तर अभी तैयार नहीं हो सका है, क्योंकि सदस्य महोदय द्वारा मांगी गई सूचना अधीनस्थ कार्यालयों से एकत्रित की जानी है और

तत्प चात उसे मुख्यालय में कम्पाईल किया जाता है। इस प्रकार यह स्वाभाविक है कि अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना एकत्रित करने और फिर कम्पाईल करने में समय लगेगा। अतः आप से अनुरोध है कि तारांकित विधान सभा प्र न नं० 1166 के उत्तर के लिये तिथि 23-3-79 की बजाये लगभग 15 दिन के प चात कोई अन्य तिथि निश्चित करने की कृपा करें।

आदर सहित,

आपका

ह/—

वीरेन्द्र सिंह

कर्नल राम सिंह

अध्यक्ष,

हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़।”

सचिव द्वारा घोशणा

श्री अध्यक्ष: साहिबान अब सैक्रेटरी साहब एक अनाउसमेंट करेगें।

सचिव: मैं सादर सदन को इतलाह देता हूँ कि हरियाणा विनियोग विधेयक 1979 जो कि हरियाणा विधान सभा ने 16 मार्च 1979 को पास किया था उस पर राज्यपाल महोदय ने 19 मार्च 1979 को मन्जूरी दे दी है।

ध्यानाकर्षण सूचना

जिला करनाल में भाराब के नये ठेकों की नीलामी सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: मुझे स्वामी आदित्यवे 1 एम0एल0ए0 से, जिला करनाल में कुछ जगहों पर भाराब के नये ठेकों की नीलामी के बारे एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस मिला है। यह प्रस्ताव मंजूर किया जाता है। आनरेबल मँबर अपना नोटिस पढ दें और एक्साइज एण्ड टैक्से इन मिनिस्टर अपना जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

स्वामी आदित्यवे 1: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सादर सदन का ध्यान इस अतयाव एक लोक महत्व के मामले अर्थात् भाराब बन्दी की और आकर्षित करना चाहता हूँ। गत वर्ष में हरियाणा सरकार ने अपने नीति वक्तव्य में तथा सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोशणा की थी कि चार वर्ष के अन्द-2 भाराब के सभी ठेके हरियाणा में बन्द करदिये जायेंगे तथा जितने भाराब के ठेके हरियाणा में हैं उनकी संख्या में सरकार कमी करेगी, किन्तु किसी भी हालत में नवीन जगहों पर भाराब के ठेके नहीं खोले जायेंगे। किन्तु मुझे खेद के साथ सदन के समक्ष

कहना पड़ रहा है कि वर्ष 1979 के लिये हरियाणा सरकार ने हरियाणा में जिला करनाल में चार स्थानों पर देसी भाराब के नये ठेके नयी जगहों के लिये नीलाम कर दिये है। वे जगहें है घोर, जुन्डला, सफीदों रेड असन्ध तथा कासनी।

अतः मैं चाहता हूं कि हरियाणा सरकार यदि भाराब बन्दी की चार वर्षीय नीति का अनुसरण करना चाहती है तो इससे हआ क्यों जा रहा है। सरकार इस और तुरन्त ध्यान दें तथा नवीन जगहों से ठेकों को समाप्त करे तथा अन्य कोई नयी जगह पर भाराब के ठेके न खोले। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, भाराब बन्दी के ही सम्बन्ध में पचकुला से तथा और भी कई जगहों से रैजोल्यु इन आये हैं वहां के लोग मेरे पास लिख लिख करके भेज रहे है फिर भी वहां पर ठेके खोले जा रहे है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी आपने अपना नोटिस पढ दिया है। अब कृपया बैठ जाईये।

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह): अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी का पहले भी इसी सम्बन्ध में एक काल अटैन् इन मो इन भी है जिसका मैंने 26 तारीख तक समय मांगा है इस काल अटैन् इन मो इन काज जवाब भी उसी के साथ मैं 26 तारीख को दे दूंगा।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

खालों को पक्का करने के बारे में ध्यानाकर्षण सूचना को वापिस लेने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: श्री हरस्वरूप बूरा एम0एल0ए0 का खालों के पक्का करने के बारे में एक काल अटैन् इन मो इन मंजूर किया गया था। वह उन्होंने वापिस ले लिया है। इसलिये उसके बारे में जो बयान इरीगे इन एण्ड पावर मिनिस्टर साहब ने देना था वह अब देने की कोई आव ययकता नहीं है।

वक्तव्य

लोक निर्माण मंत्री द्वार ने इनल हाईवेज पर हो रही गम्भीर दुर्घटनाओं सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: पब्लिक वर्कस मिनिस्टर साहब ने श्री कवंल सिंह एम0एल0ए0 के "ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ने इनल हाईवेज पर रोजनान हो रहे सीरियस एक्सीडैन्टस के बारे में आज ब्यान देना था। वह अपना ब्यान दे दें।

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): स्पीकर साहब, श्रीमती सुशमा स्वराज और स्वामी जी हिन्दी का झगड़ा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: यदि आपको वाकई में हिन्दी पढने में कोई मुि कल आती है तो आप इंग्लिश में पढ सकते है। लेकिन जहां जहां कुछ समझाना चाहें वहां कुछ हिन्दी में समझा दें।

श्री लछमन सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कल पंजाबी की बडी स्पोर्ट की थी इसलिये मेरा फर्ज बनता है कि मुझे हिन्दी में पढना चाहिये। इस छोटी सी बात के लिये स्वामी जी को नाराज नहीं करना चाहिये अध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दी में ही पढ देता हूँ।

यह सही है कि हरियाणा राज्य में उद्योग कृषि इत्यादि में तीव्र प्रगति के कारण उच्च राष्ट्रीय मार्ग नं० 1 अर्थात् दिल्ली हरियाणा समीप से अम्बाला तक तथा उच्च राष्ट्रीय मार्ग नं० 10 दिल्ली हरियाणा समीप से रोहतक, हिसार, सिरसा, उबवाली पर यातायात काफी बढ़ा है।

उच्च राष्ट्रीय मार्ग नं. 1 पर यातायात वर्ष 1975 में पैसेंजर बार युनिट 8000 प्रति दिन से वर्ष 1978 में 12000 प्रति दिन बढ़ गई है। यातायात में इसी प्रकार की बढ़ोतरी उच्च राष्ट्रीय मार्ग 10 के बहादुरगढ़ सैक्टर 10 पर हुई है। भारत सरकार, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा नियत मापदण्ड के अनुसार एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग उस समय चार लेन का पात्र हो जाता है जब उस पर यातायात 10000 पैसेंजर पर यूनिट हो जाता है अतः इस मापदण्ड के अनुसार उच्च राष्ट्रीय मार्ग नं. 1 चार लेन के योग्य है जबकि उच्च राष्ट्रीय मार्ग नं. 10 बहादुरगढ़ सैक्टर 10 में चार लेन के योग्य है और बहादुरगढ़ से आगे भी यदि भविष्य में होने वाली यातायात में बढ़ोतरी को ध्यान में रखा जाये, इसको ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार, भारत सरकार नौवहन तथा

परिवहन मंत्रालय पर पहले दौर में उच्च राष्ट्रीय मार्ग नं० 1 तथा उच्च राष्ट्रीय मार्ग नं. 10 के बहादुरगढ सैक इन के चार लेन के कार्य को तुरन्त आरम्भ करने के लिये दबाव डालती रही है।

यातायात में बढ़ौतरी के कारण दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है। पुलिस विभाग के रिकार्ड अनुसार इन उच्च राष्ट्रीय मार्गों पर दुर्घटनाओं की संख्या वश 1975 में 160 से वर्ष 1978 में 266 तक बढ़ी हैं इस संख्या में घातक तथा गम्भीर दुर्घटनाएं भी शामिल है जिनकी संख्या वर्ष 1975 में 56 से वश 1978 में 119 तक बढ़ी हैं। सड़क दुर्घटनायें निम्न कारणों से होती है।

1. सड़कों में दोश।
2. गाड़ियों में दोश।
3. चालकों में दोश।

उच्च राष्ट्रीय मार्ग नं०1 तथा नं. 10 के ज्योमैट्रिक स्टैंडरडज काफी पर्याप्त हैं तथापि उच्च राष्ट्रीय मार्ग नं०1 की क्षमता कम है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि यद्यपि 1978 में यातायात 10000 पैसेन्जर वार यूनिट से बढ़ गया है , परन्तु अभी तक इसको चार लेन नहीं किया गया है। भारत सरकार ने सिद्धान्त रूपय से माना है तथा नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय ने बारबार घोशणा की है कि उच्च राष्ट्रीय मार्ग नं०1 को दिल्ली सीमा से अम्बाला तक चार लेन चौडा किया जायेगा तथा उच्च

राष्ट्रीय मार्ग नं०10 को बहादुरगढ़ भाहर की बाहरी सीमा तक चार लेन चौड़ा किया जायेगा।

5. हाल ही में भारत सरकार ने उच्च राष्ट्रीय मार्ग नं०10 को बहादुरगढ़ भाहर तक चौड़ा करने का प्रोजैक्ट मन्जूर किया है और उच्च राष्ट्रीय मार्ग नं०1 को चौड़ा करना उनके विचाराधीन है। दिल्ली हरियाणा सीमा से मूरथल तक के पहले भाग का अनुमान भारत सरकार को मंजूरी हेतू भेजा जा चुका है। उच्च राष्ट्रीय मार्ग नं०10 पर बहादुरगढ़ तक चार लेन का कार्य आरम्भ किया जा रहा है। जबकि उच्च राष्ट्रीय मार्ग नं०1 का कार्य भारत सरकारसे दिल्ली हरियाणा सीमा से मूरथल तक के अनुमानों की मंजूरी प्राप्त होने के तुरन्त उपरान्त आरम्भ कर दिया जायेगा।

6. दुर्घटनाएं गाड़ियों के तेज चलाने भाराब के न े में गाड़ियां चलाने, गाड़ियों पर अधिक भार वाहन करने तथा रासते में गाड़ियां खड़ी करके बाधा पहुंचाने के कारण होती है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन दोशों को दूर करने के प्रत्येक प्रयत्न किये जाते है। वह पैट्रोलिंग करते है और उनको वायरलैस तथा प्रथत उपचार बक्से भी दिये हुये है। पुलिस अधिकारी अपने अमले को ट्रैफिक कन्ट्रोल करने के बारे में घोर प्रि ाक्षण दे रहे है।

7. सरकार अम्बाला तथा हिसार में स्थित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के द्वारा मोटर गाड़ी अधिनियम की जहां तक उसका सम्बन्ध यातायात को रैगुलेट तथा कन्ट्रोल करने से है

पालना करा रही है। फरीदाबाद में भी इसी प्रकार का प्रधिकरण स्थापित किया गया है।

8. परिवहन विभाग के पास पुलिस अधिकारी एक इन्फोरेसमेंट विंग है जिसका मुखिया एक पुलिस अधीक्षक है। अम्बाला, करनाल, रोहतक तथा हिसार में इस विंग के अधिक इन्फोरेसमेंट दस्ते स्थापित किये गये हैं। उनके पास राडरा,स्टौप वाच तथा सांस की जांच करने वाले यन्त्र होते हैं। ये दस्ते उच्च मार्गों पर भारी पीकरो की हालत में तथा तेज गाड़ी चलाते हुये चालकों को पकडने तथा उनका चालान करने के लिये लगातार गत लगाते रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस सडक को प्रयोग करने वाली जनता को शिक्षित करने के लिये ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह भी मनाती है। इसके अतिरिक्त अपने क्षेत्र में जिला पुलिस भी ट्रैफिक को कन्ट्रोल करने में सहायता करती है।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, ऐसा लगता है कि स्टाफ जवाब देने में अपनी काबलियत का दिखावा करना चाहता है। (व्यवधान)

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मैं दफतर के भाइयों से कहूंगा कि वे इतनी कठिन हिन्दी न लिखा करें, वे अपनी काबलियत अपने पास रखें, हमारे गले ऐसी हिन्दी न डालें।

श्री अध्यक्ष: यह तो आपका डिपार्टमेंट ही टाईप करता है (व्यवधान)

श्री लछमन सिंह: मैं उनका कहता हूँ, वे मानते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

चौधरी रिजक राम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को पढ़ने में बड़ी मुश्किल हो रही है, जो कुछ ये बोल रहे हैं इसका फायदा नहीं है। It should be taken as read and laid on the Table of the House.

श्री अध्यक्ष: थोड़ा सा रह गया है, इनको बोलने दें।

चौधरी रिजक राम: इसकी टेबल पर रख दें तो अच्छा रहेगा। (व्यवधान) नहीं तो पढाई के लिये शिक्षा केन्द्र यहां पर खोल दें (हंसी)

श्री लछमन सिंह : थोड़ा सा रहता है मैं पढ़ देता हूँ।

9. मोटर गाडी अधिनियम के अनुसार मोटर कार की कोई गति निर्धारित नहीं है परन्तु भारी गाडियों की अधिकतम गति निर्धारित है उच्च राष्ट्रीय मार्गों का ज्योमैट्रिक डिजाईन 100 कि०मी० प्रति घंटा की गति के लिये है तथापि अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी भी उच्च मार्ग पर अधिकतम गति सीमा निर्धारित की जा सकती है। सरकार मोटर गाडी अधिनियम के अधीन व्यवस्था तथा उच्च राष्ट्रीय मार्गों पर भीड़ तथा सुरक्षित यातायात की आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुये ओपन एरियाज (शहरों से बाहर का इलाका) में भी, मोटर कारों की गति सीमा नियत करने के प्रश्न पर विचार करेगी।

10. यातायात के अधीन और दुर्घटना वि लेशण करने के लिये सरकार एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग सैल की स्थापना के बारे में सक्रिय रूपसे से विचार कर रही है ताकि ट्रैफिक इंजीनियरिंग के साधन तथा सुरक्षित उच्च मार्ग यातायात के स्टैण्डर्ड बनाये जा सकें।

औचित्य प्र न

ग्रहण की गई ध्यानाकर्षण सूचना को वापस लेने सम्बन्धी

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न है। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने फरमाया कि सदन के एक माननीय सदस्य चौधरी हरस्वरूप बूरा का एक काल अटैन् इन मो इन एडमिट हुआ था जिस पर सरकार ने जवाब देना था, लेकिन चौधरी हरस्वरूप बूरा ने अपना काल अटैन् इन मो इन विदड्रा कर लिया है। इससिलिये सरकार का जवाब नहीं आयेगा। अध्यक्ष महोदय, ठीक है माननीय सदस्य का अधिकार है विदड्रा करने का लेकिन रूल 73 में साफ लिखा है कि कोई अत्याव यक महत्व का सवाल , पब्लिक इम्पोर्टेंस का प्र इन एडमिट हो, उसके आगे यह भी लिखा है कि एक ही दिन में दो एक जैसे प्रस्ताव आपके सामने आयें तों इन दोनों में से जिसको इम्पोर्टेंट समझा जाएगा, उसको एडमिट करेगे। इस प्रस्ताव के एडमिट होने पर पता नहीं कितने दूसरे प्रस्ताव सैकिफाईस हो गये होंगे। सब को छोड कर आपने श्री हरस्वरूप बूरा का प्रस्ताव एडमिट किया और

सदन में रखा गया। सदन में रखने के बाद माननीय सदस्य की प्रोपर्टी नहीं रही बल्कि वह सदन की प्रोपर्टी बन गई। मैं आपकी रूलिंग चाहती है कि कौन से रूल के तहत माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव विद्वान कर गये? ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत वे विद्वान कर सकते हैं और मेरी समझ के मुताबिक सरकार का जवाब आना चाहिये।

Mr. Speaker: I will examine this point.

चौधरी शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, सरदार लखमन सिंह जी ने हिन्दी पढ़ने का सफल प्रयास किया है, मैं उन्हें इस बात के लिये बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वे आगे भी हिन्दी पढ़ने का प्रयास करते रहेंगे।

वर्ष 1978-79 के लिये सरकारी आवासनों के बारे में समिति की दसवीं रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्ष: मੈਂबर साहिबान अब कमेटी आन गवर्नमेंट अ योरेंस के चेयरमेन कमेटी की रिपोर्ट पेश करेगें।

Shri K.L. Poswal (Chairman Committee on Government Assurances): Sir, I beg to present a typed copy of the Tenth Report (alongwith its Appedix) of the Committee on government Assurances of the Haryana Vidhan Sabha for the year 1978-79.

स्वामी आदित्यवेत: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कई बार हाउस में कहा है कि सदन की भाषा

हिन्दी और पंजाबी होगी लेकिन मेरे माननीय सदस्य श्री पोसवाल अंग्रेजी में रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, ये तो हिन्दी के बड़े अच्छे जानकार हैं इन्हें हिन्दी में बोलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: यह पवांयट आफ आर्डर नहीं हैं (व्यवधान) स्वामी जी, आपको बार बार इन्ट्रूट करना भाभा नहीं देता। (व्यवधान)

Shri Sumer Chand Bhatt: Mr. Speaker, the Chairman of the Committee on Government Assurances has neither read out the Report nor has he laid it on the Table of the House.

Mr. Speaker: He has presented the Report and it is laid on the Table of the House. अब हैल्थ मिनिस्टर सरकारी रेजोल्युशन पेश करेगी।

सरकारी प्रस्ताव

परिवार कल्याण उपायों द्वारा जनसंख्या को सीमित रखने सम्बन्धी

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डा० कमला वर्मा): मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन महसूस करता है कि हरियाणा की तेजी से बढ़ती जनसंख्या न केवल जनसाधारण का जीवन स्तर उंचा उठाने के मार्ग में एक बाधा है बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिये भी एक गम्भीर खतरा है। इसलिये यह सदन

परिवार कल्याण उपायों द्वारा जनसंख्या को सीमित रखने के लिये सरकार की नीति का समर्थन करता है। सदन यह भी प्रस्ताव करता है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्णतया ऐच्छिक आधार पर और एक व्यापक नीति जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसूति एवं बाल कल्याण, परिवार कल्याण तथा पोशाहार जैसे कार्यक्रम सम्मिलित हैं, के एक अभिन्न अंग के रूप में तीव्रता में कार्यान्वित किया जाये।

यह सदन यह भी महसूस करता है कि सरकार तथा सभी सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक संगठनों को परस्पर साहयोग करके आम लोगों को अपने हित में, अपने बच्चों के हित में और राष्ट्र के हित में परिवार को सीमित रखने के लिये इस कार्यक्रम को स्वेच्छा से अपनाने की प्रेरणा देनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या की वृद्धि एक विस्फोटक रूप धारण कर रही हैं ईसा के समय से पूर्व विश्व की आबादी में केवल मात्र दो परसैन्ट या एक परसैन्ट वृद्धि होती थी। उसके बाद विश्व की जनसंख्या के अन्दर पहले 100 वर्ष में 100 करोड़ के करीब वृद्धि हुई। उसके बाद तीस वर्षों में 100 करोड़ के करीब बढ़ोतरी हुई। वर्ष 1976 में यह जनसंख्या जब 400 करोड़ की सीमा पार कर गइ तो सारे विश्व के मानव को चिन्ता होने लगी। विकास मील देगों को विशासकर यह चिन्ता का एक कारण बन गई। आज वे जितना भी विकास करते हैं, जितना विकास मील कार्यों पर खर्च करते हैं उससे वे लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि

जनसंख्या की वृद्धि साथ-2 हो रही है। भारत के अनवर इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को चलाने के लिये भारत के सारे लोग चिन्तित हो गये। अध्यक्ष महोदय, इस वक्त भी हालत यह है कि ज्यादातर लोगों की आय का अधिकतम भाग केवल मात्र रोटी और कपड़े का खर्च हो जाता है वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य या अन्य किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के उपर खर्च नहीं कर सकते। भारतवर्ष का अगर हम सोचें तो इस समय हमारी 65 करोड़ की जनसंख्या है। और जनसंख्या की दृष्टि से वि. व. में दुसरे नम्बर पर हैं वि. व. की जनसंख्या के अनुपात के लिहाज से यह वि. व. की 15 प्रति. त जनसंख्या है। जबकि हमारी भूमि केवल 2.4 प्रति. त है। कहने का मतलब यह है कि एक वर्ष के अन्दर हमारी 1 करोड़ 25 लाख की जनसंख्या बढ़ रही है जो कि एक आस्ट्रेलिया के बराबर है या हरियाणा जैसे एक प्रान्त के बराबर हैं इस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये हमारे दे. त के स्वास्थ्य विभाग ने धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक अर्थात् सभी नेताओं को यह बात बताई और उनको वि. वास में लेकर यह ने. तलन मुवमेंट चलाने का फेसला किया। अधिक जनसंख्या से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है आज कृषि, भूमि वन, और मत्स्य आदि दिन प्रति दिन कम होती जा रही हैं। यही कारण है कि आज दे. त से गरीबी का कंलक मिट नहीं रहा है। आज 46 प्रति. त लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा को पार कर गये हैं। स्पीकर साहब, पिछली सरकार थी उसकी नीति गलत थी। मैं एक बात मान कर चलती हूँ कि गरीबी भगवान की देन नहीं है। यह मानव की योजना की

विफलता के कारण हुआ करती हैं यह पिछली सरकार की गलत नीतियां थी जिसने इस गरीबी की खाई को बढाकर रखा। अब मैं आपके सामने थोड़े से हरियाणा के तथ्य भी प्रस्तुत करती हूं। हरियाणा एक पावन भूमि है, यह वीरों की भूमि है। इसी भूमि की यमुना और सरस्वती नदियों के तटों पर बेदों की रचनायें रची गईं। हरियाणा की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र के अन्दर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश दिया था। इसी हरियाणा की पावन भूमि पर महाकवि सूरदास जैसे भगतों ने जन्म लिया था जिनकी महत्वपूर्ण रचनायें आज भी श्रद्धा के साथ पढी जाती हैं। लेकिन हरियाणा की अपनी समस्याएं भी हैं। हरियाणा 1966 के अन्दर पंजाब से अलग हुआ। भारत के नक्शे के उपर यह 22वां प्रान्त उभर कर हमारे सामने आया। उस वक्त इसकी आबादी केवल 86 लाख थी लेकिन 1971 के अन्दर यह बढ़ कर एक करोड़ हो गई और आज इसकी जनसंख्या एक करोड़ पच्चीस लाख के करीब है 32 लाख जनसंख्या केवल मात्र इन दस बारह बरसों में बढ़ गई। स्पीकर साहब, मैं यह मानकर चलती हूं कि हरियाणा के लोग बड़े परिश्रमी हैं। वे मेहनत करके समृद्ध एवं प्रगति मिल बनना चाहते हैं लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज से दो वर्ष पहले इनके उपर बड़े अत्याचार किये गये। आपातकालीन के तीन-चार वर्ष पूर्व से हमारे परिवार कल्याण का कार्यक्रम बड़ी सरलता के साथ रहता था लेकिन 1975-76 के अन्दर जब यहां पर तानाशाही मनोवृत्ति वाली सरकार थी तो संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम के तहत परिवार नियोजन के बारे में लोगों के साथ

और जबरदस्ती की गई। किसी बस में जाने वाले को नहीं छोड़ा गया और न ही ठेला लेकर जाने वाले मजदूर को छोड़ा गया। चाहे कोई भादी में जा रहा हो या गमी में जा रहा हो या अपने किसी सम्बन्धी के घर जा रहा हो सभी लोगों को बसों से उतार कर जबरदस्ती आपरे न किये गये। उससे हमारे इस कार्यक्रम को बहुत धक्का लगा। अध्यक्ष महोदय, जेल के अन्दर जब हम रेडियो सुना करते या समाचार पत्रों में समाचार पढ़ा करते तो ऐसा लगता था कि पांच सूत्री और बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत लोग बहुत सूखी हैं। लेकिन जेल से छूटने के बाद जब मैं एक गांव के अन्दर गई तो एक वृद्ध मेरे पास आया। वह करीब 65 वर्ष का था और उसकी पत्नी को मरे 20 वर्ष हो चुके थे। मैंने जब उनसे पूछा कि ताऊ टेढ़े टेढ़े कैसे चल रहे हो तो उसने कहा कि उसकी जबरदस्ती नसबन्दी की गई है। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विधवा औरत का देखा। उसका 17 वर्ष का एक पुत्र था। उसने मुझे आकर कहा कि वह बांझ होगई क्योंकि उसके 17 वर्ष के पुत्र की जबरदस्ती कर दी गई। अध्यक्ष महोदय इस तरह के एक या दो केस नहीं हजारों केस हैं। इन्होंने कोई कंवारा नहीं छोड़ा, बच्चा नहीं छोड़ा, विधवा नहीं छोड़ी और न कोई वृद्ध छोड़ा। उन्हीं दिनों अध्यक्ष महोदय बहुत दुखदाई घटनाएं भी घटीं। पीपली और नगीना में किस प्रकार का गोली कांड हुआ और उसका हमारे वीरों ने किस तरह से मुकाबला किया वह आप सबको मालूम है। मैं उस वक्त रोहतक जेल के अन्दर थी। हमने वहां सुना कि 7-8 बहिने जुडिण्डियल लौक-अप में आई है सिर्फ

इस कारण से कि उनहोंने उस समय की नौकराही हो हौसले के साथ मुकाबला किया था। स्पीकर साहब, उस वक्त की तानाशाह गवर्नमेंट ने दो साल तक लोगों के साथ बड़ी सख्ती कीथी। लोग डर के मारे ईख के खेतों के अन्दर सोते रहे लेकिन जनता ने इस सारे तजूबे का जवाब उस सरकार को यह दिया कि 32 वर्ष पुरानी कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। अध्यक्ष महोदय, जब से यह जनता सरकार आई है वह यह मान कर चलती है कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये प्रेरित करते हैं हमारे सारे हरियाणा के अन्दर 19 लाख योग्य जोड़े हैं। इनमें से 32.8 प्रतिशत ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम को अपना रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय स्तर अगर हम देखें तो यह 22.2 प्रतिशत है लेकिन हरियाणा में अधिक लोग इस कार्यक्रम को अपना रहे हैं। इस डेढ़ साल के अर्से में अध्यक्ष महोदय हमने 194 ओरियनटेशन कैंप्स लगाये हैं और 24 हैल्थ कैंम्पस लगाये हैं हम इन कैंम्पों को फैमली प्लानिंग के नाम से नहीं लगाते बल्कि हैल्थ कैंम्प के नाम से लगाते हैं कैंम्प में हमारा सर्जन आता है मैडिकल स्पेशलिस्ट जाता है और ये हर मां और बच्चों को अच्छी-पकार से चैक-अप करते हैं और चैक-अप करने के बाद सुझाव और औशधियां आदि देते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम यह मान कर चलते हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिये। देश की प्रगति इन्हीं के स्वास्थ्य के उपर निर्भर करती है। स्वस्थ बच्चा ही अच्छा किसान और मजदूर बन सकता है। स्वस्थ बच्चा ही शिक्षित हो करके अच्छा वकील, डाक्टर और इंजीनियर बन सकता है। स्वस्थ बच्चा ही प्रदेश

देश और वि व की अच्छी प्रकार से सेवा कर सकता है लेकिन बच्चे का स्वास्थ्य उसकी मां के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है स्पीकर साहब, मैं यह भी मान कर चलती हूं कि आज देा के अन्दर अनेकों नारियों का बहुत बच्चे पैदा करने के कारण दिन प्रति दिन स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है जब मातायें स्वस्थ नहीं तब स्वस्थ बच्चों का जन्म कैसे होगा और जब स्वस्थ बच्चें नहीं होंगे तब हमारे हरियाणा औरभारत देश की प्रगति कैसे होगी। इसलिये हमें यह सोच कर चलना पडेगा कि हम अपने हरियाणा की आबादी को नियंत्रित करने के लिये इस प्रकार के उपायें बरते। सरकार की और से तो इस बारे में हम कुछ करने की हम सोच रहे हे लेकिन आज मेरी प्रार्थना जितने हमारे सदन के विधायक है या जितने हमारे धार्मिक और सामाजिक नेता हे उन सबसे है कि ये सब मिलजुल कर इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये हमें सहयोग दें हमारे जितने विधायक है इनको चाहिये कि ये अपने हलके की पंचायतों के अन्दर जन सभाओं के माध्यम से लोगों को इसके बारे में समझांये। क्यंकि हम जनता के चुन` हुये प्रतिनिधि हैं हमने जो यह कार्यक्रम रखा हे, जो टारगेट हमें मिला है उसको हमें पूरा करना है।

(11.00 बजे) पिछले वर्ष जब सन 1977-78 में लोग डरे हुये थे तो स्वेच्छा से 5976 व्यक्तियों ने आप्रेंान करवाये। सन 1978-79 मे 11613 व्यक्तियों ने आप्रेंान करवाये। स्पीकर साहब आहिस्ता-2 परसैन्टेज बढ रही है लेकिन मेरी प्रार्थना है कि

सभी सदस्यगण को इसमें रुचि लेनी चाहिये। ये केवल हरियाणा का ही मसला नहीं है सारे देश का मसला है हमने 26-2-79 से एक और कार्यक्रम तैयार किया है कि जो जिला आप्रेशन के लिहाज से प्रथम आयेगा उसको एक लाख रूपा इनाम दिया जायेगा। जो जिला दूसरे नम्बर पर आयेगा उसको एक लाख रूपया इनाम दिया जायेगा। जो जिला दूसरे नम्बर पर आयेगा उसको 75 हजार और जो जिला तीसरे नम्बर पर आयेगा उसको पचास हजार रूपये इनाम के रूप में दिये जायेंगे। जो भी पैसा जिले को दिया जायेगा यह उसकी डिवैल्पमेंट के कार्यक्रम पर खर्च किया जायेगा। हर जिले के अन्दर पांच पंचायतों को चुना है कि जो भी पंचायत इस कार्यक्रम को लागू करके प्रथम स्थान पर रहेगी उसको 10 हजार रूपये इनाम के तौर पर दिये जायेंगे। जो पैसा दिया जायेगा वह पंचायतों के विकास कार्यक्रम पर खर्च किया जायेगा। इसलिये जो माननीय सदस्य बैठे हुये हैं वे इस कार्यक्रम को अपनाने में पूरा सहयोग देंगे। जो हमारे देश में और प्रदेश में समस्या उत्पन्न हो रही है इसमें अवश्य सहयोग देंगे।

Mr. Speaker: I must congratulate the Minister on a very clear and forceful introduction to the official resolution, though it was a bit long drawn out.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

“यह सदन महसूस करता है कि हरियाणा की तेजी से बढ़ती जनसंख्या न केवल जनसाधारण का जीवन स्तर उंचा उठाने

के मार्ग में एक बाधा है बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिये भी एक गम्भीर खतरा है इसलिये यह सदन परिवार कल्याण उपायों द्वारा जनसंख्या को सीमित रखने के लिये सरकार की नीति का समर्थन करता है। सदन यह भी प्रस्ताव करता है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्णतया ऐच्छिक आधार पर और एक व्यापक नीति, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसूति एवं बाल कल्याण, परिवार कल्याण तथा पोशाहार जैसे कार्यक्रम सम्मिलित हैं, के एक अभिन्न अंग के रूप में तीव्रता से कार्यान्वित किया जाये।

यह सदन यह भी महसूस करता है कि सरकार तथा सभी सामाजिक धार्मिक तथा राजनैतिक संगठनों को परस्पर सहयोग करके अन्य लोगों को अपने हित में, अपने बच्चों के हित में और राष्ट्र के हित में परिवार को सीमित रखने के लिये इस कार्यक्रम को स्वेच्छा से अपनाने की प्रेरणा देनी चाहिये।”

चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन के सम्मुख आया है। इस प्रस्ताव पर अमल करने की आज देश में बहुत ही आवश्यकता है बल्कि आज ही नहीं इसकी तो सदा से ही आवश्यकता रही है। हर घर को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये और परिवार का सही ढंग से पालन-पोषण के लिये इसको अपनाना अतयन्त आवश्यक है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुये) डिप्टी स्पीकर साहब, जिस देश की जनसंख्या बढ़ती जाती है वह देश कभी भी

सुखी नहीं हो सकता हरियाणा में एक कहावत है कि घना कुटम्ब महा दुखी। इसलिये कुटम्ब को छोटा रखना बहुत आवयक है।

डिप्टी स्पीकर साहब, बीस वर्षों से परिवार नियोजन का प्रचार किया जा रहा है लेकिन फिर भी आबादी दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है इस विषय में मेरा अपना विचार यह है कि परिवार की बढ़ौतरी में खान-पान भुद्ध और सात्विक भी रखना अत्यन्त आवयक है। जिस व्यक्ति का खान-पान ठीक होगा उसकी वृद्धि भी ठीक होगी, वह अपना भला भी चाहेगा और देश का भी भला चाहेगा परन्तु पिछले बीस वर्षों से ऐसा गलत प्रचार होता रहा है कि मुर्गा पालो, मछली पालो। डिप्टी स्पीकर साहब, इन को खाने से भारीर में सभी उत्तेजक तत्व बढ जाते है। अण्डे, मछलजी खाने से तो उत्तेजक तत्व बढ जाते है और सात्विक चीजों के प्रयोग से भुद्ध तत्व भारीर में आते है, यही ठीक बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कुछ खुल कर बोलना चाहता हूं, इस बारे में आपकी आज्ञा चाहता हूं, क्यांकि जो गलत प्रचार हो रहा है उसके विषय में बताना चाहता हूं। जंहा तक अन्डे का सम्बन्ध हे यह तो इतना उत्तेजक पदार्थ है कि यदि कोई भैंस हीट में न आये तो उसको दो अन्डे खिलौने से तीसरे दिन हीट में आकर बोलने लगती हैं जिन लड़कियों को छःछः अन्डे रोजाना खाने को मिलें तो क्या वे हीट में नहीं आयेगी? (हंसी) इसलिये खान-पान का बडा प्रभाव है यह हंसने की बात नहीं है। आप इस बात पर सोचिये, यह बिल्कुल सही बात है। कई लोग अन्डे के हक

में दलीलें देगें लेकिन अन्डे के मुकाबले में परमात्मा ने बहुत पोशक पदार्थ दिये हैं जिन से अपने विचार और भावनाओं को भादुद्ध रखा जा सकता है। इसलिये गलत प्रकार का प्रचार बन्द होना चाहिये।

पिछले दिनों पहली सरकार ने भाराब की दुकाने बढा दी थी। भाराब को सस्ता कर दिया था ताकि लोग खुब पीयें प्रचार किया जाता था कि "पीओ और जीओ" जो व्यक्ति भाराब पी लेगा क्या वह अपने परिवार की परवाह करेगा? वह तो पडोसियों की भी परवाह नहीं करेगा। भाराब बन्दी का हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो कार्यक्रम अपनाया है यह बहुत अच्छा है। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिये सरकार को काफी जोर लगाना चाहिये ताकि लोगों का कल्याण होसके।

इसी प्रकार अ लील और नंगे चित्रों की बात है। आप अखबारों में रिसालों में और फिल्म फेयर्ज में औरतों के नग्न चित्र देखते हैं इन सब पर पाबन्दी लगनी चाहिये। इस का बड़ा फर्क पडता है नौजवान लडके और लडकियों का तो कहना ही क्या अगर कोई साठ साल का व्यक्ति भी उन नग्न चित्रों को सीधी नजर से नहीं देखेगा तो तिरछी नजर करके जरूर देखेगा।

श्री उपाध्यक्ष: आपको दोमिनट ही मिलेगें। आप जल्दी समाप्त करे।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: सिनेमा में जाकर देखिये। जितने देश में कुकर्म फैले हुये है ये सब सिनेमा के कारण फैले हुये है। वैसे यह इन्डस्ट्री बहुत जरूरी है। इससे विद्या का बहुत ज्ञान दिया जा सकता है। जो ज्ञान दस साल में नहीं दिया जा सकता, वह सिनेमा में एक साल में दिया जा सकता है। अब तक इसका इस्तेमाल अच्छी शिक्षा के लिये नहीं किया गया है वह इस्तेमाल किया जाना चाहिये। सिनेमा में तो यह सिखाया जाता है कि नौजवान लडके ओर लडकियों को कैसे बिगाड़ा जा सकता है और किस तरह से वे लडके लडकियां अपने मां बाप की आंखों में धूल झोंक कर आवारा बन सकते है वहां परन चोरी डाके और कत्ल करने के सारे तरीके सिखाये जाते हैं इसलिये बहुत जरूरी है कि सिनेमा की तस्वीरों पर कन्ट्रोल किया जाए और केवल पैसा कमाने के लिये नहीं बलिक नौजवानों का चरित्र सुधारने के लिये उनका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सुधार हो सकता है इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आजकल गन्दे गानों का भी काफी रिवाज है। भाई बहन, बाप-बेटी बाप-बेटा साथ बैठे रहते है और इतने गन्दे गाने गाये जाते है कि दोनों को भार्म आती है। कुछ लोग कहते है कि अगर कोई गाना सुनना नहीं चाहता या सिनेमा नहीं देखना चाहता तो वह अपने घर में बैठा रह। लेकिन देखा गया है कि गलियों में या दुकान पर लोग लाउड स्पीकर लगा देते है और इतनी जोर से बजाते है कि काफी परे गानी होती है उन गानों में प्या और मुहब्बत की कहानी होती है और फिर जब कोई लडका लडकी भाादी कर लेता है तो जल्दी ही उनका न

उतर जाता है और तलाक पर नौबत आ जाती है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि गन्दे गानों के जो रिकार्ड है उनको बन्द कर देना चाहिये, उन पर सरकार का कोई कंट्रोल होना चाहिये। अब मैं सहि शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। लडके और लडकियों का इक्ठ्ठा पढना बहुत ही हानिकारक है। हमारे भास्त्रों में लिखा है ओर स्वामी दयानन्द ने भी लिखा है कि पांच साल से ज्यादा की अगर लडकी हो तो वह लडके के स्कूल में न जाये और जिस लडके पांच साल से ज्यादा उमर हो वह लडकियों के स्कूल में न जाये। लेनि यहां पर नौजवान लडके और नौजवान लडकियां कालिजों ओर स्कूलों में इक्ठ्ठे पढते है। वहां क्या होता है यह सब जानते है।

श्री उपाध्यक्ष: वर्मा जी आपका समय हो गया है। अब आप बैठिये।

चौधरी िव राम वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लडकियां नौकरी करती है उनको चाहिये कि वे अपने विभाग में ही नौकरी करें मतलब यह है कि जहां पर केवल लडकियां हो नौकरी करती हो वहां पर वे नौकरी करें। अगर अफसर पुरुश हो और उसके अधीन लडकी काम करे तो वहां बहुत भारी करप्शन फैलती है। यह बहुत आवयक है कि लडकियों को नौकरी दी जाए लेकिन वह लडकियों के विभाग में जैसे स्कूल में। यह नहीं होना चाहिये कि किसी दफतर में दस आदमी काम करते है और वहां पर एक या दो लडकी लगा दी

जाये तो वहां पर सारा काम खलत मलत कर दिया जाता है और वहां पर कोई काम नहीं होता। कुछ और ही होता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो संयुक्त परिवार की प्रथा थी वह बहुत अच्छी थी, उसमें आदमी कुछ भारमाता था। यहां तक भारमाता था कि एक नौजवान लडके की घर में जाने की हिम्मत नहीं थी। जूती निकाल कर और आहिस्ता-2 घर में जाता था और उसे डर रहता था कि कहीं किसी को जाने की आवाज न आ जाये और अन्धेरे में ही फिर वापिस आ जाता था। आज तो हालत यह है कि साठ साल का पुरुश है और साठ साल की स्त्री है लेकिन पंलग दोनों के साथ-2 लगे है। नौजवान लडका ओर नौजवान लडकी एक कमरे में घुसे हुये है और मां-बप बाहर घूम रहे है।

आज परिवार नियोजन या नसबन्दी की बड़ी चर्चा हो रही हैं। एक तफ तो लोगों का खान-पान इस तरह का है कि जिससे उत्तेजना बहुत होती है। और दूसरी तरफ आप कम बच्चे पैदा करने की बात करते हो। यह तो वही बात हुई कि एक तरफ तो आग लगा दी ओर दूसरी तरफ कहते हे कि जूते न पहनों एक तरफ तो हवाई जहाज से कांटे बिखेर रहे हो और फिर यह कह रहे हो कि उनसे किसी के पैर लहूलूहान न हों। उपाध्यक्ष महोदय, अगर बैल भी बदमाश करे तो उसको भी जबरदस्ती पकड कर बधिया कर देना पडता है। अगर आप भुद्ध वातावरण उत्पन्न करने का यत्न करो तो नसबन्दी करने की जरूरत ही नहीं पडेगी। मैं तो यह कहता हूं कि लोगों का आप खानपान भुद्ध कर दो, वातावरण

भुद्ध कर देा और फिर सक साल के बाद देखोगे कि परिवार नियोजन अपने आप हो रहा है। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अपने कर्तव्य को पहचानों और फिर उसके मुताबिक काम करो तभी देा का भला होगा। इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्रीमती भान्ति देवी (कैलाना): उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकारी रेजोल्युशन मेरी एक बहन की और से आया है मैं अपनी बहन को इसके लिये मुबारिकबाद देती हूं कि उनहोने बडे विस्तृत रूप मे बताया है कि फैमिली प्लानिंग के क्या लाभ है और क्या हानियां है और किस तरह से ऐमरजेंसी में यह कार्यक्रम पिछड गया थां उपाध्यक्ष महोद, फैमिली प्लानिंग के बिना कोई भी देा या प्रान्त तरक्की नहीं कर सकता है। अभी वर्मा जी कह रहे थे कि पहले अच्छी परम्परा थी लेकिन वर्मा जी को पता होगा कि उनके मित्रों के यहां कितने बच्चे है। यह ठीक है कि कुछ लोग पहलेवाली अच्छी परम्पराओं को निभाते होंगे, यह मैं मानती हूं और आज के युग में वे बातें निभानी भी चाहियें लेकिन परिवार नियोजन का बोझ अगर किसी ने इस देा के उपर लादा है तो पुरानी पीढी ने लादा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज का पढा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग बडा सतर्क है और भायद ही दो, तीन या चार बच्चों से ज्यादाकिसी के परिवार के सदस्य होंगे। हां जहां अभी पढा लिखा वर्ग नहीं है अनपढ है या पिछडा वर्ग है वह वास्तव मे हमारे लिये समस्या की बात है। इसका हमें समाधान

खोलना चाहिये मैं चाहूंगी और हमारी बहन जी ने भी बताया है कि स्वच्छ ढंग से परिवार नियोजन कापालन किया जाये। लेकिन वर्मा जी कह रहे थे कि इस लिये कडे कदम उठाने होंगे। मेरा कहना है कि कडे कदम से कोई फायदा नहीं। हमारे माननीय सदस्यों को लोगों को ऐज्यूकेट करना चाहिये। हमें लोगों को बताना चाहिये कि परिवार नियोजन से आपका और आप के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। महर्षि दयानन्द ने राष्ट्र को संदेश दिया था कि यदि हमें पुरुषों से अच्छा रहकर जीवन यापन करना है, सुन्दर जीवन बिताना है तो संयम करके जीवन बिताना होगा। संयम बड़ी अच्छी चीज है और यदि हम चाहें तो इसको बड़ी सुन्दरता से निभा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। मैं अपनी बहन जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विभाग के कर्मचारियों को हिदायतें जारी करें कि वे गांवों में जाकर लोगों को इक्ठठा करके संयम बाबत बतायें। वर्मा जी ने सिनेमा का जिक्र किया कि यह बात ठीक है कि सिनेमा का, टैलीविजन का और दूसरे कार्यक्रमों का प्रभाव कोई अच्छा नहीं पड़ता। हमारे बच्चे अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी विचारधारा रखें तो कोई संदेह नहीं कि हमारा देश काफी उन्नति कर सके। यहां पर सहिष्णुता की बात कही गई है। सहिष्णुता की बात आप सुन लजिये कि प्राइमरी स्कूल तो बच्चों और बच्चियों के अलग-2 है लेकिन हम देखते हैं कि हाई स्कूल और कॉलेज में सहिष्णुता है और वास्तव में उसमें काफी दोष है। लेकिन मैं तो कहती हू कि सहिष्णुता के उपर परिवार का बहुत बड़ा असर होता है। अगर एक अच्छे परिवार की लड़की है तो वह

हजारों आदमियों के बीच में से निश्कलंक निकल जायेगी और जिसने गड़बड़ करनी है उसको चाहे आप रस्सियों से बांधकर रखो तब भी वह गड़बड़ करेगी। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को धर्म शिक्षा की सुविधा दें। इसका बच्चों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा और हमारे बच्चे सुन्दर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इन भावों के साथ बहन जी ने जो रेजोलूशन पे किया है मैं उसका अनुमोदन करती हूँ।

श्री भले राम (बडोदा, अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने जो यह प्रस्ताव यहां पर रखा है यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है इसमें कोई भाक नहीं अतः मैं इसका समर्थन करता हूँ। वैसे यह समस्या हमारे देश के लिये बड़ी गम्भीर समस्या बनी हुई है। जिसका कोई न कोई हल होना बड़ा जरूरी है। उपध्यक्ष महोदय, गांवों में इस बारे में बड़ी बुरी हालत है। पांच-2 सात-सात बच्चे हरेक घर में हैं मैं आपको अपने ही गांव की बात बताता हूँ कि वहां पर एक रात में 10 मिनट में 5 बच्चे पैदा हुये(हंसी) इस तरह से यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इसके लिये रोकथाम की बड़ी ही आवश्यकता है मेरी बहन जी ने संयम रखने की बात कह है, मैं उनकी बात से सैन्ट परसैन्ट सहमत हूँ। लोगों में संयम होना ही चाहिये। लड़े लड़कियां को तड़क भड़क के कपड़े वगैरह नहीं पहनने चाहिये। आजकल होता यह है कि औरतें लडके और लडकियां दिन में दस-दस बार भडकीले कपड़े बदलते हैं। फिर आप ही बतायें कि

आदमी किस प्राकर से संयम रख सकता है उपाध्यक्ष महोदय, पहले छोटी उमर में ही भादी कर दी जाती थी लेकिन आज हमारी सरकार ने उस बुरी प्रथा को खत्म करने के लिये कानून बना दिया है कि 18 और 25 साल की उमर में ही भादी होनी चाहिये। मैं तो इस विचार का हूँ कि 30-35 साल से पहले भादी नहीं होनी चाहिये। अगर इस उमर में जाकर भादी की जाएगी तो इसका हमारी बढ़ती हुई आबादी पर बहुत असर पड़ेगा और कम बच्चे पैदा होंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि स्कूलों में कम से कम धार्मिक शिक्षा जरूर दी जानी चाहिये जिससे बच्चों का चरित्र उंचा रहे।

श्री उपाध्यक्ष: भले राम जी, आप दोमिनट में ही खतम कीजिये।

श्री भलेराम: उपाध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट में ही खतम करूंगा मेरी आने सभी भाइयों से और अपनी सरकार से यह प्रार्थना है कि हम इस बात का खुब प्रचार करे कि लोग फैमिली प्लानिंग का पालन करे। आम पब्लिक की जब कभी भी मीटिंग हो, उस वक्त इस बात के लिये लोगों को समझाया जाये। पिछली सरकार की तरह यह काम जबरदस्ती न किया जाये। अगर लोगों की समझ में यह बात आ जायेगी कि छोटा कुटूम्ब उनके फायदे की चीज है तो लोग खुद ही से अपनी नसबन्दी करवाएंगे और सरकार की नीति भी कामयाब होगी। अन्त में मैं फिर इस प्रस्ताव

का समर्थन करता हुआ आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी भाकरूल्ला (फिरोजपुर झिरका): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी इस सदन में मेरी बहन जी ने जो यह प्रस्ताव पे किया है मैं उसका विरोध करता हूँ। पहली सरकार ने भी इस जैसा एक प्रोग्राम बनाया था ओर अब इस सरकार ने भी वैसा ही प्रोग्राम बनाया है। पहली सरकार ने उस वक्त कहा था कि जो नसबन्दी करवायेगा उसको इनाम दियाजायेयगा और उन्होने उंगली पकडी और कन्धे तक जा पहुंचे। मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्होने कहा कुछ, किया कुछ और लोगों को गूमराह करने का पूरा प्रयास किया, जिसके कारण लोगों को बडी बडी मुसीबतों का सामना करना पडा।

डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता ही है कि हमारे मेवात के इलाके में किस प्रकार से लोगों पर जुल्म ढाये गये ओर किस प्रकार लोगों को जबरदस्ती पकड़-पकड़ कर नसबन्दी के लिये ले जाया गया। अब हमारी सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि जो अपनी मर्जी से करवाना चाहेगा उसका ही आप्रे न किया जायेगा। लेकिन मुझे डर है कि बाद में कही ऐसा न हो कि पिछली सरकार जैसा रवैया ही बना लिया जाये ओर लोगों को घरों से खीच-खींच कर आपरे न कर दिये जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, मेवात के अन्दर यह हुआकि जो 15-15 साल के बच्चे ही थे जिनकी अभी भादियां भी नहीं हुई थी, ऐसे बच्चो को घरों से

खींच-खींच कर, बसों से उतार-2 कर आपरे तन कर दिये गये, कितनी भार्म की बात थी। इसलिये आज भी लोगों के दिलो दिमाग मे यही बातें समाई हुई है कि यह सरकार भी वैसा ही तरीका अपनाना चाहती है, इसलिये मैं इस प्रस्ताव का जोर के साथ विरोध करता हूँ।

चौधरी रिजक राम (राई): डिप्टी स्पीकर साहब, जो प्रस्ताव हमारी स्वास्थ्य मंत्री महोदय, बहन कमला वर्मा जी ने इस सदन के सामने रखा है वह बहुत आव यकम है लेकिन यह भी हमें मानना चाहिये कि यह एक बडी गम्भीर, जटिल समस्या हैं इसको आसानी से सफल बनाना कोई आसान काम नहीं है। आगे कुछ कहने से पहले मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि श्री राजनारायण जी से संजय गांधी की कल मुलाकात हुई है उसको देखते हुये कही लोग ऐा महसूस न करने लग जाये कि जो प्रोग्राम पहले सरकार के वक्त में एमरजेंसी के दौरान लागू था, वह दोबारा लागू करने का प्रोग्राम चालू न हो जायें इन बातो की तरफ भी हमारी सरकार को अव य ध्यान देना चाहिये। ऐसा सं ाय लोगों के दिलों के अन्दर है कि यह सरकार भी कहीं पिछली सरकार की तरह इस काम के लिये टारगैट फिक्स न कर दे। पिछली सरकार ने हर जिले में नसबन्दी के लिये टारगैट फिक्स कर रखा था, जिसके कारण वहां पर जयादतियों, ऐक्सैसिज होती रही ओर जिसके बारे मे इस सदन में भी चर्चा हुई। टारगैट फिक्स करना यह एक गलत तरीका है ओर न ही इस काम के

लिये कोट इनाम होना चाहिये क्योकि पिछली सरकार के वक्त में पंचायतों में भी इनाम रखे गये थे ओर अफसरों को भी इसके लिये इनाम दिये जाते थे और कहा जाता था कि जो नसबन्दी की फिगर्ज सबसे ज्यादा देगा उनको इनाम दियाजायेगा। इसका यह हसर हुआ कि बडे बडे अफसर अपने टारगैट को अचीव करने के लिये लोगों की नसन्दियां करवाते थे और इनाम हासिल करते थे। इसी कारण हर जगह पर ऐक्सैसिज हुई और जिन अुसरों ने नगीना और पिपली में नसबन्दियों के कारण ऐक्सैसिज की थी, उनको भार्मा ओर भाह कमि न द्वारा दोशी पाया गयाथा और वह अफसर फिरससस्पेंड किये गये थे मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी बात दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिये। इसलिये टारगैट को फिक्स करना ही एक किस्म की ज्यादाती है। इस प्रोग्राम में किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती या टारगैट फिक्स करने वाली बात नहीं होनी चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर सहि ाक्षा का जिक्र किया गय और कहा गया कि जहां लडके और लडकियां इकट्ठी पढते है, अच्छी पो ाक पहनते है, गन्दे गाने सुनते है वहां फ़ैमिली प्लाजिग लागू करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब मैं इस बात को नहीं मानता कि अगर इस तरकह से काम चला रहा तो हो सकता है कि परिवार नियोजन के कार्य में बाधा आये। आप दूसरे दे ां में जाये जो आप दइखेंगे कि वे लोग अच्छा खाते है, पीते है और अच्छी पो ाकें डालते है

लडके लडकियां इकट्ठे पढते है , फिर भी उनकी आबादी को देखें बढती ही नहीं है। जर्मनी और स्विटजरलैण्ड मे जाकर देखें वहां पर डैथ रेअ ओर बर्थ रेट एक समान है क्योंकि वहां पर गरीब लोगों के कलये एन्टरटेनमेंट के पूरे साधन उपलब्ध है और उन लोगों का इस तरफ ध्या नही नहीं जाता कि ज्यादा बच्चे पैदा किये जायें

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी साहब, आप दो मिनट मे वाइंड अप करें

चौधरी रिजक राम: टाईम न हो तो खत्म कर देता हूं जी। वैसे मैं तो अभी ही बोलने के लिये खडा हुआ हूं। डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं अपनी बहन जी से केवल यही प्रार्थना करुंगा कि हमारे देा में लोगों के पास एन्टरटेन्मेंट के लिये कोई साधन नहीं है और किसी भी देा मे तब तक परिवार नियोजन में कामयाबी नही हो सकती जब तक कि वहां गरीबी को दूर न किया जाये। आपको पता ही है कि यहां पर 50-51 परसेन्ट लोग एक कुनबे के एक ही कोठडी में अपना निर्वाह करते है और उने पास कोई और एन्टरटेनमेंट का साधन नहीं। एक पति ओरपत्नी को जो एक ही छोटे कमरे मे सोयेगे उनके पास सिवाये बच्चे पैदा करने के लिये और कोई काम नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह मानी हुई बात है कि जितने अमीर लोग होंगे उतने ही बच्चे कम होंगे और जितने गरीब लोग उनके बच्चे ज्यादा होंगे क्योंकि अमीर लोगों के पास एन्टरटेनमेंट के और भी बहुत साधन होते है और गरीब

आदमी का स्टैण्डर्ड आफ लिविंग ऐसा ही है कि उसे सिवाये बच्चे पैदा करने के कोई और काम नहीं होता। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी आपके द्वारा सरकार से यह रिकवैस्ट है कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा ताकत लगा सकते हैं, वह इस तरफ लगायें जिस से लोगों का स्टैण्डर्ड आफ लिविंग उंचा हो और उनको इस बात का अपने आप ही ज्ञान हो कि फैमिली प्लानिंग आवयक हैं डिप्टी स्पीकर साहब, समय ज्यादा नहीं है इसलिये मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे वर्मा साहब ने कहा और मैं भी मानता हूँ कि हमारे देश के कुछ रीति रिवाज हैं उनको भी ध्यान में रखा जायें जैसे पहले संयुक्त परिवार होता था और सभी मैनबर एक ही परिवार में इकट्ठे रहते थे लेकिन आज लड़का भादी होते ही अलग हो जाता है। पहले हमारे कुछ रीति रिवाज थे कि जब लड़की के बच्चा पैदा होना हो तो वह अपने मां बाप के घर चली जाती थी और साल भर के बाद छुछक लेकर आती थी। वे रिवाज अब टुट गए हैं। आज जवान लड़के और लड़कियां भादी होते ही माता पिता से अलग हो जाते हैं। एक बात और है कि आज परिवार नियोजन आप्रेशन के द्वारा किया जाता है ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पहले अपने उपर संयम रखकर परिवार नियोजन किया जाता था। उपाध्यक्ष महोदय जब तक स्टैण्डर्ड आफ लिविंग नहीं बढ़ाया जाता तब तक आबादी पर कन्ट्रोल नहीं हो सकता। मैं एक छोटी सी बात कह कर खत्म करता हूँ। पहले हमारे एक मंत्री महोदय हुआ करती थी। उन्होंने परिवार नियोजन की मुहिम बड़े जोर से चलाई और कहा कि कम से कम बच्चे पैदा

करने चाहिए। लेकिन कुदरत की महिमा अलग ही होती है। उसी मिनिस्टर साहिबा के एक साथ दो पैदा गए इसलिए कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं। पहले बच्चे औरत पैदा करती थी लेकिन अब चिट्ठियों के द्वारा बच्चे पैदा होने लग गए हैं। पति तो विलायत में बैठा है और पत्नी यहां पर है लेकिन फिर भी बच्चा पैदा हो रहा है। भायद साईस जहां तरक्की कर जाये कि बगैर पत्र के भी बच्चे पैदा होने लग जायें। इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष ; प्र न है कि ;—

यह सदन महसूस करता है कि हरियाणा की तेजी से बढ़ती जनसंख्या न केवल जनसाधारण का जीवन स्तर राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए भी एक गम्भीर खतरा है। इसलिए यह सदन परिवार क्लायण उपायों द्वारा जनसंख्या को सीमित रखने के लिए सरकार की नीति का समर्थन करता है। सदन यह भी प्रस्ताव करता है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्णतया ऐच्छिक आधार पर और एक व्यापक नीति, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसूति एवं बाल कल्याण, परिवार कल्याण तथा पोशाहार जैसे कार्यक्रम सम्मिलित हैं, के एक अभिन्न अंग के रूप में तीव्रता से कार्यान्वित किया जाए।

यह सदन यह भी महसूस करता है कि सरकार तथा सभी सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक संगठनों को परस्पर

सहयोग करके आम लोगों को अपने हित में, अपने बच्चों के हित में और राष्ट्र के हित में परिवार को सीमित रखने के लिए इस कार्यक्रम को स्वेच्छा से अपनाने की प्रेरणा देनी चाहिए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चौधरी संत कंवर:.....

श्री मांगे राम गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहब, बहिन जी की तरफ से जो प्रस्ताव आया वह बहुत जरूरी प्रस्ताव था। जब हाउस इस चीज को चाहता है कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो जाये और जब आप हमें इसमें शामिल करना चाहते हैं तो आप हमें बोलने का तो मौका दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: अब यह प्रस्ताव पास हो चुका है, आप मैजिकल की डिमांड पर बोल लेना।

वित्त मंत्री(श्री मूल चंद जैन): डिप्टी स्पीकर साहब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो एजेंडा आज के कार्यक्रम में शामिल किया गया है इस पर बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने विचार किया है। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में अपोजि उन के भाई भी थे और इधर के भाई भी शामिल थे। कमेटी ने इस प्रस्ताव के लिए एक घंटा मुकर्र किया था ओर कल जब कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी गई थी तो किसी ने भी एतराज नहीं किया था। अगर किसी को एतराज था तो वह कल एतराज कर सकता था। कल हाउस

ने कमेटी कीरिकमैंडे इन को सर्वसम्मति से पास किया था इसलिए अब इस पर ऐतराज करना मुनासिब नहीं है।

चौधरी संत कंवर: एमरजैंसी में भी लोगों को इसी तरीके से कह कर खराब किया गया था जैसे आप कह रहे हैं। ऐसा कहकर आप पार्टी को खराब कर रहे हैं। (गोर)

श्री मूलचंद जैन: मैं अपने नौजवान साथी संत कंवर को कहना चाहता हूं कि वे पार्टी का ठेका अपने ऊपर न लें। (गोर)

चौधरी संत कंवर: यह जरूरी नहीं कि इस पर कल ही ऐतराज होना चाहिए था। हम आज भी ऐतराज कर सकते हैं और कल भी कर सकते थे।.....(गोर)

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहब, अगर मैम्बर साहब, अगर मैम्बर साहिबान इस प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं तो आप और टाईम दे दें और उसके बाद में डिमांडज को ले लेना।

श्री उपाध्यक्ष: वह प्रस्ताव अब पास हो चुका है। जो मैम्बर साहिबान बोलना चाहें वे डिमांडज पर बोल सकते हैं। इसी विषय पर एक डिमांड आ रही है।

श्री मूल चंद जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यहां पर बहस करने से फ़ैमिलि प्लानिंग का काम पूरा हो जाएगा तो वे गलतफहमी में हैं। यह काम तो मेहनत से पूरा होगा।

चौधरी संत कंवर: यह काम पूरा तब होगा जब वजीर और एम० एल० एज० पहले आप्रेंशन करवाएंगे। वरना जैसे पहले बनारसी दास के टाईम गोलियां चली थीं वैसे ही गोलियां चलेगी।

श्री मांगे राम गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहब, हाउस में एक प्रस्ताव आया था और हमारी बात सुने बगैर आपने उसे पास कर दिया। तो जब हमें बोलने का मौका ही नहीं मिला तो हमारा पक्ष लेने के क्या जरूरत है (गोर)

वर्ष 1979-80 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री उपाध्यक्ष: गुप्ता जी, आप डिमांड पर बोल लेना। अब 1979-80 के बजट की ग्रांट्स पर बहस और मतदान होगा। पहले प्रैक्टिस के मुताबिक तथा सदन का समय बचाने के लिये जितनी डिमांडज आर्डर पेपर पर रखी गई है वे सब डिमांडज एक साथ पढ़ी तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्य किसी भी डिमांडज पर डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन डिमांड पर बोलने से पहले उस डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं। जिन कट मोडिफिकेशन का नोटिस आया है वे भी एक साथ पढ़ी तथा मूव की गई समझी जाएगी। उसके बाद कट मोडिफिकेशन पर और डिमांडज पर वोटिंग होगी।

That a sum not exceeding Rs. 33,19,21,550 be granted to the Governor to defray the charges that will come in

the course of payment for the year 1979-80 in respect of the charges under Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 1,23,37,45,015 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1979-80 in respect of the charges under Demand No. 15-Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 30,66,14,960 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1979-80 in respect of the charges under Demand No. 1-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 6,95,86,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1979-80 in respect of the charges under Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 6,82,43,965 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1979-80 in respect of the charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 8,15,24,990 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1979-80 in respect of the charges under Demand No. 22-Co-operation.

Demand No. 15		
1	Shri Surrender Singh	That Demand No. 15 of Rs.

2	Shri Shamsher Singh	1,23,45,015/- on account of Irrigation be reduced by Re. 1/-
Demand No. 17		
3	Shri Shamsher Singh	That Demand No. 17 of Rs. 30,66,14,960/- on account of
4	Shri Surrender Singh	Agriculture be reduced by Re. 1/-
Demand No. 22		
5	Shri Surrender Singh	That Demand No. 22 of Rs. 8,15,24,990/- on account of
6	Shri Shamsher Singh	Co-operation be reduced by Re. 1/-

चौधरी संत कंवर(हसनगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, में डिमांड नं0 15 पर सब से पहले बोलना चाहता हूं। डिमांड नं0 15 के बजट में इरीगे ान के लिये जो प्रावधान किया गया है इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना रूपया पहले की सरकार ने इरीगे ान के लिये कभी नहीं रखा। यह बात वास्तव में सरकार की बड़ाई करने के काबिल है। लेकिन इसमें दो तीन बातें है जो

देखने वाली है। पहली बात यह है कि यह जो इरीगे इन डिपार्टमेंट को सारे का सारा रूपया दिया गया है यह रूपया ठीक तरह से खर्च होता है या नहीं? डिप्टी स्पीकर साहब, आज हालत यह है कि इरीगे इन डिपार्टमेंट में इतने गलत तरीके अपनाये जाते हैं और रूपये का मिसयूज इतना किया जा रहा है। कि भायद ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इतना मिसयूज किया जाता हो। यहां पर ठेकेदारों से परसेंटेज बंधी हुई है। यह आम बात है कि कम से कम दस प्रति शत कमि इन दिय बगैर कोई ठेकेदार अपना काम नहीं चला सकता। जब मैंने यह बात कही तो हमारे एक बड़े अफसर साहिबान इस मामले में एतराज कर रहे थे। हमने ऐस्टीमेटस कमेटी में भी कहा था कि आप आज ही हमारे साथ चलिए, वजीर साहब से भी कहा जो यहां बैठे हुए हैं आपको सीमेंट मिल सकता है। जबकि सीमेंट की हालत यह है कि न सीमेंट मिल से मिलता है और न डिपो से मिलता है। परन्तु जहां गवर्नमेंट का काम चल रहा है वहां से आप को जितना चाहे सीमेंट मिल सकता है। जो रूप्य इरीगे इन को जा रहे हैं वह नहीं हो सकता। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। हमारे सिंचाई मंत्री जी ने पिछले साल एक सवाल के जवाब में गांधारा पाकस्मा ड्रेज के बारे में कहा था कि इनको जल्दी पूरा कर लिया जायेगा लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। अब की बार भी सरकार ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि जो काम बचा है 1980-81 में पूरा हो जायेगा। दूसरी मोटी बात हरियाणा को कसम दिलाने की बात है कि जो 50 करोड़ रूपये के करीब एस0वाई0एल0 पर खर्च किया गया है

वह बेकार हो जायेगा, अगर हरियाणा ने पूरे तरीके से लड़ाई करके जल्दी से जल्दी पंजाब से पानी न लिया। डिप्टी स्पीकर साहब, आज हालात यह है कि जितनी जगहों पर पहले लाइनिंग हुई थी वे टूट गई है, दरारें पड़ गई है, जब तक यह पानी नहीं चलेगा इस नहर पर लगा हुआ रूपया सारा खराब हो जायेगा, इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी पानी लाने की कोशिश करे। हमारे यहां एक कहावत है कि दबाव के बिला बणी का मोर भी नहीं बोलता। जब तक हरियाणा सरकार पानी के लिये दबाव नहीं डालेगी तब तक पानी नहीं मिलेगा। चौधरी सुरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह जीने भी कहा था कि पानी के बिना लोगों को नुकसान हो रहा है। इसके लिए जो तरीका हमें नहीं अपनाना चाहिए, वह भी अपनाना चाहिए ताकि पानी मिल सके। अगर हम पानी के लिए नहीं कहते है तो हमें पानी पंजाब नहीं देगा। आप पंजाब का दिल्ली जाना रोक दीजिए। वह दिल्ली के बगैर नहीं रह सकता और हम पानी के बगैर नहीं रक सकते। हमें पानी चाहिए, पंजाब को रास्ता चाहिए, दिल्ली को और कोई रास्ता जाता नहीं। जब तक वे हमें पानी नहीं दे देते उनको इस रास्ते से न जाने दिया जाये। हम मानते है कि पंजाब भी हमारा भाई है, हमारा दोस्त है लेकिन अगर घर में दो भाई है, चाहे वे सगे एक ही मां बाप से हों उनकी जरूरत के अनुसार बराबर का बंटवारा किया जाता है। इसमें भार्म की क्या बात है? हरियाणा का हक बनता है उसको मिलना चाहिए। पंजाब से हमें अपना हक दबा कर लेना चाहिए। अगर हम पंजाब को दूसरी स्टेटस में जाने के लिये हक देते है,

रास्ता देते हैं, तो उनको भी हमारा हक देना चाहिए। पंजाब का हक जो रास्ते पर बनता है वह बंद कर देना चाहिए। यह भविष्यवाणी तो नहीं है परन्तु भविष्यवाणी सिद्ध होगी कि अगर पंजाब को इस रास्ते से नहीं जाने दिया जायेगा तो वह हरियाणा को पानी दे देगा। डिप्टी स्पीकर साहब अगर पंजाब हरियाणा को पानी नहीं देता तो यह झगड़ा बहुत दूर तक जायेगा। इस झगड़े में अगर सरकार नहीं जायेगी तो गांवों के लोग, जो टैक्स देते हैं जिनके खेतों को नहरी पानी मिलना चाहिए वे पानी के लिए बिलखने लगेंगे वे इस झगड़े में जायेंगे क्योंकि उनको पानी की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि इस मामले को जल्दी से जल्दी प्रांतीय स्तर तक उठाये। अब मैं इरीगे टन के अफसरों के बारे में कहना चाहता हूँ। इरीगे टन के अफसरों में करप् टन बहुत बढ़ गई है वे दस प्रति टन लेते हैं लेकिन यह बात नहीं है कि सभी करप् ट हैं। किसी-किसी डिपार्टमेंट में ऐसे भी अफसर होते हैं जो ईमानदार होते हैं। वे अपनी जेब से भी घर से भी पैसा खर्च कर देते हैं, नाजायज पैसा नहीं कमाते। लेकिन जब ज्यादातर करप् ट आफिसर हों तो उनको देखते हुए यह हो जाता है कि सभी अफसर करप् ट कहलाते हैं। एक्स0ई0एन0 का 1947 के अंदर 1275 रूपए का ग्रेड था, अब 1978 में दो प्रति टन बढ़ाकर 1300 रूपए हुआ है, यह 25 साल में हुआ है। इसके साथ एस0डी0ओ0 (सिविल) का पहले 850 रूपये का ग्रेड था जो अब 1300 रूपए कर दिया गया है उनका ग्रेड 53 प्रति टन बढ़ाया गया है 25 साल में 1300 रूपए। इसी तरह चीफ सैक्रेटरी का 2250 रूपये से बढ़ाकर

3500 रूपए 55 प्रति त बढा दिया है, कमि नर का 2000 रूपए से 2750 रूपए 37 प्रति त बढा दिया गया है, आई0जी0 का 22 प्रति त, डायरैक्टर हैल्थ सर्विसिज का 42 प्रति त, एस0ई0 का 14 प्रति त, डी0आई0जी0 का 36 प्रति त, डी0 सी0 का 25 प्रति त बढा दिया गया है। लेकिन किसी एम0एल0ए0 का नहीं बढाया है। दूसरे डिपार्टमेंट में भी ग्रेड बढाये गये है। फिर एक्स0ई0एन0 को ही क्यों अलग रखा गया है? इनका भी इसी रे गों से ग्रेड बढाना चाहिए था, एक ही डिपार्टमेंट में इतना फर्क क्यों रखा गया है? उनको भी इतनी सहूलियतें देनी चाहिए। उनको दूसरे लोगों के बराबर रखा जाये। डिप्टी कमी नर और एस0डी0ओ0 को हजारों लोगों की ए0सी0आर0 लिखने का हक मिल जाता है। एक एसी0डी0ओ0 जो ट्रेनिंग लेकर आता है एक साल के बाद ही लाखों लोगों के ऊपर मालिक की तरह हो जाता है। डिप्टी कमी नर जो कालेज के बाद आई0ए0एस0 बन जाता है वह मालिक बन जाता है, वह बड़ा अफसर हो जाता है। उसे तमाम फायदे मिलते है। वह मामूली बी0ए0 पास होता है और पूरे जिले का मालिक बन जाता है। कोई उसे सलाह दे चाहे वह पब्लिक का आदमी हो या कोई एम0एल0 हो, वह किसी की सलाह मानने को तैयार नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात को छोटा करें।

चौधरी संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि सभी अफसरों की बराबर बढौतरी होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर

साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो ऐक्सीयन है उनकी भी एस0डी0ओ0 (सिविल) के बराबर बढ़ौतरी होनी चाहिए। इसी तरीके से मैं डिमांड नम्बर 17 जोकि एग्रीक्लचर के लिये है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। एग्रीक्लचर के लिए जो रूपया खर्च होता है उस रूपए का गलत तरीके से मिसयूज होता है। किसानों को खेती के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उनके लिये वहीं चीज मंहगी होती है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी ने अम्बाला के पास एग्रो टाईप का कारखाना लगाया है जिसका एक मंत्री उद्घाटन करके आए थे। मैं वित्त मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि उस आदमी पर पंजाब और यू0पी0 में कोई मुकदमा चल रहा है। वह आदमी हरियाणा एग्रों इंडस्ट्रिज कारपोरे इन की खाद का सप्लायर होता था। पिछले दिनों एग्रों इंडस्ट्रिज कारपोरे इन ने उसकी सिक्योरिटी जब्त की है क्योंकि उस आदमी पर मिट्टी और राख मिला कर गलत किस्म का खाद बेचने का आरोप है। जब उस आदमी पर यह आरोप है तो पता नहीं सरकार ने किस तरीके से उसको कारखाने लगाने की मंजूरी दे दी। डिप्टी स्पीकर साहब, उस आदमी ने एग्रों इंडस्ट्रिज से मिलते जुलते नाम का कारखाना बनाने की स्कीम बनाई है। यह कारखाना अभी तक लगाया नहीं है बल्कि सरकार उसकी नींव रख रही है। हरियाणा सरकार ने उस आदमी को दस हजार टन खाद अलाट कर दिया था। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि वह सारा खाद गलत तरीके से

पंजाब के अंदर ब्लैक में बेचा गया। डिप्टी स्पीकर साहब, यह हमारी सरकार इस किरम के काम करती है तो क्या यह अफसोस करने के लायक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप वांडुड अप कीजिए।

चौधरी संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले दिनों ओले पड़े और बाढ़ आई उसके के लिए जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को तीन सौ रूपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया है। मैं इस बात के लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। यह बहुत ही सराहनीय कदम है इसमें कोई दो राय नहीं पिछली सरकार ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया था। इतना ज्यादा मुआवजा देने की बात किसी भी सरकार के लिए एक रास्ता बनेगी चाहे वह कोई भी सरकार क्यों न हो। इसके साथ साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन गांवों में ओले पड़े हैं उन गांवों के रोजगार भी मारे गये हैं। उन गांवों के हरिजन जो फसल की कटाई करके थोड़ा बहुत अनाज इक्ठठा कर लिया करते थे वह उससे वंचित रह गए हैं इसलिए जिन गांवों में फसल कटाई के लिए नहीं रही है तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उन गांवों के हरिजनों को राहत मिल सके। इन भाबदों के साथ मे। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री सुमेर चंद भट्ट(नग्गल): डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपके जरिए यह कहना चाहता हूँ कि जो मांगे हाउस के सामने

है उनका कुल अमाउंट 209 करोड़ 16 लाख 36 हजार 980 रूपए बनता है और तादाद में यह 6 मांगे हैं। 11.30 बजे इन मांगों पर बहस शुरू हुई है और एक बजे हाउस का समय समाप्त हो जाएगा और इससे पहले हमारे वित्त मंत्री जी बहस का जवाब भी देंगे। मेरा कहना यह है कि ऐसा टाईम फिक्स करें जिससे मैम्बरों को बोलने का टाईम पूरा मिले। अगर मंत्री जी के लिए टाईम छोड़ भी दिया जाए तो कुल 90 मिनट इस पर बोलने के लिये रखे हैं। हाउस में 90 मैम्बर हैं तो एक मैम्बर को बोलने के लिए मुक्ति कल से एक मिनट मिलता है

श्री उपाध्यक्ष: आप डिमांड पर बोलिए।

श्री सुमेर चंद भट्ट: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड पर बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ। मेरी तो अर्ज यह है कि एक मैम्बर को एक मिनट में 6 मांगों पर बोलना है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक मैम्बर सिर्फ दस सैकिंड एक मांग के बारे में बोल सकता है। यदि 209 करोड़ रूपए की मांगें हो और एक मैम्बर को 6 मांगों पर बोलने के लिए एक मिनट दिया जाए तो यह कामकाज करने का क्या तरीका है? डिप्टी स्पीकर साहब इस हाउस को फाइनैस करने के लिए और इसका कामकाज चलाने के लिये हरियाणा की जनता 36 से 40 लाख रूपये साल में खर्च करती है। वह इसलिये करती है कि बजट मैम्बर्ज के सामने आए और मैम्बर्ज उसके लिए अपनी राय दे सकें और उनकी राय के मुताबिक उसमें कुछ तरमीम की जा सके लेकिन बड़े अफसोस की

बात है कि हमने कुछ ऐसा मार्ग अपना लिया है जिसकी वजह से सदस्य पूरी तरह से अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते।

वित्त मंत्री(श्री मूल चंद जैन): डिप्टी स्पीकर साहब, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने इन सारे मामलों पर विचार करके टाईम टेबल मुकर्रर किया था कि चार दिन बजट पर चाहे कोई सदस्य किसी भी विशय पर बोलें और तीन दिन डिमांडज के लिये मुकर्रर किए। आज भी डिमांड पर बोल रहे हैं और 26 तथा 27 को भी कुछ डिमांडज होगी। उस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को सारे हाउस ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है जो कोई भी सदस्य खड़ा होकर बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के विरुद्ध कोई बात कहे तो यह मुनासिब नहीं है। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में न रखना इसके लिए मैं तो आपकी रूलिंग यह चाहता हूँ कि किसी भी मैम्बर को इस किस्म की बातों का मौका न दिया जाए।

श्री सुमेर चंद भट्ट: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि कुछ अर्से से ऐसा दिखाई दे रहा है कि ज्यों ही बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आती है स्पीकर साहब उसको पढ़ देते हैं और मैम्बर तक उसकी कापी पहुच भी नहीं पाती और वह मंजूर भी कर ली जाती है। मैम्बर को बोलने का मौका नहीं मिलता कि उस रिपोर्ट में है क्या। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस कार्य पद्धति को बदला जाये।

डा0 बृजमोहन गुप्ता(जगाधरी): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 10 के बारे में कहना चाहता हूँ। आज सुबह भी एक ऐसा विशय आया था जोकि मैडिकल डिपार्टमेंट के बारे में था। मैंने उस पर भी बोलने का टाईम मांगा लेकिन नहीं मिला। मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ दो तीन बातें कहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो फ़ैमिली वेलफ़ैयर का प्रोग्राम है इसको इम्पलीमेंट करने की जिम्मेवारी मैडिकल डिपार्टमेंट की है। आबादी बढ़ाने का प्रोग्राम भी मैडीकल डिपार्टमेंट ने ही किया है क्योंकि पहले बच्चे छोटी उम्र में दवाई न होने के कारण से, मैडिकल सुविधाएं न मिलने के कारण मर जाते थे इसलिए आबादी थोड़ी रह जाती थी। लेकिन अब मैडिकल फ़ैसीलिटीज बहुत आसानी से अवेलेबल है इसलिए मोरटेलिटी जो रेट है वह बहुत घट गया है, इसलिए आबादी भी बढ़ गई और इस तरह से आबादी बढ़ने की सारी जिम्मेवारी मैडिकल प्रोफ़े इन के जिम्में पड़ गई। अब जो आबादी बढ़ गई है उसकी रोकथाम भी करना जरूरी है और यह मैडीकल प्रोफे इन का काम है कि बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल करे। सारे सदस्य डरे हुए से बोल रहे थे कि भायद इसमें आप्रे इन का ही प्रोग्राम हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह जो आप्रे इन करने का प्रोग्राम है, **(12.00 बजे)** इससे लोग डरते हैं। आज से पहले लोगों के आपरे इन जोर-जबरदस्ती से किए गए थे। मेरी प्रार्थना है कि जबरदस्ती आप्रे इन करके मैडीकल प्रोफ़े इन को बदनाम न किया जाए, वालेंटेरीली अगर कोई करवाता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे

याद है, एमरजेंसी के दिनों में, एस0एम0ओ0 जो क्लास बन आफिसर होता है, इसके पास भी पावर नहीं होती थी कि वह अपनी मर्जी से किसी आप्रे इन केस को रिजैक्ट करे। ए0एम0ओ0 या छोटे डाक्टरज का तो कहना ही क्या, ये तो रिजैक्ट कर ही नहीं सकते थे, एस0एम0ओ0 जो क्लास बन होता है उसके बस से भी बाहर की बात थी। चाहे कोई व्यक्ति आप्रे इन के काबिल है या नहीं, इनको उसका आप्रे इन करना ही पड़ता था, ऐसे आर्डरज थे। चाहे 80 साल का बूढ़ा हो, चाहे 15 साल का कंवारा हो, डाक्टर की अपनी डिसक्री इन नहीं थी कि वह आप्रे इन करने से उसको छोड़ दे। अगर कहीं छोड़ देता था तो उसको कहा जाता था कि क्या आपने मीसा देखा है? मुझे अच्छी तरह से याद है एस0एम0ओ0 ने ए0एम0ओ0 को यह पावर दे दी थी कि वह किसी व्यक्ति को आप्रे इन करने से छोड़ सकता है लेकिन वह ऐसी पट्टी पढ़ाता था ऐसी कहानी गढ़ता था कि आप्रे इन कर देता था। डिप्टी स्पीकर साहब, 80 साल के बूढ़े और 15 साल के बच्चे का आपरे इन करने का क्या मतलब है? डा0 अपने आप तो इनके आप्रे इन नहीं करना चाहते थे। लेकिन ऊपर के दबाव से उनको करने पड़ते थे। डाक्टर खुद क्यों आप्रे इन करेगा वह सारी उम्र की बदुआ अपने सिर क्यों लेगा? मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार फैमिलि प्लानिंग का प्रचार कर रही है। फैमिली प्लानिंग के लिए आप्रे इन ही एक बढ़िया तरीका है, ऐसी बात नहीं है आप्रे इन तो आखिरी चीज है। इससे पहले और कई तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जिन को सारी दुनियां के

लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ आपरे इन से ही फैमिली प्लानिंग हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। स्त्रियों के लिये अलग तरीके हैं, पुरुशों के लिए अलग है और ये ऐसे तरीके हैं जिन से घरेलू लाईफ में, सैक्सुअल लाईफ में बाधा नहीं पड़ती। माननीय सदस्यों को समझना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग का मतलब आपरे इन ही नहीं है, यह उनके मन में संदेह है। अब मैं अपने असली प्वायंट पर आता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आपका समय तो हो गया है।

डा० बृज मोहन गुप्ता: बजट पर बोलते हुए सारे सदस्यों ने यह बात कही कि हस्पतालों में दवाइयों की कमी है कहीं कहीं पर डाक्टरों की कमी है। मैं मानता हूँ कि सब जगह डाक्टरों की कमी है लेकिन इसका कारण क्या है। मैडीकल प्रोफै इन में डाक्टरों की कमी क्यों है? इसका कारण मैं बताना जरूरी समझता हूँ। अगर मेरे माननीय मंत्री इन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे तो डाक्टरों की, लेडी-डाक्टरों की ओर स्पैशियलिस्ट्स की कमी पूरी हो सकती है। डाक्टरों सर्विस छोड़ कर फौरन में नहीं जाएंगे, जितनी जरूरत है यहीं पर मिलते जायेंगे। सबसे पहले आप देखें डाक्टरों की क्वालीफिकेशन कितनी कठिन है। मैं समझता हूँ कि सब से कठिन एजुकेशन है तो डाक्टरों की एजुकेशन है। सबसे मुश्किल मैडीकल प्रोफै इन है। इनका कम्पैरिजन किसी आई०ए०एस० आफिसर के साथ नहीं हो सकता क्योंकि जितनी मेहनत एक डाक्टर बनने के लिये करनी

पड़ती है उससे कम आई०ए०एस० आफिसर बनने के लिये करते हैं। डा० की बड़ी मुश्किल ऐजुकेशन है। अब एक डाक्टर की ड्यूटी और ग्रेड देखिए। मुझे याद है, बीस साल पहले एक डाक्टर का ग्रेड 150 रूपये (नॉन-गजेटिड) होता था। जब हरियाणा बना और डाक्टर नहीं मिलते थे तो इन का ग्रेड 200 रूपये कर दिया। ए०एम०ओ० जिसका ग्रेड 400 रूपये का है, क्लास टू है लेकिन इसके मुकाबले में एच०सी०एस० क्लास टू (एग्जैक्टिव और जुडिशियरी) का ग्रेड 700 का है। अब आप डाक्टर की ड्यूटी को देखिए। सबसे पहली बात यह है कि डाक्टर की इंडिविज्वल लाईफ नहीं है। सुबह से अपने काम में जुट जाता है, रात तक लगा रहता है। उसको लैटरिन जाने की फुर्सत नहीं होती। लैटरिन में बैठे हुए को काल आ जाये तो जाना पड़ता है। वहीं बैठे बैठे काल अटैंड करनी पड़ती है। नारनौल में ऐसा किस्सा हुआ है। अब आप देखें लैटरिन में बैठकर भी डाक्टर अपने काम में व्यस्त रहता है।

श्री उपाध्यक्ष: आपका समय खत्म हो गया है। आप वाइंड-अप करने की कोशिश करें।

डा० बृज मोहन गुप्ता: एक मिनट में खत्म करता हूँ। डाक्टर ब्रेक-फास्ट चैन से नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब यह है कि डाक्टर की इतनी सख्त ड्यूटी होने के बाजवजूद भी, इनके ग्रेड बहुत कम हैं। इनकी इंडिविज्वल लाईफ नहीं है, फ़ैमिली लाईफ नहीं है, कोई सोशल लाईफ नहीं है,

इसके बावजूद भी इनके ग्रेड कम है। सर्विस भी इनको ज्यादा करनी पड़ती है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इनके ग्रेड बढ़ा कर पूरी फैसिलिटीज देने की कोशिश करें ताकि हरियाणा में रहने वाले मैडीकल प्रोफेशनल के लोगों को, हरियाणा छोड़ कर फौरन न जाना पड़े और यहीं पर अपने देहावासियों की सेवा करें।

श्री जगन नाथ(बवानी खेड़ा, अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड सं0 15 पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। इस डिमांड में 1,23,37,45,015 रूपए की मांग की गई है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह मांग ऐसी है जिसमें और पैसा बढ़ा दिया जाए क्योंकि देहा में सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिंचाई के क्षेत्र में जितना पैसा लगे उतना ही कम है। यह पैसा किसी एक जिले को पानी देने के लिये नहीं है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता बल्कि सारी स्टेट के लोगों की भलाई के लिए होता है। लेकिन मैंने देखा है कि पानी का बंटवारा ठीक तरह से नहीं किया जाता। कुरुक्षेत्र, जींद, सोनीपत और करनाल में सौ परसेंट जमीन को पानी लगता है, एक इंच जमीन पानी के बिना खाली नहीं है। इसके दूसरी तरफ जिला गुड़गांव का कुछ एरिया, राव बीरेंद्र सिंह का महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हिसार और सिरसा का कुछ एरिया में पानी बिल्कुल नहीं लगता। मेरे हलके में अगर पांच परसेंट पानी लग जाये तो पूरा आबियाना देना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि पानी का बंटवारा सही ढंग

से किया जाना चाहिए। इसके बाद एक सीरियस बात कहना चाहता हूँ, यह बात पिछले दिनों हाउस में उठाई थी। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर अगर एक फसल को दस पानी लग जाता है और इसके मुकाबले में महेंद्रगढ़ जिले में, भिवानी जिले में एक फसल को एक पानी लगे तो दोनों को बराबर मालिया देना पड़ता है यानी एक पानी वाले को भी उतना ही मालिया देना पड़ता है जितना दस पानी वाले को देना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खेत को पानी छू भर जाएं, मालिया पूरा वसूल किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर एक फसल को एक बार पानी लग जाए तो मालिया देना पड़ता है। वह फसल पकने के बाद किसान फसल काट लेता है और इसके बाद अगर बारि 1 हो जाए तो उस में किसान दूसरी फसल बो देता है लेकिन उसको दोबारा मालिया देना पड़ता है। दोबारा फसल बोने पर उसको डबल मालिया आयेगा। पहली फसल पर जब एक पानी लगा था उसका भी आयेगा और बारि 1 पड़ने पर जो फसल बोई है, उसका भी आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष: आपका समय हो गया है।

श्री जगन नाथ: मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसे केसिज में दोबारा मालिया नहीं आना चाहिए, जितना पानी लगा है उतना ही मालिया आना चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि पानी जरा छू भर भी जाए, किसान को मालिया देना पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके इलावा डिप्टी स्पीकर साहब,

इरीगे ान वीाग के जो एस0डी0ओ0 एक्सीयन वगैरह की ए0सी0आर0 डिप्टी कमी ानर लिखता है जबकि इस महकमें के उच्चाधिकारियों द्वारा लिखी जानी चाहिए, एस0ई0 को लिखना चाहिए, यह जो अग्रेजों के जमाने से चला आ रहा पुराना समाजवादी ढांचा है इसको बदला जाना चाहिए और इनकी ए0सी आर0एस0ई0 जैसे उच्च अधिकारियों द्वारा लिखी जानी चाहिए और इनके ग्रेड भी रिवाईज होने चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, पब्लिक हैल्थ के बारे में भी मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि मंत्री महोदय बैठे है। जितनी भी पुरानी स्कीमें है उनमें आबादी बढ़ गई है। इनके बारे में भी जल्दी से जल्दी इंतजाम होना चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हर हल्के में एक ही स्कीम देनी है। देखना यह है कि जहां खारा पानी है, जहां पीने का पानी नहीं है वहां पर टौप प्रायोरिटी पर स्कीमें बननी चाहिए। धन्यवाद।

चौधरी लाल सिंह(नारायणगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद डिमांड नं0 21 की तरफ से लाना चाहता हूं। ऐसा है कि जातियां तो बहुत सी है बैकवर्ड करार दे दी गई है लेकिन हरियाणा में यह बैकवर्ड नहीं है। इसी तरह से कुछ दूसरी जातियां भी है जैसे रोड़ और अहीर जाति। ये जातियां जब दूसरे राज्यों में बैकवर्ड करार दी गई है तो यहां भी ये बैकवर्ड डिकलेयर होनी चाहिए ताकि ये लोग भी दूसरी जातियों के बराबर आ सकें।

डिप्टी स्पीकर साहब, मांग नं० 10 के बारे में भी मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ। पीने के पानी का यहां पर बहुत बड़ा भार हुआ। यहां कहा गया कि सरदार लछमन सिंह ने यह कर दिया और वह कर दिया लेकिन सच्ची बात यह है कि आज भी कालका और नारायणगढ़ के लोग हिमाचल के नालों में पानी भरने जाते हैं। आप यकीन करें कि जिस तरह हल चला कर बैलों के कंधे सूज जाते हैं उसी तरह से पानी ला ला कर हमारे यहां औरतों के कंधे सूज जाते हैं। यही नहीं गर्मियों के दिनों में तो लोग अपने घर बार छोड़ करके हिमाचल या हरिद्वार की तरफ चले जाते हैं। वहां अगर पानी ज्यादा भी दे दिया जाए तो कोई पाप नहीं। यह जरूरी नहीं कि हरेक एम०एल०ए० के हल्के में बराबर ही पैसा खर्च होना चाहिए चाहे वहां किसी चीज की जरूरत हो या न हो। जहां जरूरत हो वहां ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए।

इसके साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर साहब मैं हस्पतालों के मुताल्लिक भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। भिवानी और दूसरी जगहों पर इस सरकार ने बड़े बड़े हस्पताल खोल दिए। मेरा इलाका नदियों से घिरा हुआ इलाका है। वे लोग दवाइयों के बगैर कुत्तों की मौत मर जाते हैं। उनको हस्पताल का पता ही नहीं कि कैसा होता है। अम्बाला में भी अंग्रेजों के जमाने का हस्पताल है। इसलिए इस पिछड़े हुए इलाके की तरफ सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से आपके द्वारा प्रार्थना

करूंगा कि एक तो अम्बाला के हस्पताल को ऐसाहस्पताल बनाया जाए जैसा हस्पताल बाकी जिलों में है। दूसरे नारायणगढ़ और कालका तहसील के गांव में भी कम से कम 25 बैड के हस्पताल होने चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो भार्त लगाई गई है कि इतनी आबादी होगी तो हस्पताल बनेगा, इससे तो लोग आबादी बढ़ाने में जुट जाएंगे और बाद में फिर सरकार को फ़ैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि हस्पताल खोलने के लिए आबादी का हिसाब नहीं रखना चाहिए।

अब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं खेती बाड़ी के संबंध में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। इसके बारे में बहुत से भाई बोले लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि जमींदारों को पानी और बिजली महंगी मिलती है। जमींदार जो मीटर लगाते हैं वे भी उन्हें अपने मोल लेकर के लगाने पड़ते हैं। सरकार कोई मीटर नहीं देती। जो व्यक्ति मीटर खरीद नहीं सकता वह कनैव्तान नहीं ले सकता। इसी तरह से खाद की बात आप ले लीजिए। गरीब आदमी अपने खेत में खाद भी नहीं डाल सकता। सरकार को इसे भी सस्ता करना चाहिए।

डिमांड नं0 22 के बारे में डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा यह निवेदन है कि हमारी यह बड़ी खुशकिस्मती है कि चौधरी भजन लाल जी इस महकमें का बड़ा सुधार किया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने भी कुछ सुधार किया था लेकिन उनके पास यह महकमा थोड़े ही दिन रहा। अब हमें इतना सुख हो गया है कि

पहले जो हरिजन लोगों को पैसा खाता तो कोई था और पकड़ा कोई और जाता था वह बात नहीं होती। (विघ्न) लेकिन फिर भी अभी इसमें काफी कुछ करने की गुंजाइश है। डाक्टर साहब के हल्के में छप्पर थाने में एक आदमी के विरुद्ध केस दर्ज है। उसने लोगों के लाखों रुपये खा लिए हैं लेकिन उसक अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। इसी तरह से आज भी हर गांव में लोग इस तकलीफ की वजह से तड़फ रहे हैं। उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। (विघ्न) जितना कुछ किया गया है उसके लिए तो मैं हाउस के सामने चौधरी भजन लाल जी को मुबारिकबाद देता हूँ लेकिन जो काम बाकी रह गया है उसके लिए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उस काम को भी ये जल्दी से जल्दी पूरा कर दें।

कार और मिलों की बाबत भी मैं कुछेक बातें अर्ज करना चाहूंगा। मिलों के अंदर जो घपले थे उनमें भी चौधरी साहब ने काफी सुधार किया है लेकिन अभी बहुत सा सुधार करना बाकी है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे जिले में ये जो मिनी बैंक मैनेजर बनाए गए इनमें ऐसा हुआ कि जब एक बिरादरी के आदमी जिले में नहीं मिले तो दूसरी स्टेट से लाकर लगा दिए गए। वे ऐम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज से भी नहीं आए बल्कि डायरेक्ट रखे हुए हैं और रिस्तेदार रखे हुए हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, ये कांग्रेसी भाई हरिजनों की दुहाई तो बहुत देते हैं लेकिन हरिजनों के नाम से पता नहीं कितने पैसे खा गए। अगूठे तो हरिजनों के लगवाए गए लेकिन

पैसा कोई और खा गया। (विघ्न) अगूँटे जब फिल्लौर से टैस्ट करवाए गए तो वे सही निकले। इसलिये मैं आपकी मारफत अपने पापलर मिनिस्टर चौधरी भजन लाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सोसाइटियों के ऊपर छापे मारो। इनसे मैं यह इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि ये ईमानदार आदमी है। डिप्टी स्पीकर साहब, अम्बाला का बैंक भुरु से लेकर आज तक एक ही खानदान के हाथ रहा। आज आप देखें कि उसकी कितनी बुरी हालत है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बैठिए क्योंकि आपका टाइम हो गया है।

चौधरी लाल सिंह: आखिर मैं मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हस्पताल और पीने का पानी वहां दिया जाए जहां इसकी जरूरत है। धन्यवाद।

श्री भाम ोर सिंह(नरवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 10, 15, 21 और 22 के बारे में संक्षिप्त रूप से कुछ कहना चाहूँगा। डिमांड नं० 22 कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी सारे हरियाणा में मिनी बैंकस की जो मैनेजिंग कमेटीज है उनके चुनाव होने हे। इसके बारे में मैंने चौधरी भजन लाल जी से कल बात की थीं मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ क्योंकि उन्होंने इस बात का आ वासन दिया है कि इन कमेटीज के जो सरकारी मैम्बरज है वे चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इन्होंने इसके बारे में इंस्ट्रक् ांज भी जारी कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, ये जो डिपार्टमेंट्स इंस्ट्रूकेंस जारी की गई हैं, ये काफी नहीं हैं। इनका दुरुपयोग हो सकता है, वायले इन हो सकती हैं। मैं चाहूंगा कि कोआप्रे इन मिनिस्टर रूल्ज में तरमीम करें। अगर तरमीम न करें तो इस बात का आवासन दें कि जो मिनी बैंकों की कमेटी के चुनाव हो रहे हैं उनमें सात के करीब मैम्बर चुने जाने हैं और इन में तीन-चार सरकारी कर्मचारी भी मैम्बर हैं। वैसे कायदे के मुताबि मैनेजिंग कमेटी के पूरे मैम्बर हैं। इसलिए मैं आपकी मारफत सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर कोआपरेटिव डिपार्टमेंट इस चुनाव में भाग लेगा तो इन तीन चार की गिनती सात के मुकाबले में इतनी है कि यह चुनाव सारा धोखा होगा। इसलिए प्रजातंत्र प्रणाली को ठीक रखना है तो हिस्सेदार लोग ठीक नुमाइंदे का चुने लेकिन सरकारी कर्मचारी जो कमेटी के मैम्बर हैं उनको चुनाव में भाग लेने की इजाजत न दी जाये। यदि इसके कानून में तरमीम करना जरूरी हो वे वह भी की जाये।

उपाध्यक्ष माहदेय कोआप्रे इन डिपार्टमेंट के साथ और भी बहुत से अदायरे हैं जिनके अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं जैसे हैफेंड, लैंड मार्गेज बैंक, कोआप्रेटिव बैंक आदि हैं इन सब के जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जाने चाहिए।

जनता पार्टी ने चुनाव कसे समय बहुत लम्बे चौड़े वायदे किये थे लेकिन पिछले दो सालों से इन अदायरों के चुनाव नहीं हुए। उन्होंने अपने आदमी लगाये हुए हैं। कहीं पर सरकारी

कर्मचारी ओर कहीं पर पब्लिक का आदमी एडमिनिस्ट्रेटर या चेयरमैन लगा रखा है। तफसील में जाने का समय नहीं है। इस बारे में इतना ही सुझाव दूंगा कि वक्त को जाया किये बिना चुनाव कराये जायें।

भूगर मिल पर करोड़ों रूपया केन ग्रावर का लगा हुआ है। लाखों किसानों के जीवन का मामला है। किसानों ने यह देखना है कि किस तरह इस रूपए का उपयोग हो रहा है क्या कुछ किसानों को देना है लेकिन सरकार ने वाहं पर सरकारी अफसरों को यादूसरे लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर के तौरपर बैठा रखा है। इसलिए इनके भी जल्द से जल्द चुनाव कराये जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नम्बर 21 कम्युनिटी डिवैल्पमेंट के बारे में है। यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। इसका भी देहात के लोगों से बड़ा गहरा संबंध है जनता सरकार ने इस बात का वचन दिया था कि वह प्रजातंत्र को बहाल करेगी। अभी पिछले दिनों पंचायतों के चुनाव करवाये गये लेकिन जिला परिशदों और पंचायत समितियों के चुनाव आज तक नहीं हुए। इस बारे में बड़ी भारी कोताही हुई है, जिसका नतीजा यह हुआ कि पंचायत पूरीतरह कार्य नहीं कर रही है। जब से चुनाव हुए हैं सियासी मोटिव से बे जुमार पंचों और सरपंचों को मुअतल किया गया है और उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। हजारों और सैंकड़ों की तादाद में सस्पैंड किये जा रहे हैं। उसका कारण यह

है कि जनता पार्टी के एम0एल0ए0 उनके खिलाफ है क्योंकि उनके आदमी नहीं आये ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पंचायत डायरेक्टर आफिस के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूँ। यह आफिस चंडीगढ़ में है। हजारों की तादाद में पंचायतें हैं। यहां पर एक छोटा सा दफ्तर है और काम बहुत ज्यादा है। यहां के दफ्तर को चाहे कोई भामलात इन्कवायरी हो या कोई छोटी इन्कवायरी हो उसको पूरी जांच करनी पड़ती है जिसके कारण स्टाफ बहुत कम पड़ता है। पिछले पांच सालों से डायरेक्टर पंचायत के दफ्तर में ज्वायंट डायरेक्टर की आसामी खाली पड़ी हुई है। उस पद को आज तक नहीं भरा गया है और न ही वहां पर सरकार रूलज बना पाई है। उस आसामी पर डिप्टी डायरेक्टर काम करता है। चार पांच साल से उसी ज्वायंट डायरेक्टर का काम लिया जा रहा है। मुझे आता है कि मंत्री महोदय इस का जल्दी से जल्दी फैसला करेंगे और इस आफिस का विस्तार करेंगे।

दूसरी बात यह है कि पिछले दो साल में पांच छः डायरेक्टर चेंज हुए हैं। हर दो महीने बाद नया डायरेक्टर पंचायत लगा देते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि डायरेक्टर पंचायत को बार बार चेंज न किया जाये ताकि डिपार्टमेंट का काम ठीक तरह से चल सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 10 के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूँ। हरियाणा में करोड़ों रूपया हैल्थ डिपार्टमेंट पर खर्च किया जात है परन्तु हस्पताल और प्राईमरी हैल्थ सेंटर के लिए केवल 14 पैसे प्रति व्यक्ति का दवाई का प्रबंध किया गया है। यह गरीबों के साथ मजाक है। जो गरीब आदमी सरकारी हस्पताल में इलाज कराना चाहता है उसके लिए बहुत थोड़े पैसे दवाई के लिये रखे गये हैं। गरीब आदमी प्राइवेट डाक्टर को दिखा नहीं सकते। इसलिए 12-14 पैसे प्रति व्यक्ति का बजट में प्रबंध हो तो हस्पतालों का क्या मुद्दा है? इसलिये मुझे उम्मीद है कि दवाइयों के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा रखा जायेगा।

डिमांड नं0 15 पर बिजली के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। सरकार ने फ्लैट रेट तो कर दिया लेकिन 17 रूपये प्रति हार्स पावर बहुत ज्यादा खर्चा रखा है। पड़ोस की पंजाब सरकार में 13 रूपए प्रति हार्स पावर लिया जाता है चार रूपए का काफी फर्क है इसलिये इसको भी पंजाब के बराबर किया जाना चाहिए।

(At this stage several members rose to speak)

Mr. Deputy Speaker: As there are still several members who want to participate in the discussion, if it is the sense of the House, the time of the sitting be extended by half an hour i.e. upto 1.30 p.m.

(Voices: Yes)

Mr. Deputy Speaker: The time of the sitting is extended upto 1.30 p.m.

वर्ष 1979-80 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनराम्भ)

स्वामी आदित्यवे (हथीन): डिमांड नं० 10, 15 और 17 पर अर्ज करना चाहता हूँ। डिमांड नं० दस में 35 करोड़ रूपया का प्रावधान किया गया है। इसमें से 13 करोड़ रूपया औशधियों के लिए रखा गया है। 2 करोड़ 5 लाख रूपया रोहतक मैडिकल कालेज के लिये रखा गया है। बाकी बीस करोड़ रूपया वेतन और कार्यालय के दूसरे खर्चों के लिए रखा है। कल हमारे वित्त मंत्री जी ने जो घोशणा की है कि सभी मिनिस्टर एम०एल०ए० फ्लैट में चले जायेंगे इससे भी खर्चों में काफी फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार से आज कार्यालयों का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कार्यालयों का खर्चा घटाया जाए और उसमें कटौती की जाए। तभी हम हरियाणा की जनता का भला कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा की आबादी एक करोड़ बीस लाख है। एक करोड़ बीस लाख की आबादी के लिए 13 करोड़ रूपया दवाइयों के लिए रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, श्री सुरजेवाला ने कहा है कि दवाई के लिए सिर्फ तेरह पैसे एक आदमी के लिए रखा है। इनको तो गलत आंकड़ें देने की आदत है। उपाध्यक्ष महोदय यह एक रूपया तेरह पैसे प्रति व्यक्ति निकलता है। मेरा

कहना यह है कि यह कम है इसको बढ़ाना चाहिए। आजकल बहुत महंगा इलाज है इसलिये इस महंगे इलाज को बदलने के लिए कदम उठाने चाहिए और प्राथमिक चिकित्सा में योगाभ्यास और एकूपन्चर पर जोर देना चाहिए और इन चीजों पर सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए। महंगे इलाज पर इतना पैसा खर्च किया जाता है और फिर भी यह देखा गया है कि पूरा इलाज नहीं हो पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं० 15 के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें चीफ इंजीनियर के आफिस के लिए छः लाख 81 हजार रूपया रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय एक आफिस के लिए इतना रूपया रखने का अर्थ है कि वहां पर इस रूपए से गलीचे आएंगे, फर्नीचर आएगा और सोफा सैट आएगा। मैं समझता हूं कि यह पैसा फिजूलखर्च होगा और इसमें कटौती की जानी चाहिए। अगर हमारे मंत्रीगण और मुख्य मंत्री महोदय सादगी का जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो हमारे आफिसर्ज भी सादगी का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक तरफ तो गांवों में लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है और दूसरी तरफ एक चीफ इंजीनियर के लिए छः लाख 81 हजार रूपया रखा गया है। इसी तरह से पिंजौर गार्डन के लिए तीन लाख रूपया रखा है। यह पुराने बाद गार्डन के जमाने का बाग है। इसको सजाने के लिए तीन लाख रूपया रखा है। एक कार्यालय के लिए छः लाख रूपया रखा है और एक के लिए तीन लाख रूपया रखा है। उपाध्यक्ष

महोदय, एक तरफ तो हम इतना रूपया बरबाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि हम हरियाणा की जनता की भलाई करेंगे। यह ठीक है कि सरकार की नियत जनता की भलाई करने की है और वह सच्चे मन से जनता की भलाई करना चाहती है लेकिन मेरा कहना केवल इतना है कि जब हमारे मंत्री और मुख्य मंत्री सादगी का जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो हमारे कार्यालयों पर जो फिजूलखर्ची हो रही है उसको रोका जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नम्बर 15 में ड्रेनों की बात कही गई है और इसके लिए 1 करोड़ 23 लाख रूपया रखा गया है। लेकिन यह रूपया कहां जाता है इसका कुछ पता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुड़गांव की बाबत बताता हूँ कि वहां नालों का जाल बिछा हुआ है। वहां पर काफी ड्रेज और नालें हैं और इनके लिए पैसा भी मंजूर हो जाता है लेकिन काम नहीं होती। हथीन और रीडका के बीच में एक गोंछी ड्रेन है उस पर पुल नहीं बना है। मतरोल ड्रेन नं0 1 और नं0 2 हैं, दिघोट ड्रेन है, पिंगोंड ड्रेन और रानीका ड्रेन है। और भी बहुत सारी ड्रेज है और इन सारी ड्रेज के लिए एक करोड़ तेइस लाख रूपया रखा गया है। यह पैसा इनकी मुरम्मत के लिए है। उपाध्यक्ष महोदय, इन ड्रेज की मुरम्मत इस प्रकार की जाती है कि जब बरसात नजदीक आ जाएगी, पानी गले तक आ जाएगा, उस समय दस-पांच मजदूर वहां पर लगा देंगे। मजदूर तो दस लगाएंगे और मस्टर रोल पर

पचास आदमी दिखा देंगे। हमारे यहां एक अलीमेव ड्रेन है। पिछली बार मैंने वहां देखा कि 45 आदमी वहां पर काम कर रहे हैं और मस्टर रोल पर नब्बे आदमी दिखाए हुए हैं यानी कि 45 की जगह नब्बे आदमियों का खर्च दिखाया जा रहा है। अगर इस तरह की घपलेबाजी हो तो क्या वास्तव में हम लोगों का भला कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय इसी प्रकार परिवार नियोजन के लिए तीन करोड़ रूपया रखा है। ये लोग जितना इस बात का प्रचार करेंगे कि परिवार नियोजन कराओ उतना ही उसका उल्टा असर पड़ेगा। मेरा कहना है कि अगर यही तीन करोड़ रूपया ब्रह्मचर्य के प्रचार, इंद्रिय निग्रह के प्रचार और योगाभ्यास के प्रचार पर खर्च किया जाए तो कोई समस्या नहीं रहेगी।

चौधरी संत कंवर: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। स्वामी जी चाहते हैं कि सारे के सारे लोग इनकी तरह कपड़े पहने हो जाएं तो अपने आप परिवार नियोजन हो जाएगा।

स्वामी आदित्यवे I: उपाध्यक्ष महोदय, सब लोग मर्यादा पुरुशोत्तम राम को जानते हैं। चौदह साल तक वे अपनी पत्नी के साथ बनों में रहे और जब चौदह साल के बाद जंगलों से वापिस आए तब भी दो ही थे। हमारी सरकार को तो संयम का प्रचार करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग आप हो जाएगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जनसंख्या बढ़ाओं आर्थिक विशमता घटाओं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा की आबादी एक करोड़ बीस लाख है और यहां 58 लाख टन अनाज पैदा हो रहा है।

चौधरी देसराज: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, समझ नहीं आता कि स्वामी जी पापुले उन बढाने की बात क्यों कर रहे हैं इनको न तो किसी को रोटी देनी है और न ही किसी को कपड़ा देना है।

श्री उपाध्यक्ष: स्वामी जी अब आप समाप्त करें। आपका टाईम हो गया है।

स्वामी आदित्यवे T: उपाध्यक्ष महोदय, अगर धन का ठीक से बंटवारा कर दिया जाए तो.....

श्री उपाध्यक्ष: स्वामी जी आप बैठ जाएं। रव राम नारायण जी आप बोलें।

स्वामी आदित्यवे T: उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक मिनट और दें जिससे कि मैं अपनी बात पूरी कर सकूँ।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं। अब आप बैठ जाएं।

राव राम नारायण(साहलावास): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे टाईम दिया है। सबसे पहले मैं डिमांड नं० दस जो मैडीकल की है, के बारे में बोलना चाहता हूँ। आज फैमिली प्लानिंग के बारे में जो रेजोल्यूशन आया था, मैं उसका समर्थन करता हूँ। बगैर फैमिली प्लानिंग के अपनाएं दे T में खुद गहली नहीं आ सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में कोसली एक बहुत बड़ा गांव है। वहां पर 1922 से एक डिस्पेंसरी है। वह बहुत बुरी हालात में है। वह एक्स सर्विसमें का बहुत बड़ा

गांव है। सात हजार की आबादी है। वह हॉस्पिटल अपग्रेड होना चाहिए। उस अस्पताल में मैडीसीन बिल्कुल नहीं मिलती है। और जो वहां पर डाक्टर है उसकी भी कोई अच्छी रेपुटे इन नहीं है। मेरे हल्के में बच्चा एक गांव है वहां पर मैडीकल डिस्पेंसरी होनी चाहिए। जहां तक पब्लिक हेल्थ का ताल्लुक है उपाध्यक्ष महोदय मेरे हल्के के सारे गांवों में ब्रेकिंग वाटर है और अभी तक पीने के पानी की एक भी स्कीम वहां पर लागू नहीं हुई है। सरदार साहब ने मुझे अयोरेंस तो दी है कि मेरे हल्के में एक पीने की पानी की इसी साल स्कीम दे दी जाएगी और मुझे आता है कि वह अपना अयोरेंस अवयव पूरा करेंगे। मेरे हल्के में झांसवा और मोहन बाड़ी ऐसी जगह है जहां पर तीन-चार मील से पीने का पानी लाना पड़ता है। मुझे आता है कि इस तरह की तकलीफों को इसी साल एक पानी की स्कीम देकर अवयव दूर करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं० 15 जो सिंचाई के बारे में है, के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। जवाहर लाल नेहरू कैनल पर डिस्ट्रिब्यूटरी और वाटर कोर्सिज का नैट वर्क सारे महेंद्रगढ़ और मेरे हल्के साल्हावास में हो चुका है लेकिन एक गांव को दूसरे गांव से मिलाने के लिए कहीं ब्रिज नहीं है। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। बाजदफा तो एक आदमी को चार चार मील का चक्कर काटकर अपने खेत में पहुंचना पड़ता है। इसलिए वहां पर ब्रिज का होना बहुत जरूरी है। अगर पंजाब से हमें पानी नहीं मिला तो हमारे नहरें अब भी खाली हैं और आगे भी खाली रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय मेरे हल्के में और महेंद्रगढ़ में अस्पताल और मेडीसीन दी जानी चाहिए, इनको काफी कमी है। इसके साथ-साथ

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में से एक कैनल गुजरती है और उसके साथ-साथ सेम काफी हो गई है। एक बार हमाने माननीय सिंचाई एवं बिजली मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी वहां पर गये थे और उस वक्त उनके नोटिस में मैंने यह बात लाई थी कि यहां पर इस कारण से काफी से ज्यादा जमीन खराब हो गई है अतः मेरी अपनी सरकार से प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को नुकसान से बचाया जा सके।

अब मैं डिमांड नं० 17 पर बोलने जा रहा हूँ। कोसली के अंदर 1935 में मंडी बनाने के लिए सरकार द्वारा जमीन एक्वायर की गई थी पर आज तक वह मंडी नहीं बनी है, मुझे मालूम नहीं कि इस इलाके के साथ क्यों इतनी डिसकिमिनेशन की गई है। मैं कृषि मंत्री महोदय से यह रिकवैस्ट करूंगा कि इस मंडी को टाप प्रायोरिटी देकर डिवैल्पमेंट का कार्य किया जाए।

डिमांड नं० 18 के बारे में तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे हल्का में एक वरुआ जगह है वहां पर एक वेटरनिटी हस्पताल खोलने के लिए मैंने चौधरी भजन लाल जी से रिकवैस्ट की थी, मुझे पूरी आशा है कि वे इस तरफ अवधान देंगे।

इसके बाद मैं डिमांड नम्बर 21 के बारे में कुछ कहूंगा कि मेरे हल्के में दो ब्लॉक्स नाहड़ और साहलावास हैं जिनकी हदूद वैल डिमारकेटिड नहीं है, मेरी रिकवैस्ट है कि हैडक्वाटर साहलावास की बजाये डाकला या सुवाना कर दिया जाए। अब मैं डिमांड नम्बर 22 में कोआपरेटिव का जिक्र करता हूँ। देहातों में मिन्नी बैंक्स का जाल बिछा हुआ है और यह ठीक है कि किसानों को उन से काफी राहत

मिलती है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इसके साथ-साथ कुरुपान भी तेजी से हो रही है। एक दूसरे के नाम से बैंकों से कर्जा ले लिया जाता है और बाद में बेचारा किसान फंस जाता है और उसी को वह रकम पे करनी पड़ती है। इस प्रकार से जितने भी घपले हो रहे हैं, इसके बारे में मैं अपने वजीर साहब से कहूंगा कि इस तरफ खास तव्वजों दी जाए ताकि गरीब किसानों को किसी किस्म का नुकसान न हो सके। इन भाब्डों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और इसके साथ ही अपना स्थान लेता हूँ।

कैप्टन मांगे राम(झज्जरए अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, सब से पहले मैं डिमांड नं0 10 जोकि मेडिकल और पब्लिक हैल्थ के बारे में है पर कुछ कहना चाहता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जहां पर फ्लड की वजह से बरबादी हो गई है, उन जगहों पर खास ध्यान दिया जाये वहां पर हस्पतालों की बिल्डिंगों के बारे में कहा था कि झज्जर सब डिवीजन में जिसमे साहलावास, बेरी और बादली वगैरह आते है, हस्पताल 24 बैडज का है, इसलिये उस हस्पताल में 24 बैडज की बजाय 50 बैडज की प्रोवीजन की जाए ताकि इस इलाके के लोगों को किसी किस्म की दिक्कत न आने पाये। दूसरी बात मैं अपने सरदार लछमन सिंह जी से कहूंगा कि वे एक बार हमारे हल्के में चक्कर लगाकर आए तो तभी लोगों को पता चलेगा कि जनता सरकार भी कुछ लोगों के भले के लिये काम कर रही है। मेरे हल्के में गुडयानी आदि गांवों में वाटर सप्लाई स्कीम का अभाव है अतः मेरी अपने मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस तरफ भी तवज्जों देकर लोगों की कठिनाइयों को दूर

किया जाए। इसमें कोई भाक नहीं है कि काम हो रहे हैं और अच्छी प्रोग्रेस के साथ हो रहे हैं लेकिन सरकार को उन इलाकों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये जहां पर बिल्कुल कोई तरक्की के काम नहीं हुये हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं इरीगे टन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं इसमें कोई संदेह नहीं है कि बजट में 75 परसेंट पैसा इरीगे टन के कामों पर खर्च करने के लिये रखा गया है। मैं अपने इरीगे टन मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि सुबाना और सिकंदरपुर माईनर की तरफ भी ध्यान दिया जाए और सिकन्दरपुर माईनर को सिलानी तक एक्सटेंड किया जाए, यह माईनर सन् 1952 से प्रोफेसर भोर सिंह जी के वक्त से ऐसी ही पड़ी हुई है। यह केवल आधा या एक मील का फासला है इसका काम भीघ्र ही समाप्त किया जाए ताकि लोगों को पानी की सुविधा मिल सके।

इस माईनर के बनने से बहुत से गांवों को खेती बाड़ी के मामलें में काफी मदद मिल सकती है। रिंग वगैरह जो है, उनकी रिपेयर वगैरह का काम भी करवाया जाए। मेरे हल्के में खूडन एक गांव है बहुत छोटा सा रास्ता है वहां पर हरिजनों के सात आठ पक्के घर हैं अगर उन घरों को बांध के अंदर ले लिया जाए तो ये घर बरबादी से बच सकते हैं। एक रतनथल गांव है यह तकरीबन आधा गांव पानी में धिरा हुआ है वहां के लोगों ने आई0पी0एम0 साहब से भी इस बारे में प्रार्थना की है कि अगर इस छोटे से एरिया को गरावड़ा से ऊपर एक पक्की रोड तक मिला दिया जाए तो यह एरिया फ्लड की लपेट से बच सकता है। मुझे पूर्ण आ ता है कि हमारे मंत्री

महोदय इस तरफ पूरी तवज्जों देंगे, इसके साथ मेरी एक और प्रार्थना भी है कि रतनथल गांव में जो हरिजनों के 70-80 गांव है, वे फ्लड की वजह से बिल्कुल तबाह हो गये है और वे लोग झोपड़ियों में रह रहे है उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से क्लोई और मारोथ आदि हरिजनों के गांव है, इन सभी इलाकों के लिये सरकार को लोगों की भलाई के लिये कोई औद्योगिक सेंटर भी खोलने चाहिए और लोगों को धंधा भी देना चाहिये और साथ ही हाउसिंग विभाग की तरफ से इन लोगों के रहने के लिये हाउसिंग कालोनीज भी बनाई जानी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, इससे आगे मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर ए0सी0आरज0 को लिखेन की बातें भी आई है। डिप्टी स्पीकर साहब यह जो एस0डी0 ओज0 और एक्सीअनज है, उनकी ए0सी0आरज0 डी0सी0 लिखता है, यह बात गलत है। यह बेचारे काम तो अपने डिपार्टमेंट को जो उन से संबंधित है, करते है और ए0सी0आरज0 उनका अपना संबंधित आफिसर ही लिखें जिनके अंडर वे लोग काम करते है न कि डी0सी0 लिखें। मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है कि वे भीघ्र ही इस बात का निर्णय लेगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का ताल्लुक है, उसने बड़ा सराहनीय काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ-साथ मैं अपने आई0पी0एम0 साहब से यह बताना चाहता हूं कि मेरे हलके में नरवाना से टोहाना, हिसार सराना और पटियाला तक डबल लाईन बिछाई जा रही है जिसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं यह भी एक

बड़ा भारी सराहनीय कदम है। इसके साथ मैं बिजली बोर्ड के ही बारे में एक और बात कहना चाहता हूँ कि इसमें जो सिक्क्योरिटी गार्डज लगे हुये हैं वे सब एक्स-मिलटरी मैन हैं। अब से पहले 1969 में इनके ग्रेड रिवाइज किये गये थे, आज दस साल हो चुके हैं उनकी पे नहीं बढ़ाई गई। इसलिये मेरी गुजारि है कि सरकार उनकी पे रिवाइज करे। इन भाव्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

कामरेड भांकर लाल(सिरसा): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ दो तीन बातों के ऊपर अपने ख्याल रखूंगा। सब से पहले मैं डिमांड नं० 22 पर बोलूंगा जोकि कोआपरेटिव से ताल्लुक रखती है। किसानों को मिन्नी बैंकों की तरफ से जो कर्जे दिये जाते हैं उसमें ऐसा होता है कि 25 परसैंट तो कै 1 के रूपा में दिया जाता है बाकी 75 परसैंट खाद और बीज वगैरह की भाक्ल में किसानों को दिया जाता है, इसलिये मैं चौधरी भजन लाल जी से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि किसानों को हर तरह की सहूलियतें दी जाएं और उन्हें कर्जा जो है वह नकद ही दिया जाए क्योंकि लोगो की इस बारे में काफी शिकायतें हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, इससे आगे मैं डिमांड नं० 10 पर बोलूंगा जोकि मैडिकल हैल्थ से संबंधित है। सिरसा के अंदर बड़ा पुरान अस्पताल है जिसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है और वहां पर किसी किस्म का रोगियों के लिये ठीक इंतजाम नहीं है वहां पर पीने के लिये पानी नहीं है, और वहां पर रोगियों के लिये कोई खास साधन भी उपलब्ध नहीं है। फूटी दिल्ली की तरह वह बिल्डिंग दिखाई दे

रही है। वहां पर न तो कोई बाथरूम है, और न ही लेट्रिन है। अगर एक रोगी वहां पर चला जाए तो वह वहां से और ज्यादा बीमार होकर निकलेगा, ऐसी बुरी हालत है उस हस्पताल की। इसलिये मेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि उस बिल्डिंग को नये सिरे से बनवाया जाए और वहां पर जो एक अच्छे हस्पताल में सहूलियतें होती है वे दी जाएं ताकि लोगों को सुविधा हो सके। इसके बाद मैं डिमांड नं० 15 पर बोलना चाहता हूं जो कि सिंचाई से संबंधित है। इसके बारे में मेरी यह अपील है कि देहात के अंदर जो पक्के नाले बनते हैं या किसानों के खेतों में पक्के खाल बनते हैं उन पर सरकार का आठ आने खर्च आता है औ वह किसानों से एक रूपया ज्यादा यानी डेढ़ रूपया चार्ज करती है। हालांकि सरकार को किसान की भलाई के काम के लिए वर्ल्ड बैंक से आधे परसेंट सूद पर कर्जा मिलता है लेकिन वही कर्जा अगर किसान को दना हो तो उससे लगभग दस परसेंट सूद लिया जाता है। इसके अलावा जो हमारी एम०आई०टी०सी० है उसके अंदर इतनी घपलेबाजी है कि उसकी वजह से किसान के ऊपर बहुत बोझा पड़ता है। इसलिए सरकार को इसका प्रबंध करना चाहिए। जब सरकार को हम इतना टैक्स दे रहेस है तो सरकार को किसानों के खाल आधे पैसे लेकर पक्के करने चाहिए। मेरी आखिरी बात यह है कि अभी मैंने डिमांड नं० 10 का जिक्र किया था उसके बारे में मैं थोड़ा सा और कहना चाहता हूं। वह डिमांड परिवार नियोजन के संबंध में है। मैं मानता हूं कि परिवार नियोजन के बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। मगर इसमें ऐसा नहीं होना चाहिये जैसे इंदिरा राज के अंदर जोर जबरदस्ती हुई थी। यह प्रोग्राम तभी सफल हो सकता है अगर लोगों को इस बारे में

अपने विचार दिये जायें और शिक्षा दी जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ और इस बात से मुझे खतरा हो गया है।.....

.....

श्री उपाध्यक्ष: कामरेड जी इसका डिमांडज से कोई ताल्लुक नहीं है।

कामरेड भांकर लाल:.....(गोर).....

.....

चौधरी संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।माननीय सदस्य ने राज नारायण जी के बारे में जो भाब्द कहें है ये एक्सपंज होने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: ये भाब्द डिमांड से संबंधित नहीं है इसलिये ये कार्यवाही में नहीं आएंगे।

मास्टर शिव प्रसाद(अम्बाला भाहर): डिप्टी स्पीकर साहब, सब से पहले मैं मैडीकल की डिमांड पर बोलूंगा। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि अम्बाला में जो सिविल हस्पताल बनाने का सरकार ने निर्णय किया है वह भीघ्र अति भीघ्र पूरा होना चाहिए। इसके अलावा वहां पर भाहर के बीच में एक टी0बी0 हस्पताल बना हुआ है मैं चाहूंगा कि उसको भाहर की आबादी से बाहर ले जाये। पब्लिक हैल्थ के बारे में मैं यह कहूंगा कि अम्बाला भाहर में पानी की बहुत किल्लत है। हैल्थ मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब जब अम्बाला में गये थे तो उनहोंने यह कहा था कि 1.18 करोड़ रूपये की अम्बाला के लिए जो स्कीम है उसकी एडमिनिस्ट्रटिव एप्रूवल

भीघ मिल जाएगी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पंजाब की सीमा में जो एस0वाई0एल0 कैनल बननी है अभी तक उसका पानी न आने की वजह से हमारे इलाके का पानी दूसरे इलाकों में ले जाया जा रहा है वह पानी पाकिस्तान को जा रहा है इसलिए इस पानी को भीघ लेने की कोशिश की जाए। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो हमारे इलाके का पानी है इसको अगर ऊपर ही रोक लिया जाए तो इस इलाके को पापी के लिये और सिंचाई के लिये बहुत पानी मिल सकता है। अब यह पानी नदियों के किनारे बसे हुए लोगों को बरबाद करता हुआ हरियाणा के दूसरे जिलों में चला जाता है और इस पानी का लाभ अम्बाला जिला नहीं उठा पाता। इसलिये मेरा यह सुझाव है टांगरी और घग्गर नदी के पानी को रोक कर अम्बाला जिले के लिए इसे पीने और सिंचाई के प्रयोग में लाया जाये। डिमांड नं0 18 के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट प्लेस है लेकिन वहां पर डंगरों के हस्पताल की बिल्डिंग की बहुत बुरी हालत है। उस हस्पताल के इंचार्ज को जो बैठने का कमरा है पता नहीं उसकी छत कब गिर जाए। इसलिये उस हस्पताल की बिल्डिंग नये सिरे से बननी चाहिये यह काम इसलिये भी जरूरी है कि अम्बाला एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है इसलिए इस दृष्टि से भी यह काम किया जाना जरूरी है। मैं अधिक न कहता हुआ डिमांड नं0 21 के बारे में इतना ही कहूंगा कि बाढ़ पिछले साल भी आई और इस साल भी आई, मेरे हल्के में कुछ गांव ऐसे हैं जो घग्गर के किनारे बसे हुए हैं। जैसे उडियाना है, मानकपुर है, लोहगढ़ है, गंडेरी है, देवी नगर है, घोल और लाहरसा इत्यादि हैं। ये ऐसे गांव हैं जो घग्घर के किनारे पर

है। पंजाब की तरफ घग्घर के साथ-साथ बांध बनने की वजह से पानी का रूख बदल गया है और हरियाणा की तरफ से भी बांध न बांधा गया तो वह पानी जी०टी० रोड़ को भी तोड़ सकता है। जी०टी० रोड़ अम्बाला को बाढ़ से बचाने के लिये बांध का काम करती है। इसके साथ कुछ गांव है जिनके बचाने के लिए घग्घर पर बांध बनाना जरूरी है। इन गांवों में डडियाना से देवी नगर तक सड़क नहीं है। मैं पब्लिक वर्कस मंत्री जी से कहूंगा कि डडियाना से देवी नगर तक सड़क भीघ्रति गीघ्र बना कर इन गांवों को सड़कों से मिला देना चाहिये। कोआप्रे इन मंत्री महोदय से कहूंगा कि इनके विभाग में जो धांधली होती है वह दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी ई वर सिंह(गुहला, अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब मैं डिमांड नं० 10 पर बोलना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, जिन तहसीलों में अस्पताल नहीं है उनमें हस्पताल होने चाहिए मेरे क्षेत्र में सब तहसीलों को समानता नहीं मिली है। मेरी प्रार्थना है कि जहां पूरी तहसील में कहीं भी अस्पताल नहीं है वहां 10-12 बैड का सिविल हस्पताल होना जरूरी है। ऐसी-ऐसी तहसीलें है जहां कि स्थिति यह है कि वहां दवाइयों का कोई प्रबंध नहीं है कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। वहां पर सबसे पहले सिविल हस्पताल बनाये जाये। इसके साथ ड्रेंज के बारे में डिमांड नं० 15 पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे हल्के में कोई नई ड्रेन नहीं खोदी गई है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि मेरे इलाके में भी ड्रेंज बनायी जाये क्योंकि वहां इनकी जरूरत है। इसके साथ एक्सीअन के ग्रेड के बारे में कहूंगा कि इनका ग्रेड भी एस०डी०ओ० के ग्रेड के रे गों में बढना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो पहले भी कहा जा चुका है

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री(चौधरी भजन लाल):
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग की कुछ माननीय सदस्यों ने तारीफ भी की है और कुछ सदस्यों ने आपत्ति भी की है। कोआप्रेटिव ऐ ऐसा अदायरा है जिसके बारे में यह समझा जाता है कि यह प्रौफिट पर ही चलना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, सहकारिता का उद्दे य प्रौफिट से नहीं है। हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन की भावकल मैं चलाया था। यह बड़ी खु ि की बात है कि कोआप्रे ान विभाग ने जितना का किया है यह बड़ा ही सराहनीय है। हरियाणा में इस क्षेत्र में जितना काम हुआ है इतना और किसी प्रांत में नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय जब हरियाणा बना उस समय हम एक लाख टन अनाज बाहर से लेते थे ओर आज 22-23 लाख टन अनाज हमारे प्रांत में सरप्लस पैदा होता है और हम बाहर भेजते हैं। कोआप्रेटिव विभाग का यही उद्दे य होता है कि किसान को अच्छा बीज, अच्छी खाद, और कीटना ाक दवाईयां तथा कर्जे दिए जाएं। उस पैसे से लोग पम्पिंग सैट, ट्यूबवैल लागये ताकि अनाज को समय पर पानी दे सकें जिससे फसल अच्छी हो। हमारे दे ा और हमारे प्रान्त में जो हरित क्रांति आई है इसमें सहकारिता का बड़ा भारी योगदान है। कुछ मेरे साथी इस विभाग में घपले की बात करते हैं। घपले के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब हरियाणा बना उस समय हमारी वर्किंग कैपिटल 59 करोड़ की थी और अब वर्किंग कैपिटल 540 करोड़ रूपये है। इसमें से सिर्फ एक करोड़ नब्बे लाख रूपये के 979 केसिज घपले के हैं। यदि नै ानेलाईजड बैंक्स को आप देखेंगे तो इसके मुकाबले में बहुत ही

कम गबन इस इदारे में मिलेगा। आप महसूस करेंगे, सदन महसूस करेगा कि जहां 5 अरब 40 करोड़ वर्किंग कैपिटल हो उसमें से 1 करोड़ 90 लाख बहुत बड़ी रकम नहीं है। इसके बावजूद हम इसे वापिस लेने के प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे प्रान्त में 9 हाजर 858 कोआप्रेटिव सोसायटियां हैं, हमने फैसला किया है कि हर साल इनके अकाउंट का ओडिट करेंगे। हमारी कोर्पोरेशन होगी कि पूरी 9858 सोसायटीज का ओडिट करायें। इनमें से 9405 का ओडिट हो गया है। इनमें कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं है। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए एक फ्लॉइंग सुकैड बनाया जायेगा जिसमें एक संयुक्त रजिस्ट्रार, एक डी0आर0 और चार इंस्पैक्टर होंगे। यह धांधली बहुत पहले की हो रही है। पहले की जो प्रणाली थी उसमें सोसायटियों के जो सैक्रेटरी होते थे वे अगर किसी को कर्ज देते थे तो भोले भाले किसान से सौ रूपये पर अंगूठा लगवा लेते थे और बाद में एक बिंदी और जोड़ कर उसका 1000 बना दिया करते थे। हमारी कोर्पोरेशन यही है कि किसी से किसी प्रकार की धांधली न हो, ज्यादाती न हो। परन्तु कायदे कानून के आगे हमारी भी नहीं चलती। जब किसी आदमी ने एक रकम के आगे अंगूठा लगा दिया तो उसे बचाना हमें मुश्किल हो जाता है, परन्तु फिर भी हम कोर्पोरेशन कर रहे हैं कि इस प्रकार के केस में इंसाफ किया जाये, इस प्रकार के केसों की सर्वे करवा रहे हैं, उनकी इन्कवायरी करवा रहे हैं। अगर कानून ने इजाजत दी तो पूरी-पूरी मदद की जाएगी। इसके साथ साथ जिन-जिन महानुभावों ने घपले की बात की है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इतनी घपले की बात नहीं है। हमारा महकमा पूरी कोर्पोरेशन कर रहा है कि पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया

जाए यह महकमा ऐसा है कि कुछ न कुछ कमी रह सकती है क्योंकि इस महकमें का वास्ता बहुत ज्यादा लोगों से पड़ता है। हर तरह के लोग होते हैं। दूसरे महकमों में भी इस तरह की बातें होती हैं। आगे के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम धांधली हो। डिप्टी स्पीकर साहब अगर देखा जाये तो 540 करोड़ की वर्किंग कैपिटल में से 1 करोड़ 90 लाख की धांधली हो तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग यह नहीं देखते कि हम कितने भले का काम करते हैं, गरीब आदमी के लिए और आम आदमी के लिए, हरिजन के लिए, पूरी-पूरी सुविधा प्रदान करते हैं। कई भाईयों ने सहकारी भूगर मिलों का भी जिक्र किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने सारे देण्डे से ज्यादा गन्ने का भाव किसान को दिया है जिसके कारण हमें 5 करोड़ 88 लाख रुपये का नुकसान हुआ है हमने फैसला किया था कि गन्ने का भाव ज्यादा से ज्यादा किसानों को दें इसीलिए 12.50 रुपये क्विंटल के हिसाब से गन्ने का भाव दिया गया है। इस घाटे को पूरा करने के लिए हमने सरकार से चार करोड़ रुपया मांगा है। प्राइवेट मिलों को भी नुकसान हुआ होगा। सरकार ने किसानों को गन्ने के लिए दो करोड़ रुपये की सबसिडी दे दी है जो कि अभी रिलीज हो चुकी है। इस महीने की भी जल्दी ही सबसिडी रिलीज कर दी जायेगी। हम जानते हैं कि किसान बड़ी मुश्किल से गन्ना पैदा करता है परन्तु फिर भी उसको पूरी कीमत नहीं मिल पाती है।

चौधरी देस राज: यह जो सबसिडी दी जा रही है क्या सभी गन्ना पैदा करने वालों को दी जायेगी?

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आप जानते हैं कि मिलों में जितना भी गन्ना आयेगा उतने सारे गन्ने पर सबसिडी दी जायेगी। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह सबसिडी किस तारीख तक देनी है। इसके साथ साथ जहां तक वसूली का ताल्लुक है हरियाणा प्रांत दे 1 में पहला प्रांत है जहां बैंकों की वसूली 98 प्रति 100 है जोकि दे 1 में सबसे आगे है। इसी वजह से हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसके लिए इनाम के तौर पर हमें ट्राफी दी है, आवार्ड दिया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मेरे कुछ साथियों ने खाद के बारे में जिक्र किया। खाद का कम होने का जहां तक ताल्लुक है इसका कारण यह है कि खाद बाहर से आता है लेकिन फिर भी हम जब वेयर हाउसिंग कार्पोरे 100 के खाद लेते हैं तो उसका वजन करके लेते हैं। इसके लिए हमने किसानों को कह रखा है कि आप हैफ्ट की मारफत खाद को वजन करके लें। हमने हैफ्ट को पूरी हिदायतें दी हुई हैं और सरकुलर भेजा हुआ है कि किसी भी किसान को एक तोला खाद कम नहीं मिलना चाहिए। तो किसान का फर्ज बनता है कि वह खाद का वजन करके ले और किसान को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अगर कट्टा फटा हुआ है तो नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ साथियों ने यह भी कहा कि पुरानी खाद है उसमें डले बंध जाते हैं और वह खाद किसानों को दे देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि खाद इतनी पुरानी नहीं होती है। हो सकता है कि कुछ जगहों पर एक सीजन में थोड़ी बहुत खाद बच जाती हो तो वह अगले सीजन तक चलती है। जो खाद बच जाती है उसको हम टैस्ट

करवाते है अगर टैस्ट करवाने के बाद थोड़ी सी भी उसकी ताकत कम हो जाए तो उसका भाव भी कम करते है और किसानों को बताते है कि भाई इसमें अगर आपको सौ फीसदी ताकत चाहिए तो इसमें सौ फीसदी ताकत नहीं है इसमें तो 80 फीसदी है। अगर वह उस खाद को लेता है तो उससे उतना ही भाव कम लेते है लेकिन कोई गड़बड़ की बात नहीं है कि किसान को जान बूझ कर गुमराह किया जाता है। मैं अपने साथियों से यह निवेदन करता हूँ कि वह लोगों को बताएं कि खाद का वजन करके लें। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कुछ साथियों ने कहा कि सोनीपत और गोहाना में खाद में गड़बड़ हुई और घपला हुआ है।

चौधरी ई वर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि खाद वजन करके लेनी चाहिए और फटा हुआ कट्टा नहीं लेना चाहिए तो मेरा यह कहना है कि किसानों को खाद जबरदस्ती थोपा जाता है। चाहे वह खाद कैसी भी है।

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, खाद जबरदस्ती नहीं दिया जाता और किसान तो खाद उतनी ही लेता है जितनी उसको जरूरत हो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और न ही थोपने की बात है। किसान खाद को वजन करके ले और देख करके ले। खाद इतना ज्यादा तो है भी नहीं कि जबरदस्ती दिया जाए। अब वह पहले वाली बात नहीं रही है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ साथियों ने कहा कि सोनीपत और गोहाना में खाद का घपला हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर गड़बड़ हुई। हमने वहां के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को सस्पेंड किया और उसके खिलाफ केस दर्ज

करवाया। इसी तरह से गोहाना में हमने डिप्टी मैनेजर को सस्पेंड किया और उसके खिलाफ भी केस दर्ज करवाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि अगर इससे संबंधित कोई भी अधिकारी या कर्मचारी होगा उसके विरुद्ध भी सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। इसके बाद अगर कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसको भी सरकार माफ नहीं करेगी। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बोलने का समय दिया।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नं० 15 पर माननीय अपोजी उन के सदस्यों ने और दूसरे सदस्यों ने कटमो उन दी है और अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा कि आपको पता है कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सिंचाई पर, फ्लड कंट्रोल पर, ड्रेजिंग वगैरह पर काफी अभियान चलाया है। सन् 1971-72 से लेकर 1975-76 तक इरीगे उन पर कुल 18 करोड़ रुपए खर्च होते रहे हैं और 1978-79 में इस पर 78.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए जोकि पिछली रकम से साढ़े चार गुणा ज्यादा बैठती है। डिप्टी स्पीकर साहब, 1977-78 में हरियाणा प्रांत में बहुत ज्यादा फ्लड आए इसलिए सरकार ने फ्लड के काम को प्राथमिकता देनी चाही और प्रायरिटी बेसजि पर फ्लड को रोकने के लिए हमने 138 करोड़ रुपए की मासटर प्लान बनाई थी। पिछले साल की आपत्ति को देखते हुए हमने उस पैसे को भी 173 करोड़ रुपए बढ़ाया है ताकि आने वाले वर्ष में हरियाणा की भूमि को फ्लड की मार से बिल्कुल छुटकारा दिलाया जाए। इस प्राथमिकता को देखते हुए ही हमने एक उजीना

ड्रेन बनाई जोकि एक बहुत बड़ी ड्रेन है। डिप्टी स्पीकर साहब, वह आपके ही जिले में है। उसको चार महीने के अंद महकमा नहर ने बड़ी मेहनत के साथ हमारे इंजिनियर्स ने दिन रात एक करके तैयार की है। यह ड्रेन तैयार करके मेवात के लाखों एकड़ एरिया को पानी से छुटकारा दिलाया और आज उस एरिया में खेती बाड़ी हुई है। इसी प्रकार से हमने रोहतक और झज्जर एरिया में बुपनियां और छुड़ानी ड्रेंज बनाई। वह ड्रेंज बनने के बाद हजारों एकड़ एरिया को पानी से छुटकारा हुआ और वहां पर भी आज किसान की खेती लहरा रही है। झज्जर और छुड़ानी का एरिया उस पानी से तबाह हो जाता था उसके चारों तरफ रिंग बांध बंध करके तैयार हो चुके है। करनाल जिले में एक असंध कस्बा है वह भी पानी से तबाह हो जाता था उसके चारों तरफ भी रिंग बांध बंध कर तैयार हो चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले हरियाणा के सैंकड़ों गांव पानी से तबाह हो जाते थे और पंजाब के लिए चारा तक नहीं मिलता था। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे मुख्य मंत्री जी, विधायक और इंजीनियर्स ने बड़ी मेहनत से गांवों के चारों तरफ रिंग बांध बांधने का अभियान चलाया और वह बांध बंध कर तैयार हो चुका है। पिछले साल उन गांवों को फ्लड के पानी से राहत मिली। डिप्टी स्पीकर साहब, कल राव साहब, फ्लड का जिक्र करते हुए बड़े हल्के अंदाज से बात कर रहे थे, टीका टिप्पणी कर रहे थे और आहें भर रहे थे कि यह तो सरकार की नियत पर है इसलिए फ्लड आते है। बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने यह बात कही। मैं राव साहब की इज्जत करता हूँ। वह मुख्य मंत्री भी रह चुके है और अपोजी पक्ष के लीडर भी है। इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारे मुख्य मंत्री जी ने

अपोजी इन के भाईयों को आमंत्रित किया था और खुद हमारे मुख्य मंत्री जी, सारे मंत्रीगण और सदस्यगण ने जनता के साथ मिल करके गांवों बांध बांधे। हमारे मुख्य मंत्री जी ने बीमारी की हालतम में होते हुए भी गांवों में टोकरियां उठाई लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि चौधरी भाम शेर सिंह और राव साहब एयरकंडी शंड कोठियों में बैठे आराम कर रहे थे। कल परसों से यह मगरमच्छ के आसूं बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों के लिए यह करदिया वह कर दिया लेकिन उसमुसीबत के समय यह किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी मुसीबत में हिस्सेदार नहीं बन सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, इनको लोगों के हमदर्द बनने का कोई हक नहीं। यह तो इन्होंने सिर्फ ढोंग चाया है इसलिए मैं इनसे गुजारि । करूंगा कि आज भी हरियाणा में फ्लड रोकने का काम पूरे जोर से चला हुआ है, ये उसमे रोड़े न अटकाएं और ऐसे हालात पैदा न करें कि गांवों में पार्टीबाजी हो बल्कि लोगों को समझा बुझा कर ड्रेंज लिकलवाएं और बांध बंधवाएं। मैं इनको यह एक किस्म से न्यौता देता हूं कि वह हमारे साथ आएँ अभी तीन चार महीने बरसात के बाकी रहते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक लिफ्ट इरीगे इन स्कीमज का ताल्लुक है जवाहर लाल नेहरू स्कीम सिवानी स्कीम लोहारू स्कीम कम्पलीट हो चुकी है और जवाहर लाल कैनाल को 1980 तक कम्पलीट कर दिया जाएगा। इस नहर से जहां पिछले दिनों में 65 हजार एकड़ रकबे की आबपा मी होती मी वहां 1 लाख 55 हजार रकबे की आबपा मी की जाएगी। सबसे बड़ी बात सदन को मैं यह बताना चाहता हूं कि पहली बार, पिछली रबी की फसल के लिए इस नहर से पानी दिया गया रबी के दौरान लगातार नहर में पानी चलता

रहा। जवाहरलाल नेहरू कैनल का विधिवत उद्घाटन दो तीन महीने के बाद करने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि या तो प्रधान मंत्री जी या चौधरी चरण सिंह जी के हाथों इसका उद्घाटन करवायेंगे। मैं सदन को इस बारे में सूचित करना चाहता था।

डिप्टी स्पीकर साहब, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट बड़े जोर-शोर से चल रहा है, धड़ाधड़ नहरें पक्की हो रही हैं माइनर्ज पक्के किए जा रहे हैं खाले पक्की की जा रही हैं ताकि जितना पानी जमींदार के लिय पहुंचाना आवश्यक हो उसमें हम कामयाब हो सकें और किसान की खेती की सिंचाई कर सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, हमने स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। 70 स्प्रिंकलर सैट्स पिछले साल लगाये गये और 50 सैट्स इस साल लगाने जा रहे हैं। वह रकबा जो ऊंचा-नीचा है, जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हो सकते, वहां पानी देने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक बात और खास तौर पर कहना चाहता हूं जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है नहर में पानी ठहरा नहीं चलता ही रहा। इस बात को मेरे भाई जो दाईं तरफ बैठे हैं, इन्होंने इन्कार नहीं किया। सरकार का यह फर्ज भी है और विवास दिलाता हूं कि हरियाणा के किसान को अधिक से अधिक पानी देने का प्रयत्न किया जाएगा, हर तरीके की कोशिश की जाएगी कि कहीं किसान की कोई फसल पानी के अभाव के कारण मर न जाए और अगर फ्लड आ जाए तो जहां एक तरफ नहरों में पानी चलेगा वहां दूसरी तरफ फ्लड के प्रकोप से फसलों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इस तरफ हरियाणा सरकार तीव्र इकदमात उठाने जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: आप खत्म कर रहे हैं या और ज्यादा बोलना चाह रहे हैं?

श्री बीरेंद्र सिंह: मैंने भुरु में कहा था कि मेरे पास ऐसा महकमा है जिसका अरबों रूपए का बजट है। एस0 वाई0 एल0 पर भी बोलना है, मेरे इ लू बड़े डेलिकेट है।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, आप बोलिएं।

श्री बीरेंद्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि इरीगे ान डिपार्टमेंट इस साल कुछ और इकदमात उठाने जा रहा है जिससे किसान को भारी राहत मिलने वाली है। सबसे पहले हमने हुकम दिया है कि ऐफि एंसी डायग्राम हर डिस्ट्रिब्यूटरी पर लगाया जाए जिससे इरीगे ान की डिवैल्पमेंट और वाटर सप्लाई की रैगुलेरिटी का पता लगेगा। हर माइन, हर डिस्ट्रिब्यूटरी पर, जहां से पानी चलता है, वहां पर ऐफि एंसी डायग्राम तैयार करने का हुकम दिया है और 15 जून से 30 जून तक जब, मैं मौके पर जाऊंगा तो ऐफि एंसी डायग्राम चैक किए जाएंगे। लोगों की रोज-बरोज की मुसीबत रहती है, लोग ि ाकायत करते हैं कि टेल पर पानी नहीं पहुंचता मोघा ऊंचा-नीचा है, ये डायग्राम लागू करने से इन सारी समस्याओं को दूर करने का इरादा है। इसके अतिरिक्त हरियाणा प्रांत में जितनी डिस्ट्रिब्यूटरीज है, जितने माइनर्ज है, उनकी दोबारा रिपेयर की जाए, बैंकस सुधारे जाएं, सफाई की जाए, इसके लिये आदे ा दिए जा चुके हैं और मैं बजाते खुद 15 जून से 30 जून तक हर डिस्ट्रिब्यूटरी और माईनर का पर्सनली मुआयना करूंगा ताकि डिपार्टमेंट जो सफाई का काम करेगा, उसकी तसल्ली कर सकूं इसके

इलावा डिप्टी स्पीकर साहब, 1 मई से 30 मई तक "क्लयरेंस का महीना" मनाया जाएगा। क्लयरेंस-मंथ प्रोग्राम में कहा गया है कि ट्रांसफर आफ एरियज के केसिज खालों की लाइनगि के केसिज चकबंदी से ताल्लुक रखने वाले केसिज जो काफी देर से चल रहे हैं, इन सब केसिज को, इस क्लियरेंस-मंथ के अंदर यानि 30 मई तक निपटारा किया जाएगा ताकि सालों-साल से जो मुकदमें चल रहे थे उनका खात्मा किया जा सके। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने फैसला किया है कि कैनाल सिस्टम में जो वायर-सिस्टम था वह बहुत पुरान सिस्टम हो चुका है, इसको बदलना है। हमें पानी के एक एक कतरे की जरूरत है। कई दफा फ्लड की मार इतनी जबरदस्त होती है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है और हमारे यहां फ्लड कंट्रोल सिस्टम न होने के कारण फ्लड की मार हो जाती है....

.....

श्री उपाध्यक्ष: क्या आप दस मिनट और लेंगे।

श्री बीरेंद्र सिंह: जी हां।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Deputy Speaker: Is it the sense of the House that the time of the House be extended by another fifteen minutes?

(Voices: Yes)

Mr. Deputy Speaker: The sitting is extended by 15 minutes i.e. till 1.45 p.m.

वर्ष 1979-80 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरागम)

श्री बीरेंद्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि हम कैनाल वायर सिस्टम की जगह वायरलैस सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिस से रैगुले इन आफ वाटर सप्लाई में लोगों को राहत मिलेगी, फ्लड कंट्रोल की वार्निंग मिलेगी, लोगों को पहले पता लगा जायेगा कि यह कयामत आने वाली है।

डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे बड़ा सवाल एस0 वाई0 एल0 के पानी का है। चौधरी भाम डेर सिंह सुरजेवाला ने इसके बारे में एक प्राइवेट मैम्बरज रैजोल्यू इन मूव किया, कई सवाल पूछे गए, हर सै इन में एस0वाई0एल0 का जिक्र चलता रहा है। ठीक है, इसका जिक्र होना भी चाहिए क्योंकि इस चैनल से हरियाणा के करोड़ों लोगों का इंटरैस्ट बाबस्ता है। बहुत जरूरी चैनल है, इसके बारे में लोगों को चिंता लगी हुई है और यह चिंता का विशय भी है मेरे दोस्त चौधरी भाम डेर सिंह सुरजेवाला ने, (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान पदासीन हुए) राव साहब ने और कई दूसरे अपोजि इन के साथियों ने कहा कि यह पानी पिछली सरकार, यानि इंदिरा गांधी से लिया था। यह बात गलत है। इंदिरा गांधी ने नहीं दिया था, हिंद सरकार ने यह पानी हरियाणा को दिया था। वे इस बात का फख्र महसूस न करें। हमारा हमक 4.8 मिलियन एकड़ फीट बनता था लेकिन पिछली सरकार ने 3.5 एम0ए0एफ0 पानी हमारे पल्ले

बांध दिया और ये बड़े फख से कहते हैं कि इन्होंने पानी लिया। कब लिया? चेयरमैन साहब, 1966 में हरियाणा बना। दो साल के बाद 1968 में केस भुरू किया और पूरे आठ साल के बाद इनको एस.वाई.एल. का पानी मिला। आज ये फख से बड़े मरोड़ में आकर कहते हैं कि इन्होंने पानी लिया और जो मिला वह भी 1.30 एम0ए0एफ0 कम। पूरा पानी नहीं लिया। इतना भारी नुकसान करके आये हैं और आज उछल उछल कर इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन जनता क्रेडिट देने वाली नहीं है। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई। हमने हर तरह की कोशिश की कि पंजाब के पोर्न में चैनल खुदवाई जाए, इस काम को कम्प्लीट करवाया जाए, हमने नोटिफिकेशन की लेकिन पांच-चार दिन पहले अखबार में छपा कि पंजाब सरकार ने हमें सिविल सूट का नोटिस दिया है। आज मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि दफा 80 के नोटिस की नकल हमने ले ली है इसके मुताबिक पंजाब 24मार्च 1976 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहता है, ऐसा इस नोटिस से प्रतीत होता है। दफा 80 का नोटिस हिंद सरकार को भी दिया और दो-तीन राज्य सरकारों को भी दिया और मैं सदन को विवास दिलाना चाहता हूँ कि जो नोटिस पंजाब सरकार ने दिया, इसका करारा जवाब दिया जाएगा। मैं इस सदन को यह भी विवास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार बहुत जल्दी बड़े मुनासिब इकदमात इस बारे में उठाने जा रही है और सतलुज जमुना कैरियन चैनल हम खुदवा कर रहेंगे। (गंसा)

चेयरमैन साहब, कुद सदस्यगण ने दो चार और बातों का जिक्र किया। कुछ ने कहा कि ऐग्जैक्टिव इंजीनियर का ग्रेड 1947 में इतना था और अब तक केवल दो परसेंट बढ़ा है। इसके बारे में मेरा कहना यह है कि हरियाणा सरकार ने ऐ-पे-कमी इन बना दिया है और हर भाई को यह हक है कि वह अपना अपना केस उसके सामने पे कर सकता है। अगर किसी के साथ ज्यादाती हुई होगी तो यह पे-कमी इन उसको दूर करेगा। कुछ भाइयों ने कहा कि टैक्नीकल डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं इनके ए0सी0आर0 डी0सी0 या एस0डी0एम0 लिखता है। इसके बारे में सरकार ने काफी गौर किया है लेकिन यही सोचा गया कि यही सिस्टम चलना चाहिए क्योंकि यह ठीक है। ऐडमिनिस्ट्रे इन को ठीक ढंग से चलाने के लिए यह सिस्टम ठीक है। चौधरी जगन नाथ फरमा रहे थे कि हरियाणा के कुछ जिलों में पानी ज्यादा है और कुछ में कम है। उनका मतलब क्या था पूरी तरह में समझ नहीं पाया। इस समय वे हैं नहीं वरना उनसे पूछ ही लेते। वाटर अलाउंस रोहतक और सोनीपत जिले का चौधरी बंसी लाल घटा कर गए थे। मैंने तो इसके बारे में एक नोट लिखा है कि इसक ऐग्जामिन किया जाए। वकई ही अगर ज्यादाती हुई तो यह वाटर अलाउंस पूरा किया जाएगा। इसके अलावा भायद उनका यह मं हो कि उस इलाके में भिवानी और लोहारू वगैरा में अब तक उतना पानी नहीं पहुंचना चाहिए था या नहर पैरीनियल नहीं बनी जबकि बाकी जिलों में पैरीनियल कैनाल्ज है। यह सिस्टम

सारा एस0वाई0एल0 से जुड़ा हुआ है। जब भी वह पानी हमें मिलेगा वह इस सिस्टम को फीड करेगा।

एक बात कैप्टन मांगे राम जी ने कही कि रिंग बांध बनाये जाने चाहिए। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सुबाना गांव का बांध बन जाएगा।

गौंवी और मैट्रोल ड्रेन के बारे में स्वामी आदित्यवे I जी ने कहा। ये कहां रहते हैं और किस चक्कर में रहते हैं मुझे पता नहीं। जब भी मैं इनके यहां जाता हूँ तो ये मुझे मिलते ही नहीं।

स्वामी आदित्यवे I: चेयरमैन साहब, माननीय मंत्री महोदय स्टेज पर रहते हैं और मैं जनता के बीच में रहता हूँ। (विघ्न)

श्री बीरेंद्र सिंह: चेयरमैन साहब, मंत्री बनने के बाद मैं सबसे ज्यादा गुड़गांव जिले में गया हूँ। इनके इलाके का बनचारी नामक गांव है। सबसे पहले मैं वहां गया था। लोगों ने एतराज किया कि हमारे हल्के के एम0एल0ए0 पता नहीं कहां रहते हैं और वे उन्हें बोलने नहीं देंगे बहुत मुश्किल से मैंने लोगों को मनाया।

स्वामी आदित्यवे I: चेयरमैन साहब, मैं इस प्रकार की बात नहीं कहना चाहता कि किसने किसको बुलाया लेकिन इतना

जरूर कहना चाहता हूँ कि ये छुपकर जाना चाहते थे परन्तु लोगों ने मुझे सूचना दी कि स्वामी जी आप भी आएँ। (विघ्न)

श्री बीरेंद्र सिंह: चौधरी राजेंद्र सिंह और सरदार खाँ आदि सारे एम0एल0एज0 वहाँ थे। आखिर में ये भी आ गये। लेकिन मैं उस बात का ज्यादा जिक्र न करते हुए इन्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैट्रोल ड्रेन के लिए पैसा मंजूर किया गया है और वह काम जरूर होगा परन्तु स्वामी जी जरा सब्र रखिए। स्पीकर साहब भी आपको यही कहा करते हैं कि आप जरा धैर्य रखा करें। यदि आपको कोई शिकायत हो तो कृपया ढंग से बताया करें ताकि उसे रफा दफा किया जा सके। मैं सन्यासियों की बड़ी इज्जत करता हूँ और आपकी भी करता हूँ लेकिन धैर्य के साथ सारे काम होंगे। अंत में चेयरमैन साहब मैं यही कहूँगा कि जहाँ इरीगे टन डिपार्टमेंट का ताल्लुक है वह इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हरियाणा के किसान की अधिक से अधिक सेवा की जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।

विकास मंत्री(ठाकुर बीर सिंह): चेयरमैन साहब, मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मेरे लायक दोस्त चौधरी भामदेव सिंह ने कुछ आपतियाँ उठाईं जिनकी क्लैरिफिकेशन देना यहाँ जरूरी है ताकि सदस्यगण सारे हालात से वाकिफ हों और इनकी तसल्ली हो क्योंकि पंचायती राज से तकरीबन सारे देहात का ताल्लुक है। मैं अपने लायक दोस्त को यह बताना चाहता हूँ कि सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी इस पंचायती राज सिस्टम

के लिए बहुत अच्छी तरह से गौर किया जा रहा है और हम बड़ी तेजी से काम करना चाहते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने अगले लोक मेहता नामक एक कमेटी बनाई उन सारी चीजों को जायजा लेने के लिए हमें कि कौन सा पंचायती राज का सिस्टम स्वीकार करना चाहिए क्योंकि पिछला जो सिस्टम हमारे सामने था वह ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। एक कमेटी हमारे यहां भी बनी हुई है जिसमें मेरे दोस्त भी मੈम्बर हैं। उसकी मीटिंग मैं जल्दी ही बुला रहा हूँ और हमारी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा सिस्टम हम अपनी स्टेट को दें। इसमें सारे सदस्यगण भी और मेरे लायक दोस्त भी मुझे सहयोग दें ताकि हम एक ऐसा सिस्टम अपनी स्टेट को दें जो इफैक्टिव हो, स्टेट में अच्छी तरह से काम कर पाए और पंचायती राज की जो आशाएं हमारे भाई हमारे से रखते हैं वे पूरी हो।

चेयरमैन साहब मेरे लायक दोस्त ने एक सवाल यह उठाया कि पंचायत के इलैक्शन तो हो गये लेकिन पंचायत समिति और जिला परिशद के इलैक्शन नहीं हुए। चेयरमैन साहब, पंचायत के इलैक्शन हमने नोर्मज को देखते हुए जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश की लेकिन पंचायत समिति और जिला परिशद के बारे में डिजिजन चूंकि अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है इसलिये इनके चुनाव नहीं हुए। चेयरमैन साहब हमारी जो कमेटी बनी है वह अगर इस निर्णय पर पहुंचती है कि जिला परिशद या पंचायत समिति में से कोई भी कमेटी इफैक्टिव नहीं है तो इलैक्शन बेमायने हो जाते हैं। यह कमेटी अपनी

रिपोर्ट तैयार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद इलैक्ट्रान जल्दी से जल्दी करवा दिए जाएंगे।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री सभापति: आप कितना टाइम लेंगे? भायद बाकी मिनिस्टर साहेबान भी बोलना चाहेंगे।

ठाकुर बीर सिंह: मैं तो दो तीन मिनट ही लूंगा।

स्वास्थ्य मंत्री(श्रीमती डा० कमला वर्मा): मैं भी थोड़ा सा टाइम लूंगी।

श्री सभापति: तो क्या हाउस की यह सैंस है कि इसका समय दो बजे तक बढ़ा दिया जाए?

आवाजें: जी हां।

श्री सभापति: हाउस का समय दो बजे तक बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1979-80 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

ठाकुर बीर सिंह: चेयरमैन साहब, अभी दो तीन दिन पहले इस कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें काफी निर्णय ले लिये गये हैं। इसकी रिपोर्ट कम्प्लीट होने के बाद ही इलैक्ट्रान जल्दी

से जल्दी करवा दिये जाएंगे यह आ वासन मैं हाउस में देना चाहता हूँ।

चेयरमैन साहब, एक प्वांयट यह रेज किया गया कि इस डिपार्टमेंट के अधिकारीगण के कोई सर्विस रूल्ज नहीं है और न ही सीनियोरिटी लिस्ट तैयार की गई है। यह बात दुरुस्त है लेकिन आपको मालूम है कि 31 साल तक हमारे कांग्रेसी भाई हकूमत कर गए। उस 31 साल के अर्से में यह सर्विस रूल्ज और सीनियोरिटी लिस्ट तैयार नहीं कर पाए लेकिन हमारा बड़ा क्वांटिटीसिज्म करते हैं। मुझे इस महकमे का चार्ज लिए केवल एक महीना हुआ है। मैंने सीनियोरिटी लिस्ट तैयार करवा दी है और उसे ऑफिसरज के पास औबजैक् इंज के लिए भेज दिया है। उसका टाईम भी खत्म हो गया है और वह काम कम्प्लीट हो गया है। रूल्ज बना दिये गये हैं, एल0आर0 को भेज दिये गये हैं, उसके बाद कैबिनेट कंसीडर करेगी। वहां पास होने के बाद लागू कर दिये जायेंगे। सीनियोरिटी लिस्ट और रूल्ज बनाये बिना न किसी की प्रोमोशन हो सकती थी और न ही कुछ और कोई काम हो सकता था। इसी कारण से इन जगहों को भरा नहीं जा सका और उनके राइट नहीं मिल सके। मैंने जब इस विभाग का चार्ज लिया था तभी ये आर्डर कर दिये थे कि वहां पर रूल्ज बनाये जाने चाहिए और सीनियोरिटी लिस्ट बनाई जानी चाहिए। भामदेव सिंह जी ने यहां डिप्टी डायरेक्टर का जिक्र किया, केवल डिप्टी डायरेक्टर श्री गुप्ता की प्रोमोशन का ही सवाल नहीं है

और भी लोग है जिनके हक नहीं मिले है। उनके हक 31 साल से रूके हुए थे। जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी एल0आर0 से आने के बाद रख दिये जायेंगे। जिनका हक है उनको अब य दिलाया जायेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि सरपंचों और पंचों को पोलिटिकल बेसिज पर सस्पेंड कर दिया जाता है। यह बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारी यह बदकिस्मती कहें या कुछ कहें अभी तक गांवों के लोगों ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं अपनाया है। गांवों में इलैकान होने के बाद भी ग्रुपइजम का सिस्टम बना रहता है। मैं तो कई दफा मीटिंगों में भीकहा करता हूं कि जब तक इस डिपार्टमेंट को री-आर्गेनाइज नहीं किया जायेगा तब तक लोगों का भला नहीं हो सकता। मैं तो यह कहा करता हूं कि यह कसाई वाला काम है क्योंकि कभी किसी सरपंच के खिलाफ कभी पंच के खिलाफ एकान लेना पड़ता है। एकान न लें तो भी काम नहीं चलता है। मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का उद्देश्य नहीं है कि किसी के खिलाफ पोलिटिकल बेसिज पर एकान लिया जाये। अगर कोई पंच या सरपंच करणान के केस में इन्वाल्वड है तो उसके खिलाफ हम इन्कवायरी करने में मजबूर होते हैं। हमने जो कमेटी बना रखी है वह सारी बातों के बारे में जांच कर रही है ताकि पंचायती राज को इफैक्टिव ढंग से लागू किया जा सके। हम पंचों और सरपंचों को पावर दिलाना चाहते

हैं। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही हम इन सारी चीजों को लागू करकेंगे लेकिन अब जो हमने तरीक इख्तियार कर रखे हैं उसमें कोई पोलिटिकल बेस पर किसी के खिलाफ ऐव इन नहीं लेते हैं। अगर कोईस हाइएस्ट लैवल पर हजारों और लाखों रूपए की करण इन करता है उनके खिलाफ इन्कवायरी करवाते हैं और उसी का सस्पेंड करते हैं। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर रहा था कि हमारे देहाती भाई आपस में ऐडजस्ट नहीं कर पाते हैं ज्यों ही इलैव इन खत्म होता है दूसरी पार्टी वाले उसके खिलाफ इल्जाम लगा कर आ जाते हैं। इस कारण से ही वहां पर काम ठीक नहीं चल पा रहा है।

एक चीज और उनके ध्यान लाना चाहता हूं कि यह डिपार्टमेंट इसी कारण से ठीक काम कर रहा था कि यहां पर न तो कोई सीनियोरिटी लिस्ट बनी हुई थी ओर न ही कोई सर्विस रूलज बने हुए थे। चंडीगढ़ में जो डिवैल्पमेंट डिपार्टमेंट है उसको नीचे के काम की पूरी तरह से जानकारी नहीं होती थी। डिस्ट्रिक्ट लैवल पर अपनी मनमानी से काम कर रहे थे। हमारी पिछली सरकार ने जिला परिशदों और पंचायत समितियों का और जिला परिशदों का फंड दिया गया था जिसको इस्तेमाल करने के लिए उनके पास मनमाने अख्तियार आ गये इसलिए उन्होंने उस पैसे को मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने कुर्सी पर बैठते ही उनकी इस मनमानी पावर

पर चैक लगाई और उसको इस्तेमाल करने के लिए एक कमेटी बनाई।

श्री सभापति: आप से रिकवैस्ट करूंगा कि आप जल्दी से समाप्त करें।

ठाकुर बीर सिंह: मैं अभी खत्म कर रहा हूँ। इसलिए अब सारा सिस्टम ठीक चल रहा है। पंचायती राज को री-आर्गेनाइज कर रहे हैं और जो भी स्टैप्स लेने जरूरी है वे ले रहे हैं। अगर किसी को कोई िाकायत हो तो हमारे नोटिस में लायें। ये हमारी मीटिंग में तो आते नहीं। मीटिंग में आते तो उनको भी जानकारी होती। इसलिए चौधरी भामोर सिंह जी की बातें निराधार हैं। इन भाब्डों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ।

स्वास्थ्य मंत्री(श्रीमती डा० कमला वर्मा): चेयरमैन साहब मैं सदस्यों की भावनाओं का आदर करती हूँ कि उन्होंने मांग नम्बर दस पर अपने विचार रखे। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकती कि जनता सरकार ने आने के पचास बीस मास में काफी सुविधाएं प्रदान की हैं और बहुत ज्यादा काम किया। हम यह मानते हैं कि हम इतना काम नहीं कर पाये हैं कि जितना होना चाहिए था कि गांव गांव में डिस्पेंसरी या हस्पताल बना सकें। लगभग डेढ़ साल के अंदर जो कुछ भी हमने किया है उसके विशय में मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ। अभी श्री बीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि फ्लड आया, उस फ्लड को काबू पाने के

लिए ड्रेनें बनाई गई और दूसरे भी साधन अपनाये गये माननीय सदस्यों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे विभाग के डाक्टरों ने बाढग्रस्त क्षेत्रों में जा कर लोगों की चिकित्सा की। लोगों को मलेरिया और पेट के रोगों से बचाया। हमारे विभाग के डाक्टर ने गांव-गांव में जा कर जनता की पूरी चिकित्सा सेवा की। चेयरमैन साहब, पहली सरकार के टाईम पर भी बाढ आती थी लेकिन उन्होंने कभी भी कोई दवाई नहीं पहुंचाई हमने लोगों को मलेरिया से बचाने के लिए 6798 औशधी वितरण केंद्र खोले हुए है। हम वहां की पंचायत या मास्टर्स को मलेरिया के लिये गोलियां भी देते है ताकि वे गांवों में वितरण कर सकें और मलेरिया के प्रकोप से लोग बच सकें।

इसी प्रकार से हमने 146 मलेरिया क्लीनिक खोले जहां पर कर्मचारी खून-जांच की सलाईड बनाने में सेवाग्रस्त हैं। पहले हमारे पास स्टाफ की कमी होने के कारण लाखों स्लाईड को पानी में धो देते थे लेकिन अब हमने स्वास्थ्य विभाग के 255 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी ताकि खून की सही तरह से जांच हो सके। इसी तरह से मेरे साथी ग्रामीण जनता की भलाई के लिए बड़े इच्छुक है लेकिन मैं उनको यह बताना चाहती हूं कि सन् 1977-78 के अंदर छः रूरल डिस्पेंसरी खोली जिसमें से केवल एक डिस्पेंसरी िवाजी कालोनी रोहतक में खोली है बाकी सारी डिस्पेंसरियां गांवों में खोली है। हमने पांच स्थानों पर सबसीडियरी स्वास्थ्य केंद्र खोले है वे पांचों पांचों गांवों के अंदर

खोले है। आठ सबसीडियरी सेंटर हमें 31 मार्च तक खोलने जा रहे हैं। फाइल गई हुई है। वे सैक इन हो कर आ जायेंगे तब खोल दिये जायेंगे। हमने वर्ष 1978-79 में 50 उप-स्वास्थ्य केंद्र बढ़ाये हैं। इनकी संख्या पहले 784 होती थी लेकिन अब 834 हो गई है। 206 सब-सेंटर और भी सैक इंज हो चुके हैं। मैं सै इन में व्यस्त होने के कारण नहीं जा सकी लेकिन ये भी 31 मार्च तक खोले दिये जायेंगे जिनमें एक मेल और फीमेल मल्टीपरपज वरकर होंगे जो दोनों क्योरेटिव एंड वेंटिव चिकित्सा कर सकेंगे। इसी प्रकार से हमने रूलर हिस्पैंसरी चुटाला बवानी खेड़ा और ताउडू को अपग्रेड कर दिया है। चुटाला को अपग्रेड करके तीस बिस्तर का अस्पताल बना दिया। बवानी खेड़ा को 25 बिस्तरीय और ताउडू को दस बिस्तरीय अस्पताल बना दिया गया।

चेयरमैन साहब, सोनीपत के अस्पताल को जो पहले पचास बिस्तरों का था अब उसे सौ बिस्तरों का कर दिया है। जैसे ही जमीन एक्वायर हो जाएगी हम उसकी बिल्डिंग बनानी शुरू कर देंगे। जिला सिरसा, भिवानी तथा गुड़गांव के फरीदाबाद अस्पताल में पीड्रियाट्रिक क्लीनिक खोलने की स्वीकृति दे दी गई है। जिला सिरसा के बारे में मेरे एक साथी ने कहा है मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सिरसा में भवन निर्माण का काम विचाराधीन है और आने वाले साल के अंदर हम इसको जरूर शुरू करवा देंगे। सोनीपत, सिरसा और अम्बाला इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स में होस्पिटल बनाने के लिए भवन निर्माण की बात विचाराधीन है।

सभापति महोदय, पहले कुछ ही जगहों पर टी०बी० अस्पताल हुआ करते थे लेकिन हमने जिला सोनीपत तथा सिरसा में टी०बी० कंट्रोल कार्यक्रम के अधीन ला दिया है। इसके अतिरिक्त चेयरमैन साहब, मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि आंखों के रोगों के निवारण के लिए हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, जींद और सिरसा में आंखों की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हिसा मंडल में एक चलता फिरता अस्पताल आंखों का हस्पताल खोला गया है जो गांवों के अंदर गांव के लोगों की आंखों की चिकित्सा की सुविधा प्रदान करेगा। चेयरमैन साहब, यह मैं मानती हूँ कि गांवों में मैटरनिटी अस्पताल न होने के कारण हमारी बहनों को काफी तकलीफ होती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर मिडवाइफरी केयर देने तथा परिवार कल्याण सेवाओं को अपनाने के लिये रित करने के उद्देश्य से जनता भासन के दौरान परम्परागत दाई शिक्षण योजना चलाई गई है जिसके अंतर्गत गांव में पहले से कार्य कर रही अशिक्षित दाईयों को एक माह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ताकि वह पहले से अच्छा कार्य कर सकें। राज्य में अब तक कुल 2535 दाईयां शिक्षित की जा चुकी है।

मल्टीपरपज स्कीम के अंतर्गत अम्बाला व महेंद्रगढ़ जिलों में यह योजना पहले ही चलाई जा रही थी। वर्ष 1977-78 में यह योजना रोहतक, गुड़गांव व हिसार जिलों में विस्तृत की गई 1979-80 में इसे सोनीपत, सिरसा व करनाल के

तीन जिलों में भी लागू कर दिया जाएगा। इस तरह से ग्यारह जिलों में से आठ जिलों में यह स्कीम इस साल पूरी हो जाएगी और अगले साल तीन जिले और पूरे हो जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत एक महिला और एक पुरुष कार्यकर्ता पांच हजार की आबादी को विन्टिव तथा क्योरेटिव चिकित्सा सुविधा दान करेंगे। विचारधीन समय के दौरान 1844 कार्यकर्ताओं को इस योजना के अधीन शिक्षित किया गया तथा ग्यारह सौ कार्यकर्ता इस समय शिक्षण ले रहे हैं।

यहां पर दवाओं के कम होने की बात कहीं गई है। चेयरमैन साहब, दवाएं कम हैं क्योंकि हमें बजट का दो तिहाई मिलता है। दो तिहाई से दवाएं पूरी करना कठिन है। चालू वर्ष में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां अधिक जुटाने के लिए 21 लाख रुपए की धन राशि भीषण ही दी जाने वाली हैं जबकि पहले ही बीस लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जा चुकी है। इससे दवाइयों की कुछ कमी पूरी हुई है।

चेयरमैन साहब, चेचक की भूयुक्त दर को कायम रखने के लिए बड़ी निगरानी व सतर्कता रखी गई है और इस दौरान चेचक का कोई भी रोगी राज्य में नहीं पाया गया।

सभापति महोदय, इस वर्ष हमने 35 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज गांवों में खोली हैं। जहां तक स्टाफ का संबंध है पहले हर डिस्पेंसरी खाली थी। जनता सरकार आने के बाद हमने

स्टाफ की कमी को दूर करने का प्रयत्न किया और लोक सेवा आयोग इत्यादि के माध्यम से निम्नलिखित स्टाफ रेगुलर/एडहाक भर्ती किया गया:-

डाक्टरज	एच0सी0एम0एस 0-1	75 (20सीधी भर्ती द्वारा और 55 पदोन्नति द्वारा)
	एच0सी0एम0एस 0-2	260
1	डेन्टल सर्जन	16
2	ए0एन0एम0	131
3	स्टाफ नर्स	157
4	लेबोरेट्री असिस्टेंटस	22
5	फार्मेसिस्ट	49
6	रेडियोग्राफर	16

इसके अतिरिक्त सिविल अस्पताल, यमुना नगर व रिवाड़ी में नई योजना के अंतर्गत अतिरिक्त अमला लगाया गया है।

लगभग सारे तहसील व जिलों के अस्पतालों में विशेषज्ञों की सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है।

ग्रामीणों को अपने स्वास्थ्य की स्वयं रक्षा करने के उद्देश्य से राज्य में जन स्वास्थ्य योजना को अम्बाला व महेंद्रगढ़ जिलों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में तथा भोश 9 जिलों के चुने खंडों में जन स्वास्थ्य योजना लागू की गई। इस योजना का उद्घाटन हरियाणा में प्रधान मंत्री महोदय द्वारा 2 अक्टूबर 1977 को ताउड़ू जिला गुड़गांव में किया गया। इस योजना के अंतर्गत एक जन स्वास्थ्य रक्षक के तीन माह के प्रशिक्षण ग्रहण करने के उपरांत अपने ही चुने हुए गांव में एक हजार की आबादी को साधारण चिकित्सा सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षा देना आरम्भ कर दिया है। राज्य में अब तक 2259 जन स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षित किये जा चुके हैं और इस समय 241 जन स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

सभी जिला स्तर के अस्पतालों में पोस्ट मार्टम कार्यक्रम विस्तृत किया जा चुका है और चालू वर्ष में सुदृढ़ किया जा रहा है। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से परिवार कल्याण सेवाओं को नया मोड़ दिया है। नियोजित परिवार की आवकता तथा

महत्व को समझाने के लिए शिक्षात्मक अभियान चलाया गया है। खंड स्तर पर ओपिनियन लीडर्ज के 194 प्र शिक्षण वि विर लगाये गये है ताकि लोगों की गलतफहमियों को दूर करने में साधक हो सकें। इसी प्रकार 24 स्वास्थ्य वि विर का आयोजन भी किया गया जिसके अंतर्गत परिवार कल्याण के अतिरिक्त मूल स्वास्थ्य की देख रेख स्वास्थ्य शिक्षा व प्रतिरक्षण कार्यक्रम पर बल दिया गया।

ब्रिटि एड स्कीम के अंतर्गत नलबंदी सुविधाओं को दस उपमंडलीय अस्पतालों में विस्तृत किया गया तथा इस योजना के अधीन प्रत्येक अस्पताल में छः बिस्तरों वाला वार्ड तथा लेबर रूम को अतिरिक्त सामान देकर आप्रे ान थियेटर में बदला गया है। इसके अतिरिक्त यह सुविधा 25 प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में भी उपलब्ध है गत वर्ष जनवरी, 1978 तक केवल 5976 आप्रे ान किये गये जबकि इस वर्ष 11,613 आप्रे ान किये जा चुके है। इसी प्रकार पिछले वर्ष केवल 15122 लूप लागये गये थे जबकि इस वर्ष 21847 लूप लगाये गये । एन0एच0 5 फरीदाबाद में डिसपैंसरी के अपने भवन निर्माण का कार्य भुरु हो गया है जिसका खर्चा लगभग 10.51 लाख रुपए होगा। सैक्टर 17 फरीदाबाद के डिसपैंसरी तथा स्टाफ क्वार्टज का निर्माण कार्य भुरु हो चुका है। इसके खर्चे का अनुमान 13.11 लाख रुपए है। इ0एस0आई0 अस्पताल फरीदाबाद में अमले के माकन बनाये जा रहे है और इस निर्माण कार्य का खर्चा लगभग 18.28 लाख रुपए होगा। सैक्टर 7 फरीदाबाद के डिसपैंसरी के अमले के लिए भी

मकान बनाये जा रहे हैं, जिस पर 5.61 लाख रुपए व्यय होंगे।
इ0एस0आई0 डिस्पेंसरी पिंजौर के निर्माण कार्य के लिए
एच0एम0टी0 के कैम्पस में एक एकड़ अतिरिक्त भूमि देने का
निर्णय लिया है। गुड़गांव में इ0एस0आई0 डिस्पेंसरी के निर्माण
के लिये भूमि की खरीद की गई है।

इ0एस0आई0 अस्पताल फरीदाबाद में एक अतिरिक्त
एम्बुलेंस ली गई है और इ0एस0आई0 अस्पताल, जगाधरी की
नाकार एम्बुलेंस को बदल दिया गया है। मार्च, 1978 में
इस0एस0आई0 डिस्पेंसरी हिसार में 12 बिस्तरों का एक डिपेंडें
नार्ड चालू कर दिया गया है तथा ऐसा ही एक नार्ड इ0एस0आई0
डिस्पेंसरी सोनीपत में दिनांक 24-1-1979 को चालू कर दिया
गया है।

फरीदाबाद-बल्लभगढ़ कम्पलैक्स में कर्मचारी बीमा
निगम से अतिरिक्त डिस्पेंसरीयां खोलने की वित्तीय अनुमति प्राप्त
की गई है और इन्हें भीघ्र ही खोलने की कार्यवाही की जा रही
है।

Mr. Chairman: Now the demands and the cut
motions will be put to the vote of the House.

There is no cut motion to demand No. 10

Question is-

That a sum not exceeding Rs. 33,19,21,550 be
granted to the Governor to defray the charges that will come in

the course of apyment for the year 1979-80 in respect of the charges under Demand No.10-Medical and Public Health.

The motion was carried.

Mr. Chairman: There is a cut motion to demand No. 15 by Sarvshri Surinder Singh and Shamsheer Singh Surjewala. I will put it to the vote of the House.

Question is-

That Demand No. 154 of Rs. 1,23,37,45,015/- on account of Irrigation be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Chairman: Now I will put the demand to the vote of the House.

Question is-

That a sum not exceediang Rs. 1,23,37,45,015 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of apyment for the year 1979-80 in respect of the charges under Demand No.15-Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Chairman: There is also a cut motion to demand No. 17 by Sarvshri Shamsheer Singh Surejewala and Surinder Singh. I will now put it to the vote of the House.

Question is-

That Demand No. 17 of Rs. 30,66,14,960/- on account of Agriculture be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Chairman: Now I will put the demand to the vote of the House.

Question is-

That a sum not exceediang Rs. 30,66,14,960 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of apyment for the year 1979-80 in respect of the charges under Demand No.17-Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Chairman: There is no cut motion to Demand No. 18. I will, therefore, put the demand to the vote of the House.

Question is-

That a sum not exceediang Rs. 6,95,86,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of apyment for the year 1979-80 in respect of the charges under Demand No.18-Animal Husbandry.

The motion was carried.

Mr. Chairman: Now, I will put demand No. 21 to the vote of the House.

Question is-

That a sum not exceediang Rs. 6,82,43,965 be granted to the Governor to defray the charges that will come in

the course of apyment for the year 1979-80 in respect of the charges under Demand No.21-Community Development.

The motion was carried.

Mr. Chairman: There is a cut motion to demand No. 22 by Sarvshri Surinder Singh and Shamsheer Singh Surjewala. I will now put it to the vote of the House.

Question is-

That Demand No. 22 of Rs. 8,15,24,990/- on account of Cooperation be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Chairman: Now I will put the demand to the vote of the House.

Question is-

That a sum not exceediang Rs. 8,15,24,990 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of apyment for the year 1979-80 in respect of the charges under Demand No.22-Cooperation.

The motion was carried.

Mr. Chairman: The House stands adjourned till 2 p.m. on Monday the 26th March, 1979.

(*13.55 hours)

(The Sabha then *adjourned till 2 p.m. on Monday, the 26th Mach, 1979).

